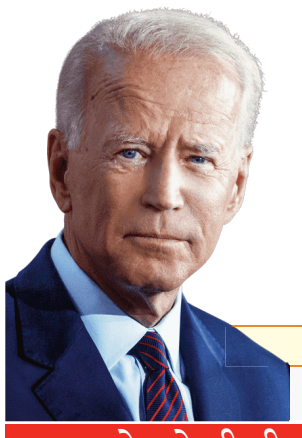

इंडिया पब्लिक खबर

वर्ष: 7 ▪ अंक : 07 ▪ पृष्ठ : 12 ▪ 15 फरवरी से 21 फरवरी तक ▪ दिन: सोमवार ▪ मूल्य: 3 रुपये

www.indiapublickhabar.in

लखनऊ से प्रकाशित व प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर से प्रसारित

साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र

बाइडेन ने की चीन पर पेंटागन टास्क फोर्स बनाने की घोषणा

बजट में गरीबों, बेरोजगारों की अनदेखी: चिदंबरम

खास खबरें

रास्ते पर आया चीन, पैंगोंग झील से हटने लगी सेना

आईपीके, लखनऊः भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीने से चल रहा विवाद अब समाप्ति की ओर अग्रसर लग रहा है। दोनों देश पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण से सैनिकों को हटाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी को राज्यसभा में दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ निरंतर वार्ता से पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट से सेना हटाने पर सहमति बनी है। समझौते के बाद, भारत-चीन चरणबद्ध...

शेष पेज 08 पर

सरकार लेगी 12 लाख करोड़ का कर्ज, आप पर होगा ये असर

आईपीके, लखनऊः कोरोना वायरस ने पूरे देश की हालत बिगाड़ दी है। हर क्षेत्र में इस महामारी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में देश के खजाने की हालत भी काफी दयनीय हो गई है। अब इस हालत को दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार भारी रकम कर्ज में लेने जा रही है। इस बार के बजट में सरकार ने यह ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार करीब 12 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। आपको बता दें कि मौजूदा साल यानी 2020-21 में भी सरकार ने करीब इतना ही...

शेष पेज 09 पर

अंकिता रैनाः नई टेनिस सनसनी

आईपीके, लखनऊः इस समय टेनिस जगत में जो नाम चर्चा का विषय बना हुआ है वो है भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना का। अंकिता ने काफी कम समय में बड़ी पहचान बना ली है। अब अंकिता ने एक और इतिहास रचा है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला युगल के ड्रॉ में जगह बना ली है। इस तरह अंकिता किसी ग्रैंडस्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली 5वीं भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बन गयी हैं। 28 वर्षीय अंकिता ने रोमानिया की मिहेला बुजारनेकु के साथ जोड़ी बनायी है और उन्हें महिला युगल में सीधा प्रवेश मिला है। अंकिता से पहले निरुपमा मांकड़ (1971), निरुपमा वैद्यनाथन...

शेष पेज 10 पर

खबरों से अपडेट रहने के लिए स्कैन करें।

जन्म विशेष

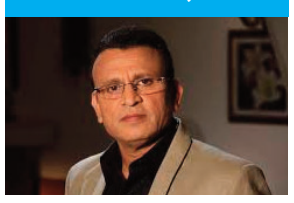

सशक्त अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड अभिनेता अन्नू कपूर का जन्म 20 फरवरी 1956 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने फिल्म मंडी से अपने करियर की शुरूआत की थी और अब तक सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्हें कई बार फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिल चुके हैं।

अंदर पढ़ें

युवा उड़ान

भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा अर्जुन, सेना को मिलेगी मजबूती

पीएम मोदी ने सेना को सौंपा पहला टैंक, केमिकल अटैक से बचाएंगे खास सेंसर

नई दिल्लीः वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहे भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 'अर्जुन टैंक' मील का पत्थर साबित होगा। यह न सिर्फ दुश्मन देशों के छक्के छुड़ाएगा, बल्कि भारत की अनूठी रक्षा तकनीक से भी दुनिया को रूबरू कराएगा। कारण कि इस स्वदेशी युद्ध टैंक का डिजाइन, विकास और निर्माण सीवी-आरडीई, डीआरडीओ ने 15 अकादमिक संस्थानों, 8 प्रयोगशालाओं और कई एमएसएमई के साथ मिलकर किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार 14 फरवरी को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को डीआरडीओ अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी की मौजूदगी में स्वदेशी रूप से विकसित पहला अर्जुन मार्क-1ए मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) सौंपा। अब इसके बाद 6,600 करोड़ रुपये के अर्जुन एमबीटी के अंतिम बैच के उत्पादन के लिए औपचारिक रूप से आदेश देने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही रक्षा उपकरण, डिजाइन, विकास और विनिर्माण में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल ने एक और प्रमुख मील का पत्थर हासिल किया है। अर्जुन टैंक को डीआरडीओ के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (सीवीआरडीई) ने डिजाइन किया है। टैंक का निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) के हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाडी द्वारा किया जाएगा। सरकार से अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 30 महीनों के भीतर पांच एमबीटी का पहला बैच सेना को सौंप दिया जाएगा। अर्जुन युद्धक टैंक पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है, जिसे पहली बार 2004 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। मौजूदा समय में सेना के पास 124 अर्जुन टैंक की दो रेजिमेंट हैं, जिन्हें जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जब नवम्बर में सैनिकों के साथ दीपावली मनाने पाकिस्तान से लगी जैसलमेर (राजस्थान) के लोंगेवाला सीमा पर गए थे तो उन्होंने जिस अर्जुन टैंक की सवारी की थी, उसी का यह उन्नत संस्करण एमके-1ए है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण समिति (डीएसी) ने 2014 में 118 अर्जुन एमके-1ए टैंकों के लिए 6,600 करोड़ रुपये के ऑर्डर को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक ऑर्डर नहीं दिया गया है। यह परियोजना 2015 से इसलिए अधर में थी, क्योंकि सेना ने रूसी टी-90 टैंकों के ऑर्डर देने पर ध्यान केंद्रित किया था।

फाइल फोटोः अर्जुन टैंक

इन जगहों पर की जाएगी तैनाती

चेन्नई में रविवार को 124 अर्जुन टैंकों के पहले के बैच के बेड़े में 118 टैंकों को शामिल किया गया, जो पहले ही सेना में शामिल हो चुके हैं और उन्हें पाकिस्तान के मोर्चे पर पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात किया गया है। बता दें कि यह अर्जुन टैंक पहले के 124 टैंकों की भांति सेना के बख्तरबंद कोर में दो रेजिमेंट बनाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में इनके कोर होने से सेना को काफी मजबूती मिलेगी और पाकिस्तान भी इनके निशाने से दूर नही होगा।

पाकिस्तान के लिए काल है यह टैंक

भारत जिस तरह से अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूती दे रहा है और स्वदेशी हथियारों से सेना को सुसज्जित कर रहा है, उससे दुश्मन देशों के हौसले पस्त हो गए हैं। पुलवामा के बाद भारत के एयर स्ट्राइक से थर्राए पाकिस्तान के लिए यह अर्जुन टैंक किसी काल से कम नही है, क्योंकि यह पलक झपकते ही दुश्मनों को मिट्टी में मिला देगा।

कीमत लगभग 8,400 करोड़ रुपए

अर्जुन टैंक की कीमत लगभग 8,400 करोड़ रुपये हैं। ये टैंक भारत को दुश्मनों पर बड़ी बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बता दें कि पिछले दिनों ही एक उच्चस्तरीय बैठक में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में 118 अर्जुन मार्क 1ए टैंक को शामिल करने की मंजूरी दी थी, जिसकी कीमत लगभग 8,400 करोड़ रुपए है।

अर्जुन टैंक की ये है खासियत

डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने अर्जुन मेन बैटल टैंक (एमके-1ए) में नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया हुआ हैं और फायर क्षमता में भी बढ़ोतरी की गई है। यह टैंक बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को ढूढ़ लेता है और युद्ध के मैदान में दुश्मनों द्वारा बिछाई गई माइंस हटाकर आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम भी है। यही नही केमिकल अटैक से बचने के लिए भी इसमें खास तरह के सेंसर लगाए गए हैं।

अर्जुन सीरीज का है आखिरी बैच

सेना में पहले से ही अर्जुन टैंक प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ऐसे में 118 अर्जुन मार्क-1ए टैंक इस सीरीज का आखिरी बैच होंगे। बता दें कि सेना अर्जुन टैंक के करीब 68 टन वजन को समस्या मानती है, क्योंकि लद्दाख व अरूणांचल जैसे दुर्गम इलाकों में इनकी तैनाती नही हो सकती है। यहां पर सेना 20-25 टन वजनी टैंकों की ही आवश्यकता पहले जता चुकी है।

लोकतंत्र को कमजोर कर रही भाजपाः अखिलेश

अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान

लखनऊः स्वतंत्रता आंदोलनों से लोकतंत्र को ताकत मिली है, लेकिन भाजपा सरकार इसे लगातार कमजोर करने के प्रयास में लगी हुई है। साजिश के तहत लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रासंगिकता को समाप्त किया जा रहा है।

यह कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा कि आज देश में कृषि क्षेत्र की दुर्दशा हो गई है और किसानों के साथ छल किया गया है। न तो उनकी आय दोगुनी हुई और न ही उन्हें फसल की लागत का ड्योढ़ा दाम मिला। आज किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में केंद्र सरकार की 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का उल्लेख क्यों नहीं है ? प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ ? अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे एकजुटता के साथ वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के पक्ष में 90 प्रतिशत मतदान कराने का संकल्प लें। इसके लिए अभी से बूथ स्तर तक पूरी तैयारी करें। भाजपा की साजिशों के प्रति सावधान रहें और जनता के बीच जाकर समाजवादी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें। बता दें कि सपा ने राजधानी लखनऊ के साथ-साथ प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी महिलाओं की सुरक्षा, मान सम्मान, बेरोजगारी, शैक्षिक क्षेत्र की समस्याओं एवं अन्य मुद्दों को लेकर समाजवादी महिला घेरा कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने घेरा बनाकर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले बजट पर भी सवाल खड़े करते हुए अखिलेश ने कहा था कि इस तरह के बजट से अर्थव्यवस्था नीचे गिरी है। नोटबंदी से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। लोगों का कारोबार चौपट हो गया, लोगों की नौकरी चली गई और छोटे कारोबारियों को जीएसटी ने निराश किया था। कोविड-19 आया, न जाने कितने कारोबार को बर्बाद कर दिया। खेती के अलावा सबको नुकसान हुआ। ऐसे परेशानी के दिन किसी ने नहीं देखे होंगे। इन सभी कारणों की वजह से अर्थव्यवस्था नीचे गई है। भाजपा चाहती, तो लोग उबर जाते। इस बजट से लगता है कि जो सरकार की चीजें है, उनको भी बेच रहे हैं। अगर चीजें बिक जाएगी, तो सरकार क्या करेगी। इस बजट ने जनता को निराश किया है।

दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन के विस्तार के लिए 8 बोलीदाता

नई दिल्लीः दिल्ली मेट्रो ने मैजेंटा लाइन के लिए भूमिगत (यूजी) और इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल (ईएंडएम) काम के लिए 8 बोलीदाताओं (बिडर्स) को अंतिम रूप दिया है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की तरफ से टेंडर निकालने के बाद, आठ कंपनियों ने 38.23-किलोमीटर मैजेंटा लाइन के तहत नए 2.03-किमी भूमिगत विस्तार के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम के लिए निविदाएं (बोलियां) प्रस्तुत की हैं। वर्तमान में, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) और वेन्सर कंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड (वीसी-सीएल) का एक संयुक्त उद्यम विकासपुरी पार्क शाफ्ट-कृष्णा पार्क स्टेशन -विकासपुरी रैंप सेक्शन के बीच नए 2.03 किलोमीटर के भूमिगत विस्तार (डीसी-06) का निर्माण कर रहा है।

किसानों की किस्मत संवारेगा गोबर से बना 'पेंट'

हर गांव में फैक्ट्री लगाने की चल रही तैयारी

नई दिल्लीः देश के हर गांव में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री खुलवाने की तैयारी में एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जुटे हुए हैं। इसके लिए उनका सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय खास प्लान तैयार करने में जुटा है। गोबर से पेंट बनाने के लिए एक फैक्ट्री खोलने में 15 लाख रुपये का खर्च आ रहा है। मंत्रालय का मानना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सपना साकार हुआ तो हर गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से शहरों की तरफ पलायन की समस्या खत्म होगी।

गडकरी के मुताबिक, गोबर से बना अनोखा पेंट लांच होने के बाद डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। अभी जयपुर में ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इतने आवेदन आए कि सबकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। साढ़े तीन सौ लोग वेटिंग लिस्ट मे हैं। पांच से सात दिनों की ट्रेनिंग होती है। ऐसे में हम ट्रेनिंग सुविधा बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग लेकर गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री का संचालन करें। हर गांव में एक फैक्ट्री खुलने से ज्यादा रोजगार पैदा होगा। दरअसल, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने बीते 12 जनवरी, 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से तैयार गोबर से बना प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया था। यह पेंट इको-फ्रेंडली है। पहला ऐसा पेंट है, जो विष-रहित होने के साथ फफूंद-रोधी, जीवाणु-रोधी गुणों वाला है। गाय के गोबर से बने और भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित, यह पेंट गंधहीन है। यह पेंट दो रूपों में उपलब्ध है- डिस्टेंपर तथा प्लास्टिक इम्यूलेशन पेंट के रूप में मार्केट में आया है। एमएसएमई मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल मार्च 2020 से गोबर से पेंट बनाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को प्रेरित किया था। आखिरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की जयपुर में स्थित यूनिट कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने इस तरह के अनोखे पेंट को तैयार करने में सफलता हासिल की। इस पेंट में सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम जैसे भारी धातुओं का असर नहीं है। इसको लेकर किसानों में भी खासा उत्साह है।

किसानों की बढ़ेगी कमाई

पेंट की बिक्री बढ़ने के बाद गांवों में गोबर की खरीद भी बढ़ेगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, सिर्फ एक मवेशी के गोबर से किसान हर साल 30 हजार रुपये कमाएंगे। अभी तक किसान गोबर का सिर्फ खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांव-गांव पेंट की फैक्ट्रियां खुलने के बाद गोबर की खरीद का भी एक तंत्र बन जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। मोदी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की कोशिशों में जुटी है। ऐसे में गोबर के माध्यम से भी किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में गडकरी के मंत्रालय ने यह प्रयास किया है।

आदर्श बनेगी भोपाल की रशीदिया शाला

भोपालः मध्य प्रदेश की माध्यमिक शालाओं को सर्वसुविधायुक्त बनाने की मुहिम शुरु हो रही है। राज्य के एक हजार विद्यालयों की तस्वीर बदली जानी है और उसकी शुरुआत होगी राजधानी के रशीदिया माध्यमिक शाला से। इस विद्यालय को मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा।

प्रदेश में भी दुनिया के कई मुल्कों की तरह अब कक्षा 1-8 तक के बच्चों के लिए सर्वसुविधायुक्त सर्वोत्तम स्कूल उपलब्ध होंगे। राज्य में एक हजार विद्यालयों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाना है। राज्य का मॉडल विद्यालय रशीदिया माध्यमिक शाला को बनाया जाना है। भोपाल के संभागायुक्त कवींद्र कियावत ने निर्देश दिए कि स्कूल को 31 मार्च तक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाये। इस कार्य को भोपाल विकास प्राधिकरण, नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी के संयुक्त प्रयासों से आदर्श विद्यालय के अनुरूप अधोसंरचना का विकास कर मॉडल बनाया जाएगा। इसमें अधोसंरचना, स्मार्ट क्लास रूम आईटी सेटअप सहित, आर्ट एवं क्राफ्ट रूम, संगीत कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष इंटरनेट सहित, खेल कक्ष, सिक-रेस्ट रूम, आगंतुक एवं प्रतीक्षा स्थल, कैंटीन, शौचालय बालक-बालिका एवं स्टाफ के लिए अलग शौचालय रहेंगे।

ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने में निभाएगी अहम भूमिका

अब आपका पेट्रोल भी बचाएगा हेलमेट

- स्मार्ट हेलमेट डिवाइस में लगे हैं 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर
- पुलिस, एम्बुलेंस और परिवार को खुद भेज देगा लोकेशन

वाराणसीः हेलमेट का अभी तक केवल एक फायदा था सड़क दुर्घटना से बचाना, लेकिन इस नए तरह के हेलमेट से कई काम हो सकेंगे। एक तो दुर्घटना से सुरक्षा करेगा ही साथ ही पेट्रोल बचाएगा और अनहोनी होने पर एम्बुलेंस व पुलिस को सूचित भी करेगा। निजी कॉलेज के बीटेक के छात्रों के बनाये इस हेलमेट से ट्रैफिक कन्ट्रोल भी होगा।

अशोका इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वाराणसी के छात्र आशीष त्रिपाठी, विपिन और सुलेख ने मिलकर स्मार्ट ट्रैफिक हेलमेट ईज़ाद किया है। जो ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती लाल होने पर गाड़ी को बंद कर देगा। हरी होने पर अपने आप गाड़ी स्टार्ट कर देगा। यह ट्रैफिक सिग्नल के 50 मीटर के दायरे पर आते ही काम करना शुरू कर देता है। इसमें लगे ट्रांसमीटरों से दुर्घटना होने पर बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं। छात्र विपिन ने बताया कि हमारा पूरा सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर पर काम करता है। इस स्मार्ट हेलमेट डिवाइस में 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगा है। रिसीवर हमारी बाइक में लगाया जाएगा। 1 ट्रांसमीटर हमारे हेलमेट में लगा है, जो पहनने पर एक्टिवेट हो जाएगा। गाड़ी में लगा रिसीवर ऑन होता और हेलमेट के पहनने पर हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है। दूसरा ट्रांसमीटर चौराहे के सिग्नल सिस्टम के पास लगा होगा, रेड सिग्नल में लगे ट्रांसमीटर के संपर्क में जैसे ही हमारी गाड़ी आएगी, वैसे इसमें लगे रिसिवर को रेड सिग्नल ट्रांसमीटर ऑफ यानी बंद कर देता है। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा, वैसे आटोमैटिक बाइक को शुरू कर देगा।

रेड सिग्नल ट्रांसमीटर की रेंज अभी 50 मीटर है, जिसे और बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना होने पर भी यह हेलमेट आपकी रक्षा करेगा। सेंसर के जारिए दुर्घटना स्थल की लोकेशन को पुलिस, एम्बुलेंस और परिवार को भेजने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि सिग्नल पर बाइक बंद होने से करोड़ों लीटर पेट्रोल की बचत कर वातावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। एक मिनट में करीब 20 एमएल तेल जल जाता है, तो एक मिनट के लिए एक करोड़ गाड़ी बंद हो जाएं तो लाखों लीटर पेट्रोल बचा सकते हैं। यह बहुत बड़ी बचत होगी। क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र गोरखपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी महादेव पांडेय ने बताया यह अत्यंत महत्वपूर्ण इनोवशन है। इससे पेट्रोल तो बचेगा ही साथ में आकस्मिक दुर्घटना पर भी रोक लगेगी।

"यह ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। महादेव पांडेय, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

अंदर पढ़ें

युवा उड़ान

कोरोना टेस्टिंग की अनोखी किट बना रहा आईआईटी दिल्ली

नई दिल्लीः आईआईटी दिल्ली जल्द ही कोरोना टेस्टिंग के लिए एक अनोखी किट विकसित करने जा रहा है। इस किट की खास बात यह है कि इससे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की जांच बेहद कम समय में की जा सकती है। कोरोना जांच करने वाली इस किट की विश्वसनीयता आरटी पीसीआर टेस्ट जैसी ही होगी, लेकिन आरटीपीसीआर के मुकाबले यह बहुत कम समय में जांच रिपोर्ट देने में सक्षम होगी।

आईआईटी दिल्ली में विकसित की जा रही यह कोरोना जांच किट विश्वसनीय नतीजे देने के साथ-साथ कम लागत पर उपलब्ध होगी। इस किट के माध्यम से एंटीजन टेस्ट किट की तरह ही तेज गति से कोरोना की जांच संभव होगी हालांकि, एंटीजेंट किट के मुकाबले इसके नतीजे ज्यादा सटीक और विश्वसनीय होंगे। आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी. रामगोपाल राव ने कहा कि हम कोरोना की तुरंत जांच करने वाली एक नई प्रकार की किट विकसित कर रहे हैं।

- आरटीपीसीआर के मुकाबले कम समय में देगी रिपोर्ट
- एंटीजेंट किट के मुकाबले ज्यादा होगी विश्वसनीयता

यह एक बेहद आधुनिक त्वरित किट होगी, लेकिन इसकी विश्वसनीयता बाजार में मौजूद एंटीजेंट किट के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। बड़ी बात यह भी है कि इसकी कीमत बेहद कम है। यह अगले कुछ दिनों में उपलब्ध हो सकेगी। वी. रामगोपाल राव ने कहा कि दुनिया की सबसे किफायती आरटी पीसीआर किट हमने 399 रुपये में तैयार की है। इससे पहले देश में विभिन्न स्थानों पर कोरोना का आरटी पीसीआर टेस्ट 4500 रुपये में किया जा रहा था। इसके निर्माण से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।

लागू हुई स्क्रैप पॉलिसी तो घटेगा 95 हजार वाहनों का बोझ

बढ़ते प्रदूषण पर भी लगेगी लगाम, प्रदेश के 30 लाख वाहन स्क्रैप पॉलिसी में होंगे शामिल

आईपीके, लखनऊः देश में वाहन कबाड़ नीति लागू हुई तो राजधानी के करीब 95 हजार निजी व कॉमर्शियल वाहन इसकी जद में आएंगे। जबकि पूरे प्रदेश की बात की जाए तो यह आंकड़ा करीब 30 लाख निजी व कॉमर्शियल वाहनों का है।

आंकड़ों के अनुसार, लखनऊ आरटीओ में 25 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। हालांकि, कोरोना काल की वजह से लखनऊ आरटीओ में नए वाहनों के पंजीकरण की गति कुछ धीमी हुई है, बावजूद इसके राजधानी की सड़कों पर रोजाना वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही वाहनों के ईंधन के जरिए होने वाले प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में वाहन कबाड़ नीति को काफी कारगर माना जा रहा है। हालांकि, जानकारों का यह भी मानना है कि वाहन कबाड़ नीति की सफलता इसके नियम-कानून पर निर्भर करेगी। उल्लेखनीय है कि बीते 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत अब 20 साल पुराने निजी वाहन और 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को सड़कों पर दौड़ने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। वहीं जानकारों का यह भी मानना है कि वाहन कबाड़ नीति लागू होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई ताकत मिलेगी।

फाइल फोटो

सड़क से कम होगा वाहनों का बोझ

वाहन कबाड़ नीति लागू होने से सड़क पर बेतहाशा बढ़ रहे वाहनों का बोझ कुछ कम होगा। वर्ष 2021-22 में राजधानी के करीब 95 हजार निजी व व्यावसायिक वाहन इसमें शामिल हैं। आगामी वर्षों में हर साल एक लाख व उससे अधिक वाहन स्क्रैप पॉलिसी की जद में आएंगे। इससे हर साल सड़कों से वाहनों का दबाव कम होगा व प्रदूषण घटेगा।

वन नेशन, वन पॉलिसी जरूरी

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के टेक्निकल कमेटी मेंबर हरजिंदर सिंह ने बताया कि वाहन के लिए वन नेशन, वन पॉलिसी बेहद जरूरी है। देश में वाहनों के स्क्रैप का काम बहुत बड़ा है, मगर इस काम में बड़ी संख्या में निजी लोगों की भागीदारी है। सरकार पॉलिसी में किस तरह के नियम-कानून शामिल करती है, यह देखना होगा।

गुजरात की तर्ज पर लागू हो थ्रीपी मॉडल

ऑटो-रिक्शा थ्री व्हीलर महासंघ के अध्यक्ष पंकज दीक्षित ने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी के जरिए सड़कों से पुराने वाहनों को हटाया जाना सरकार का स्वागत योग्य कदम है। व्यावसायिक वाहनों में शामिल ऑटो की उम्र 15 साल होती है। उसके बाद वह चलने की स्थिति में नहीं होते। उनके अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना सरकार का मकसद है। ऐसे में सरकार को सार्वजनिक परिवहन की दिशा में बेहतर कदम उठाने चाहिए। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के संचालन के लिए गुजरात की तर्ज पर थ्रीपी मॉडल लागू किया जाना चाहिए। इस मॉडल के तहत रात में वाहनों को खड़ा करने के लिए बड़ी-बड़ी पार्किंग, सीएनजी पंप, मेंटीनेंस के लिए वर्कशॉप एक ही जगह पर होते हैं। इस मॉडल से काफी लाभ होगा।

फिटनेस के नाम पर होगी उगाही

वाहन कबाड़ नीति के तहत 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निजी वाहन और 15 साल की उम्र पूरी कर चुके व्यावसायिक वाहनों को फिटनेस की प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिटनेस सही पाए जाने पर ही यह वाहन सड़कों पर चल सकेंगे। ऐसे में जानकारों का यह भी कहना है कि इससे वाहन स्वामियों से फिटनेस के नाम पर उगाही भी बढ़ेगी। सुविधा शुल्क की आड़ में अनफिट वाहनों को भी सड़कों पर चलने के लिए फिट घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में न तो पुराने वाहन कम होंगे और न ही प्रदूषण में कमी आएगी। वहीं वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए ऑटोमेटेड सेंटर बनाए जाएंगे। ऐसे में ऑटोमेटेड सेंटर सरकार की निगरानी में होंगे अथवा निजी हाथों में, इस पर भी संशय बरकरार है।

बजट 2021: लखनऊ मंडल में नई लाइनों, डबलिंग कार्यों पर जोर

- कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी मिला बजट
- आलमबाग कारखाने के आधुनिकीकरण के साथ लगेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
- एनईआर के नौतनवां में बनेगा रेलवे का पहला कन्टेनर टर्मिनल

आईपीके, लखनऊः बीते एक फरवरी को पेश किए गए आम बजट में रेलवे के पूर्वोत्तर व उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की योजनाओं को बजट आवंटित किया गया है। इस क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे का रोजा-बुढ़वल-सीतापुर रूट जल्द डबल होने के साथ-साथ इसके इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी जल्द पूरा होगा। इसके साथ ही बहराइच-श्रावस्ती के बीच नई लाइन बिछेगी, जिससे पूर्वोत्तर रेलवे में यात्री ट्रेनें रफ्तार भरेंगी। वहीं गोरखपुर-नकहा जंगल के बीच गुड्स शेड भी जल्द तैयार हो जाएगा, जिससे मालगाडियों को निकालने में आसानी होगी।

रेलवे नेपाल में पहली बार ऑटोमोबाइल को भेजने के साथ नौतनवां में एनईआर अपना पहला कन्टेनर टर्मिनल बनाएगा। इससे माल लदान में पूर्वोत्तर रेलवे नए आयाम स्थापित करेगा। वहीं उत्तर रेलवे के आलमबाग कारखाने का आधुनिकीकरण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तैयारी, ब्रिज वर्कशॉप के उन्नयन, सभी प्रकार के पहियों की मरम्मत के लिए सुविधाओं का प्रावधान, आधुनिकीकरण और मरम्मत के लिए एलएचबी और आईसीएफ सवारी डिब्बों की मेंटीनेंस समेत अन्य कार्य होंगे। पूर्वोत्तर रेलवे की डीआरएम डॉ. मोनिका अग्निहोत्री ने बताया कि इस बार रेलवे को मंडल के कार्यों के लिए 4.4 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। इससे रेलवे नौतनवां में कन्टेनर टर्मिनल बनाएगा। इससे उत्पादों को नेपाल और घरेलू स्थानों पर भेजने में आसानी होगी।

बहराइच-श्रावस्ती के मध्य बिछेगी नई लाइन

पूर्वोत्तर रेलवे के बहराइच-श्रावस्ती रेलखंड पर बजट में नई लाइन बिछाने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है। रेलवे जल्द ही इस पर सर्वे शुरू करेगा। बहराइच-नानपारा-नेपालगंज के बीच आमान परिवर्तन का काम भी जल्द होगा। करीब 56 किमी के इस सेक्शन पर काम होना है। रोजा-बुढ़वल-सीतापुर पर डबलिंग और डोमिनगढ़-गोरखपुर के बीच तीसरी लाइन को भी मंजूरी मिल गई है।

बुढ़वल-गोंडा तीसरी लाइन के लिए मिले 265 करोड़

डीआरएम ने बताया कि बुढ़वल-गोंडा के बीच तीसरी लाइन बिछाने के लिए 265 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गयी है। हालांकि पूरे मंडल का यह सबसे टेढ़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिस पर रेलवे को खासी मेहनत करनी होगी। वहीं डालीगंज-मल्हौर के बीच डबलिंग और विद्युतीकरण के लिए भी 60 करोड़ रुपए मिले हैं। यह सभी काम 2024 तक पूरे होने हैं। इसके साथ ही ब्रॉडगेज लाइन पर 2023 तक सभी रूट पर विद्युतीकरण काम पूरा होना है।

मालगाड़ियों की रफ्तार हुई दोगुनी

डीआरएम ने बताया कि कोरोना काल में रेलवे ने ट्रैक मेनटेनेंस पर काफी काम किया है। ट्रैक सुधार कर मालगाड़ियों की रफ्तार दोगुनी हो गयी है। 23 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली मालगाड़ियों को मंडल में 50 से 55 की स्पीड पर चलाया गया। मंडल में जहां पहले 77 मालगाड़ियां आती थीं, वहीं अब उनकी संख्या बढकर 102 तक पहुंच गयी है। साथ ही यात्री ट्रेनों की पंचुअलिटी पहुंच गई है।

इन लाइनों के दोहरीकरण के लिए भी मिला बजट

- ✓ आलमनगर-उतरेटिया डबल लाइन 18.09 किमी के लिए 45 करोड़
- ✓ उतरेटिया-रायबरेली के 65.6 किमी के लिए 40 करोड़
- ✓ रायबरेली-अमेठी के 60.1 किमी के लिए 60 करोड़
- ✓ बाराबंकी-अकबरपुर के 161 किमी के लिए 250 करोड़
- ✓ जंघई-प्रतापगढ़-अमेठी के 87 किमी के लिए 175 करोड़
- ✓ बाराबंकी-मल्हौर तीसरी व चौथी लाइन के 32.84 किमी के लिए 80 करोड़

उत्तर रेलवे की नई लाइनों समेत अन्य को मिला बजट

रेल बजट में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की कई सारी योजनाओं के लिए भी बजट का निर्धारण किया गया है। इनमें नई लाइनों के निर्माण के लिए 9454 करोड़ रुपए, रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के लिए 41 करोड़ रुपए, सिग्नलिंग प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 352 करोड़ रुपए, कर्मचारी कल्याण के लिए 56 करोड़ रुपए और यात्री सुविधाओं को अधिक बेहतर करने के लिए 291 करोड़ रूपए का निर्धारण किया गया है।

इन कार्यों के लिए भी मिला बजट

- रेलवे कालोनियों में नलकूपों की व्यवस्था के लिए 45 लाख रुपए
- सेकेंड इंट्री गेट का पुल
- लखनऊ-सुलतानपुर-वाराणसी रूट पर प्लेटफॉर्मों को विकसित करने के लिए 13 करोड़ रुपए
- एस्केलेटर, एटीवीएम, यूटीएस मोबाइल एप से जनरल टिकट
- शताब्दी, राजधानी, दूरंतों ट्रेनों के 50 रैक में वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा
- लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर तीन, चार, पांच, आठ और नौ के वॉशेबुल एप्रेन में बदलाव और सैलून साइडिंग की व्यवस्था
- फैजाबाद में लोको पायलट व गार्ड के लिए नए रनिंग रूम व अन्य सुविधाओं के लिए 90 लाख रुपए
- आलमबाग माल शेड क्षेत्र का विकास
- लखनऊ-कानपुर अतिरिक्त लूप लाइनें
- अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग-समपार फाटकों पर चौकीदार की व्यवस्था
- अधिक दबाव वाले लेवल क्रॉसिंग को इंटरलॉक करने की व्यवस्था
- मेमू ट्रेनों के लिए शेड की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए
- मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कार शेड

एक्सईएन ने रीबोर के नाम पर बहा दिए करोड़ों

- ऑपरेटर व एक्सईएन की मिलीभगत से किसान परेशान
- दो ट्यूबवेल कई बार हो चुके रीबोर, फिर भी नहीं मिल पा रहा पानी

आईपीके, मिर्जापुरः सरकार भले ही किसानों की आय दोगुनी करने व उनको बेहतर से बेहतर कृषि संसाधनों को उपलब्ध कराने का खम ठोंक रही हो, लेकिन अधिकारियों की मनमानी सरकारी मंशा को पलीता लगा रही है। किसानों को सुविधा देने के नाम पर करोड़ों का वारा-न्यारा भी कर दिया जा रहा है, पर उसका लाभ उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है।

सरकार के करोड़ों रूपए पर किस तरह पानी फेरा जा रहा है, उसका सटीक उदाहरण सिंचाई विभाग है। जनपद में सिंचाई विभाग के एक्सईएन ऑपरेटर के दबाव में सरकारी पैसे का जमकर दुरूपयोग कर रहे हैं। किसानों की मानें तो एक्सईएन व ऑपरेटर के मिलीभगत के कारण पहाड़ी ब्लाक के अकसौली गांव में 2 ट्यूबवेल किसानों के खेत की सिंचाई हेतु लगाये गए हैं। जिससे किसानों की सिंचाई तो नहीं हो पाती है, किंतु ऑपरेटर के दबाव में एक्सईएन ने सरकार के लगभग दो करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। यह बर्बादी रीबोर करने के नाम पर की गई। इस दरम्यान दोनों ट्यूबवेल का कई बार रिबोर भी हो चुका है, बावजूद इसके किसान आज अपने खेतों की सिंचाई के लिए दर-दर भटक रहे हैं। मामले के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों से ग्रामीणों ने कई बार मामले की शिकायत भी की, पर जिम्मेदारों ने जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। जांच का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, किसानों को यह नहीं पता है।

ट्यूबवेल के रीबोर होने के बावजूद किसान पानी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ट्यूबवेल ऑपरेटर ने ग्रामसभा अकसौली में दोनों ट्यूबवेल अपने खेत में लगवाया है, जो नाले के पास स्थित है। वहीं बरसात व बाढ़ के कारण जब नाला उफान में आता है तो ट्यूबवेल डूब जाता है। मजबूरन किसानों को निजी पंपिंग सेट आदि का सहारा लेकर खेतों की सिंचाई करनी पड़ती है। पहाड़ी ब्लाक के ग्रामीणों की मानें तो यह कोई पहली बार का वाकया नहीं है। यहां ऑपरेटर व एक्सईएन आए दिन सरकार को चूना लगाने का काम करते रहते हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि मामले के संबंध में यदि कठोर कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम सभी ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। किसानों ने भ्रष्ट ऑपरेटर व एक्सईएन पर कार्रवाई की मांग भी की है।

अपहरण मामले में चौथे आरोपी को भी पुलिस ने दबोचा

आईपीके, झांसीः पुलिस ने गुरूबख्सानी अपहरण मामले के चौथे आरोपी को भी गुरूवार 11 फरवरी को दबोच लिया। इस मामले के तीन आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी।

बता दें कि पिछले दिनों बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले चिकित्सक गुरूबख्सानी का अपहरण कर लिया था। चिकित्सक को छानबीन के बाद बरामद कर लिया था और मुकदमा पंजीकृत कर बदमाशों की तलाश में जुट गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश राजवीर सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद लगातार दबिश के बाद दो अन्य आरोपियों को भी पकड़ने में सफलता हासिल की थी। तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चौथे आरोपी रामलखन गुर्जर ने झांसी पुलिस के भय से मुरैना में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसे झांसी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हैं। दबोचे गए आरोपी रामलखन गुर्जर ने बताया कि टोयोटा गाड़ी (एम पी 06 सी ए 8356) से ही फिरौती के लिये डॉ. गुरूबख्सानी का अपहरण किया था और घुमाते-घुमाते मुरैना के हिंगौना गांव के जंगल में ले गए थे, जहां से डॉक्टर भाग निकले थे। झांसी पुलिस ने मामले के सभी आरोपियों लकारा निवासी राजवीर सिर गुर्जर, वासूदेव विहार निवासी बादाम सिंह, दतिया के उन्नाव बालाजी निवासी पुष्पेन्द्र गुर्जर एवं रामलखन गुर्जर निवासी मुरैना को गिरफ्तार कर लिया है।

पूर्वांचल के लोगों को लुभाएंगे लखनऊ के पशु-पक्षी

आईपीके, लखनऊः राजधानी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान को कई पशु और पक्षियों को छोड़कर जाना ही होगा। भले ही उनको अपने तमाम साथियों की जुदाई महीनों खलती रहे। इनमें बाघ, तेंदुआ, अजगर के अलावा तमाम पक्षी भी हैं। इनके नाम लिखे जा चुके हैं। इनको भेजने की तैयारी भी चल रही है। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खाँ प्राणि उद्यान का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके उद्घाटन से पहले ही इनको वहां भेज दिया जाएगा। लखनऊ चिड़ियाघर के तमाम पशु-पक्षी अब पूर्वांचल के लोगों को लुभाएंगे।

राजधानी में काफी समय से तमाम पशु-पक्षी दर्शकों का मन मोहा करते थे, लेकिन अब गोरखपुर में प्राणि उद्यान बना दिया गया है। इससे वहां भी दर्शकों को लुभाने वाले पशु और पक्षियों की जरूरत पड़नी स्वाभाविक है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, लिहाजा अफसर किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे, हो सकता है कि तमाम पशु-पक्षी यहां के अलावा अन्य प्राणि उद्यान से भी भेजे जाएं। बहरहाल, जो लिस्ट में प्रस्तावित है, उनको भेजने के लिए परिवहन की तलाश चल रही है। प्राणि उद्यान में सभी पशु-पक्षियों को बड़ी देखरेख में रखा जाता है, इनको दूर की यात्रा कराना बेहद जोखिम भरा होता है, इसलिए सुलभ वाहन और चिकित्सक की देखरेख में इनको भेजा जाएगा। नन्दा नाम की मादा तेंदुआ और मैलानी नाम की मादा बाघ भी यहां के दर्शकों को बड़ी याद आएंगी। चिड़ियाघर लखनऊ में पिछले कई सालों से पशु-पक्षियों के प्रति प्रेमभाव देखा जा रहा है। यहां इनके प्रति स्नेह रखने के लिए तमाम जागरूकता के आयोजन भी होते रहे हैं। यही नहीं प्राणि उद्यान के निदेशक आरके सिंह की सख्ती के चलते भी इन बेजुबानों को चिढ़ाना भी कार्रवाई की जद में था। उछल-कूद करने वाला सेही का जोड़ा, काला हिरन के चार नर और तीन मादा, जंगली बिल्ली मादा, बारहसिंहा दो नर और दो मादा, पाढ़ा एक नर और एक मादा, सियार एक नर और एक मादा, दो अजगर, घड़ियाल एक नर, एक मादा यहां के दर्शकों को अब देखने को नहीं मिलेंगे। इनको प्रथम चरण में ही भेज दिया जाएगा। दूसरे फेज में तमाम तरह के पक्षी भी यहां से गोरखपुर भेज दिए जाएंगे। इनकी भी लिस्ट तैयार की जा रही है।

खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप

आईपीके, जौनपुरः जिले में तेजी से चल रहे मिलावट के कारोबार को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरकत में आ गया है। बुधवार 10 फरवरी को जिले के कई स्थानों पर हुई छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीम के कई स्थानों से दूध व अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया है।

बता दें कि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में 3 से 28 फरवरी तक जनपद में विशेष अभियान चलाकर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की योजना बनी है। इसी क्रम में बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद के अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही की गई। अभिहित अधिकारी डॉ. वेद प्रकाश मिश्र के निर्देशन व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सचल दल में सम्मिलित खाद्य सुरक्षा अधिकारी गण सुनील द्विवेदी द्वारा भैंस के दूध का नमूना, संतोष कुमार दुबे एवं रघुनाथ प्रसाद पटेल द्वारा मिश्रित दूध का नमूना एकत्रित किया गया। जिसे जांच हेतु खाद्य विश्लेषक को भेज दिया गया है। दरअसल, जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री बेतहाशा बढ़ती जा रही है, जिसकी लगातार शिकायतें आ रही थीं।

छात्रा की मौत पर फूटा गुस्सा, आवागमन कराया बंद

दोनों तरफ ईंट का ढेर रखकर पुल कराया बंद, रेलिंगविहीन पुलिया दे रही दुर्घटना को दावत, जिम्मेदार मौन

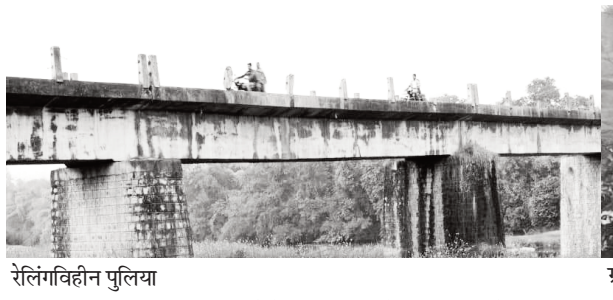

रेलिंगविहीन पुलिया

ग्रामीणों द्वारा ईंट गिराकर बंद कराया गया आवागमन

आईपीके, मिर्जापुरः मिर्जापुर जिले के हलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हथेड़ा गांव निवासी हाईस्कूल की छात्रा की भटवारी गांव स्थित सिंचाई विभाग के पुल से 120 फीट नीचे अदवा नदी में गिरने से हुई मौत के बाद बुधवार 10 फरवरी को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुल के दोनों तरफ ईंट का ढेर रखकर सिंचाई विभाग तथा जिला प्रशासन के प्रति आक्रोश जताते हुए पुल पर आवागमन को पूरी तरह से बंद करा दिया।

ग्रामीण अजय, राजू, शुभम जयराजी, शीला, बसंती चांद, अमर बहादुर, दीनानाथ, धनंजय, अभयराज, इन्द्र बहादुर, राजकुमार गुप्ता आदि ने पुल पर पहुंचकर जिला प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यदि क्षतिग्रस्त पुल की रेलिंग को सिंचाई विभाग द्वारा दुरुस्त करा दिया गया होता तो छात्रा की मौत नहीं होती। बता दें कि थाना क्षेत्र के हथेड़ा गांव निवासी हाईस्कूल की छात्रा सुधा मिश्रा पुत्री शारदा प्रसाद मिश्र बीते मंगलवार 9 फरवरी को साइकिल से स्कूल जा रही थी। जैसे ही भटवारी गांव स्थित क्षतिग्रस्त पुल पर कुछ दूर आगे बढ़ी तो वह साइकिल समेत अनियंत्रित होकर करीब 120 फीट नीचे गिरकर गंभीर रूप घायल हो गई थी। साथ में स्कूल जा रही सहेलियों के चीख-पुकार पर ग्रामीणों ने छात्रा को नदी से बाहर निकाला और उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हलिया लेकर गए। छात्रा की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह के काफी समझाने-बुझाने के बाद परिजनों ने छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाया और गमगीन माहौल में छात्रा का अंतिम संस्कार किया। 40 वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया पुल क्षतिग्रस्त और जर्जर हो गया है और लगभग पूरी रेलिंग टूट गई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों का कई बार ध्यान आकृष्ट करवाया तथा पुल को दुरुस्त कराने के लिए ग्रामीणों ने कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते पुल को दुरुस्त नही करवाया जा सका। बता दें कि क्षतिग्रस्त पुल से कई बार लोग गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं तथा गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने जनहित को ध्यान में रखते हुए पुल को अविलंब दुरूस्त करवाने हेतु जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करवाया है।

जनप्रतिनिधियों को नहीं है परवाह

लोगों से चुनाव जीतने के लिए नेता जी पुल, सड़क सहित सारी सुविधा देने का वादा कर लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही सारे वादे भूल जाते हैं। 4 दशक पुराना पुल जिसकी रेलिंग भी नही है, उस रास्ते पर चलना मौत को दावत देना है लेकिन मजबूरी में ग्रामीणों को आना-जाना पड़ता है।

विकास भवन का डीएम ने किया निरीक्षण

गाजीपुरः जिलाधिकारी एम. पी. सिंह ने शुक्रवार 12 फरवरी को विकास भवन परिसर एवं विकास भवन सभाकक्ष का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय बाहर गंदगी पाये जाने एवं सभाकक्ष के छत से पानी टपकने तथा बिजली के तार बेतरतीब ढंग से बिखरे होने, लाइट की व्यवस्था ठीक न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नाजीर विकास भवन को सख्त निर्देश दिया कि तत्काल छत पर लगे टंकी के पानी को दूसरे स्थान पर लगाया जाए। इसके साथ ही अधि. अभि. ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को निर्देश दिया कि छत से टपकते पानी को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा बिजली, लाईट, साफ-सफाई कराते हुए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।

थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिस-कर्मियों पर हत्या का मुकदमा

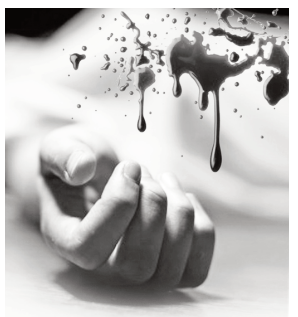

आईपीके, जौनपुरः हिरासत में युवक की मौत के बाद जौनपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। परिजनों व ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन मृतक के भाई की तहरीर पर थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिस-कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। इसको लेकर क्षेत्र में काफी तनाव भी है।

जानकारी के अनुसार लूट के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम चार युवकों को पूछताछ हेतु बक्सा थाना ले आई थी। चारों युवकों से पुलिस ने पूछताछ की और थाना क्षेत्र के चक मिर्जापुर निवासी तिलकधारी यादव के 25 वर्षीय पुत्र किशन यादव उर्फ पुजारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। बीते गुरूवार 11 फरवरी की देर रात किशन की हालत अचानक खराब हो गई। पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में उसे बक्सा सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जब यह घटना आम हुई तो गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ जौनपुर-प्रयागराज राजमार्ग पर पकड़ी ब्लाक चौराहे पर जाम लगा दिया। जहां पर जाम हटवाने के लिए पहुंची पुलिस टीम से कहासुनी के बाद ग्रामीणों ने उन पर पथराव भी किया। जिसके बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा व एसपी राजकरण नैयर ने ग्रामीणों को समझाते-बुझाते हुए घटना के मजिस्ट्रेट जांच की बात कही, तब जाकर ग्रामीण माने। इस मामले में मृतक के भाई अजय यादव की तहरीर पर बक्सा के थानाध्यक्ष अजय सिंह समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। इन पुलिसकर्मियों पर आईपीसी की धारा 302, 394, 452, 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बिना सुविधा शुल्क बिजली कनेक्शन मिलना टेढ़ी खीर

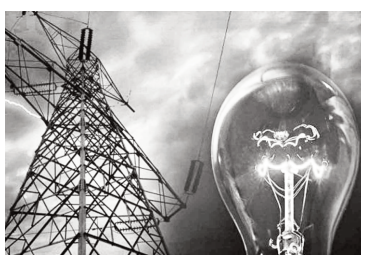

आईपीके, रायबरेलीः एक तरफ योगी सरकार जहां भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तमाम विभागों में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। मनमाने कर्मियों पर कार्रवाई न होने से इनके हौसले बुलंद हैं और आम लोगों को पिसना पड़ रहा है।

रायबरेली जिले में बिजली विभाग की मनमानी लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। विभाग की मनमानी के चलते उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन के नाम पर मोटी रकम वसूल की जा रही है। पैसे न देने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए टाल-मटोल और कागजात संबंधी समस्याओं का बहाना बनाया जा रहा है। बता दें कि मम्मी जी का हाता सब्जी मंडी में बनी मार्केट में बिजली कनेक्शन के नाम पर तो जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहां तो बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा सुविधा शुल्क लेकर रेवड़ी के भाव कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। लोगों की मानें तो इस मार्केट में तीन या चार बैनामे हुए हैं, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं के साथ साठ-गांठ करके फर्जी पेपर बनाकर कनेक्शन बांट दिए हैं। यही नही बिजली विभाग एक तरफ लाइन लॉस दिखाता है, वहीं लाइनमैनों द्वारा बिजली की चोरी कराई जा रही है। यही नही लाइनमैनों के द्वारा माहवारी बांध कर कटिया कनेक्शन दिया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो मो. शकील पुत्र मो. हसीब को बिना किसी पेपर बैनामा के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर अधिकारियों ने कनेक्शन जारी कर दिया। सुविधा शुल्क की मांग पूरी न कर पाने की वजह से शकील का कनेक्शन तो हो गया था, लेकिन मीटर नहीं लगाया गया। यह तो बानगी मात्र है तमाम ऐसे उपभोक्ता हैं, जो कनेक्शन के लिए महीनों से विभाग के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें कनेक्शन नही दिया जा रहा है।

मौनी अमावस्या पर लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी

महामारी पर भारी पड़ी आस्था | कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी लगाई डुबकी

प्रयागराजः श्रद्धा, आस्था और विश्वास किसी भी धर्म के लिए प्राण के समान होते हैं। हिंदू धर्म में यही आस्था अन्य मतावलम्बियों से उसे भिन्न बनाती है। बिना किसी आमंत्रण के एक साथ लाखों लोगों का जुटना, कहीं न कहीं उस धर्म की जड़, पौराणिक मान्यताओं और नवीनता को प्रदर्शित करती है। यह आस्था देवासुर संग्राम के बाद अमृत कलश के छलके हुए कुछ बूंदों के द्वारा प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में शुरू हुआ, जो आज तक अनवरत रूप से जारी है।

प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद मेले का रंग ही निराला हो गया है। श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है और घाटों पर सफाई के साथ-साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के बाद आयोजित इस मेले में गत वर्ष की तरह श्रद्धालुओं की संख्या में कमी रही, लेकिन अन्य जिलों के अलावा देश-विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। मेले की भीड़ और आस्था को देखते हुए भिन्न-भिन्न राजनीतिक दल के लोग भी मेले का आनंद लेने यहां पहुंचे। इस मेले में प्रियंका गांधी भी अपनी बेटी और सहेलियों के साथ भगवा रंग में रंगी नजर आईं और स्नान के बाद उन्होंने विधिवत रूप से दत्तात्रेय गोत्र के अनुसार कर्मकांड भी किया तथा शंकराचार्य से आशीर्वाद भी लिया। माघ मेला के मौनी अमावस्या पर 30 लाख लोगों से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया, हालांकि यह संख्या प्रशासन के अनुसार कम बताई जा रही है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर मनवांछित फल की कामना भी की।

आकर्षण का केंद्र रही पुष्प वर्षा

मेले में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। दोपहर में जब स्नान का पुण्य काल आया तो आसमान में हेलीकॉप्टर द्वारा श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की वर्षा की जाने लगी, जिससे अभिभूत लोगों ने जय श्रीराम का नारा लगाया। साथ ही सरकार का इस मेले की भव्यता को लेकर भी धन्यवाद दिया।

भंडारे और लंगर का हुआ आयोजन

मेले में तमाम स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भंडारे और लंगर का भी आयोजन किया गया था। ओम नमः शिवाय भंडारा, अखंड युवा समिति, जांबाज हिंदुस्तानी, भैया जी का दाल-भात, सत्य प्रकाश मिश्रा इत्यादि द्वारा मेले में भंडारे का आयोजन किया गया। किन्नर अखाड़ा द्वारा भी मेले में भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। मेले के अलावा सिविल लाइन में भी सक्सेना सभा प्रयागराज द्वारा पैदल चल रहे तीर्थ यात्रियों को चाय और नाश्ते का प्रबंध किया गया था। जिसमें संस्था के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सक्सेना, संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष डॉ. अरविंद शरण दरबारी, विजय कुमार, सचिव कौशल सक्सेना, उपाध्यक्ष डॉ. सुमन रानी सिन्हा इत्यादि उपस्थित रहे।

मौनी अमावस्या पर संपन्न हुआ भंडारा

इंजीनियर योगेश मौर्य पुत्र केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री के सौजन्य से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मौनी अमावस्या पर आए हुए भक्तों के लिए चैफटका स्थित काली मंदिर के समीप भोजन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसमें भक्तों तथा स्थानीय जनता ने खूब छक कर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा प्रारंभ होने के पूर्व इंजीनियर योगेश मौर्य ने विधि-विधान से मां काली का पूजन अर्चन कर लोगों को प्रसाद वितरित किया। उक्त अवसर पर पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व विधायक गुरु प्रसाद मौर्या, पार्षद पवन श्रीवास्तव, पार्षद अमन वलेचा, आनंद ओझा, सहित अनेक कार्यकर्ता वितरण कार्य हेतु उपस्थित रहे।

टीकाकरण में अव्वल रहा बलरामपुर अस्पताल: डॉ. राजीव

इलाज के साथ मरीजों की दी जाएगी काउंसिलिंग, वैक्सीन है पूरी तरह सुरक्षित, न घबराएं लोग

आईपीके, लखनऊः प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का गौरव हासिल कर लाखों मरीजों की जिम्मेदारी संभालने वाले बलरामपुर अस्पताल को स्थापित हुए 152 वर्ष हो चुके हैं। पिछले दिनों इस अस्पताल ने धूमधाम से अपना स्थापना दिवस मनाया। ऐसे में अस्पताल के 152 वर्ष के सफर, कोरोना काल में बीएसएल-2 लैब की स्थापना की चुनौतियों, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं व कोरोना टीकाकरण आदि को लेकर इंडिया पब्लिक खबर के **ब्यूरो इंचार्ज शरद त्रिपाठी व विशेष संवाददाता रघुनाथ कसौधन** ने **निदेशक डॉ. राजीव लोचन** से विशेष बातचीत की। प्रस्तुत हैं उसके अंशः

▪ बलरामपुर अस्पताल के स्थापना को 152 वर्ष हो चुके हैं। अब तक यह अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा और यह सफर कैसा रहा ?

इस अस्पताल को स्थापित करने का उद्देश्य पूरी तरह सफल रहा। आजादी से पूर्व यहां सिर्फ अंग्रेजों का इलाज होता था, लेकिन बाद में इंडियन और यूरोपियन वार्ड अलग-अलग बनाए गए। आजादी के बाद बलरामपुर के राजा भगवती सिंह ने यह चिकित्सालय सरकार को सौंप दिया। यह पूरे प्रदेश के अग्रणी अस्पतालों में से एक रहा, क्योंकि यह मेडिकल कॉलेज से भी पुराना है। यहां पर ही सबसे पहले कार्डियक आईसीयू खुला था और यहां पर एक से बढ़कर एक प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दीं। जितने वीआईपी लोग थे, सभी का यहीं पर इलाज होता था। हमारे यहां लगभग 800 बेड हैं और यह प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। यहां पर सारी सुपर स्पेशियलिटी की सुविधाएं मौजूद हैं। नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी से लेकर प्लास्टिक सर्जरी तक की यहां सुविधा उपलब्ध है और हाल ही में प्रदेश का पहला सुपर स्पेशियलिटी डेंटल यूनिट भी यहां स्थापित हुआ है, जिसमें 7 एमडीएस डॉक्टर है। प्रदेश की पहली पीएमएस लैब भी हमारे यहां है और जल्द ही हम यहां पहली माइक्रोबॉयलाजी डिपार्टमेंट भी शुरू करने वाले हैं। प्रतिदिन हमारे 40-45 डायलिसिस होते हैं और हेंड इंजरी का यह प्रमुख केंद्र है। सभी विषयों में यहां पर काफी अच्छा काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां बड़े पैमाने पर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और आज प्रतिदिन 2-3 हो रहे हैं।

▪ पिछले दिनों अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विवि के कुलपति प्रो. एके सिंह ने कहा कि था डॉक्टर इलाज के साथ-साथ मरीजों की काउंसिलिंग भी करें ? इस दिशा में क्या प्रयास हो रहा है ?

डॉक्टर का काम इलाज करना होता है और मरीजों को बेसिक चीजें समझाने में हम उसका समय खराब नही कर सकते हैं। मरीजों के काउंसिलिंग का काम

डॉ. राजीव लोचन, निदेशक

पैरामेडिक्स व अन्य सोशल वर्कर्स का है। हमारे सिस्टम में कहीं कमी है, जिसे दूर करने की जरूरत है। फिलहाल हमारे पास एक ही काउंसलर है जो मरीजों को गाइड करने का काम करता है। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और डॉक्टरों पर लोड कम होना चाहिए। हमने काउंसलर के और अधिक पदों की मांग शासन के समक्ष रखी है, जिसकी पूर्ति होते ही मरीजों को बेहतर काउंसिलिंग भी दी जाएगी।

▪ कोरोना काल में आरटीपी-सीआर जांच के लिए बीएसएल-2 लैब स्थापित की गई। यह कितना चुनौतीपूर्ण रहा ?

यह बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था और बहुत हाई लेवल का काम था। जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नही था। लैब बनाने के लिए मैंने खुद केजीएमसी के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉ. अमिता से इसके बारे में जानकारी ली। वहां से अध्ययन करने के बाद हमने प्राइवेट वायरोलॉजी लैब बनाने वालों से भी जानकारी जुटाई। जिसके बाद हमने खुद बहुत अच्छे स्तर की आरटीपी-सीआर लैब स्थापित की। लैब बनने के बाद हमारे पास लैब टेक्नीशियन नही थे तो इसकी भी व्यवस्था बनाई गई। कुछ हमें एनएचएम से मिले, कुछ विभागों को हमने बंद किया और फिर इसका काम आगे चल पड़ा। अच्छी बात यह है कि अब हमें एमडी माइक्रोबायोलॉजी के पद भी मिल गए हैं, वह भी इस काम को देखेंगे और आगे हम माइक्रोबायोलॉजी बना पाएंगे।

▪ कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, ऐसे में आम लोग कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। क्या यह उचित है ?

कोरोना को लेकर लापरवाही बरतना खतरे को निमंत्रण देना है। यूरोप में अभी भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यह स्थिति हमारे यहां न आए इसके लिए सचेत रहना होगा। वैसे तो कोरोना में हमारे देश ने काफी अच्छा काम किया, खास तौर से उत्तर प्रदेश ने। मेरा तो यहां तक कहना है कि विश्व में सबसे अच्छा काम यूपी में हुआ है। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हमने कोरोना पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पा लिया, यह बहुत बड़ी सफलता है। अभी भी कोरोना के वैरिएंट सामने आ रहे हैं और इसे फैलने में देर नही लगेगी। ऐसे में सभी लोग मास्क नियमित लगाएं और दो गज की दूरी का पालन जरूर करें।

▪ कोरोना से उबरने के बाद मरीजों में कई मनोविकार या अन्य समस्याएं उभर रही हैं। ऐसे में उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ?

सबसे जरूरी यह है कि आप अपने फिजीशियन से लगातार संपर्क में रहें। इसमें परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, परिवार के सदस्यों को ठीक होने के बाद भी मरीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहां पोस्ट कोरोना क्लीनिक खोली गई है, जिसमें योग, होम्योपैथिक आदि चिकित्सक मौजूद हैं। जिन लोगों को समस्याएं हो रही हैं, तो वह यहां आकर जरूरी सलाह ले रहे हैं। अगर वह कुछ समय तक लगातार इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो धीरे-धीरे यह समस्या दूर हो जाएगी।

▪ अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी विभाग स्थापित करने की योजना है। यह कब तक स्थापित हो जाएगा ?

जैसे ही हमारे यहां दोनों माइक्रोबायोलॉजिस्ट ज्वाइन कर लेंगे, हम उसके एक महीने के अंदर काम शुरू कर देंगे। यह विभाग शुरू होने से मरीजों को काफी अधिक सुविधा मिलेगी और कल्चर जांच के लिए अन्य संस्थानों की दौड़ से छुटकारा मिलेगा।

▪ एमआरआई भवन तैयार हो गया है। मरीजों को कब तक इसकी सेवाएं मिल पाएंगी ?

इस बारे में अभी हम कुछ नही कह सकते, क्योंकि अभी तक मशीनें आने की कोई सूचना नही मिली है। डीजी साहब इस बारे में मैं वार्ता करूंगा, जिससे जल्द से जल्द लोगों को इसकी सुविधा भी मिल सके।

▪ बाहर की दवाएं या बाहर से जांच के लिए मरीजों को कहा जा रहा है ? क्या इसकी शिकायत के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है ?

यह पूरी तरह से गलत शिकायत है। एमआरआई के अलावा हमारे यहां सभी प्रकार की जांच होती है और कोई भी चिकित्सक बाहर से जांच लिखता नही है। दवाओं को लेकर कभी-कभी समस्या हो जाती है। हमारे यहां दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति होती है और यहां भर्ती मरीजों को पर्याप्त दवाएं मिलती हैं।

▪ कोरोना वैक्सीनेशन का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल नही हो सका ? इसके पीछे क्या कारण रहे ?

सभी चिकित्सालयों की अपेक्षा बलरामपुर अस्पताल कोरोना टीकाकरण में सबसे अव्वल रहा। हमने अपने यहां केंद्रों पर एक कम्प्यूटर ऑपरेटर लगा रखा है, जिनका रजिस्ट्रेशन है और वह छूट गए हैं तो उन्हें भी बुलाकर टीका लगाया जा रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिसकर्मी ड्यूटी की वजह से टीका लगवाने नही आ पा रहे हैं, तो हमने पुलिस लाइन में केंद्र बनाने की योजना बनाई गई पर वहां उन्होंने केंद्र बनाने से मना कर दिया। इन सभी चुनौतियों के बीच भी हमने अन्य चिकित्सालयों की अपेक्षा काफी बेहतर वैक्सीनेशन किया।

▪ वैक्सीन को लेकर अभी भी आम लोगों में भ्रम की स्थिति है। इसको लेकर आपका क्या कहना है ?

वैक्सीन को लेकर किसी को भी घबराने की जरूरत नही है। यह पूरी तरह सुरक्षित है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद 50 वर्ष की उम्र के ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर शुरू होने जा रहा है। वैक्सीन एक वरदान की तरह होता है। इसके पहले स्माल पॉक्स, पोलियो आदि की वैक्सीन आई, जिसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। आज यह बीमारियां हमारे यहां नही हैं। पोलियो के समय भी इसको लेकर अफवाह फैली, जिसका बाद में हमें खामियाजा भुगतना पड़ा पर अब हमें यह गलती नही करनी है।

▪ एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी माह में ही अमेरिका में कोरोना से एक लाख लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब भारत में कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया। इस सफलता के पीछे क्या कारण रहे ?

कोरोना के नियंत्रण आदि को लेकर जो काम हमारे देश में हुआ है, उस पर हर देशवासी को गौरवान्वित होना चाहिए। आज हमारे यहां दो वैक्सीन हैं, जिसकी मांग आधी दुनिया कर रही है। प्रधानमंत्री की अपील का जनता और स्वास्थ्यकर्मियों पर बहुत बड़ा असर पड़ा और लोगों ने इसे गंभीरता से लिया। हमारे देश में भविष्य की व्यवस्थाएं बनाई गई और कभी भी बेड्स की कमी नही हुई। अमेरिका में इसको लेकर अभी भी लापरवाही बरती जा रही है, जिसका परिणाम है कि आज भी वहां पर कोरोना नियंत्रण में नही आ पा रहा है।

▪ स्वास्थ्य बजट में 137 फीसदी का इस बार इजाफा किया गया। इसको आप कैसे देखते हैं ?

यह बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी, जिसके लिए उनका धन्यवाद। बजट में 137 फीसदी की रिकॉर्ड बढ़ोतरी करना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है और देश के हेल्थ स्ट्रक्चर को काफी मजबूती मिलेगी।

कैमरे ही आसान करेंगे ट्रैफिक की राह

दुर्घटना वाले क्षेत्र की हो रही मैपिंग, यातायात नियम तोड़ने वालों की देंगे जानकारी

आईपीके, लखनऊः जाम की समस्या हो या यातायात नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगानी हो, इसके लिए कैमरे पर ही निर्भर होना होगा। इसके लिए कैमरों को ऐसी अत्याधुनिक तकनीकी से लैस किया जाए जो हमारी आवश्यकताओं को समझ कर काम कर सकें। इससे शहर में जाम के साथ ही यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी आसानी से शिकंजा कसा जा सकेगा।

यह जानकारी आईआईटी कानपुर के प्रो. प्रन्मेष चक्रवर्ती ने दी। वह बुधवार 10 फरवरी को राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कांफ्रेंस हाल में एक्सपर्ट कंसलटेशन ऑन स्टेट रूल्स फॉर रूल सेफ्टी अंडर द मोटर व्हीकल (एमेंडमेंट) एक्ट 2019 आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रोड सेफ्टी सेल के साथ ही अन्य विभागों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में नेशनल हाइवे, हेल्थ, पीडब्लूडी के साथ परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ ही आईआईटी एक्सपर्ट ने भी इस बारे में अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह, परिवहन आयुक्त धीरज साहू, अपर परिवहन आयुक्त राजस्व अरविंद कुमार पांडेय, आरटीओ रामफेर द्विवेदी, एआरटीओ प्रवर्तन संजय तिवारी, रोडवेज के सीजीएम टेक्निकल जयदीप वर्मा और कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए कई बिंदुओं पर काम चल रहा हैं। अब ब्लैक स्पॉट में वही क्षेत्र सामने आ रहे हैं जहां पर दुर्घटनाएं हो रही है। इसके लिए मैपिंग भी की जा रही है।

कैमरे के जरिए मिलने लगे सूचनाएं

प्रो. प्रन्मेष ने दुर्घटनाओं में कमी लाने लिए कैमरे पर फोकस करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाएं रोकने के लिए अब कैमरे पर अधिक फोकस किया जाना चाहिए, हालांकि अभी कैमरा उतना एक्सपर्ट नहीं बन सका है, जिससे वह हमारे सभी काम पूरे कर सके। इसे और अत्याधुनिक बनाना होगा। वाहन चलाते समय यदि कोई हेलमेट नहीं पहने है तो इसकी जानकारी कैमरा तत्काल अधिकारियों को दे। कहीं दुर्घटना होती है तो कैमरे के जरिए इसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों तक पहुंच सके। ताकि राहत कार्य तेज गति से किया जा सके।

चालकों को नहीं सभी साइनेज की जानकारी

आईआईटी रुड़की के प्रो. इंद्रजीत घोष ने बताया कि सिर्फ रोड इंजीनियरिंग सुधार कर दुर्घटनाएं नहीं रोकी जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि चालकों को ड्राइविंग के नियमों की सभी जानकारियां हो। कई ऐसे चालक हैं जो परिवहन विभाग के सभी साइनेज का मतलब नहीं बता सकते हैं। इसके बाद भी उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। चालकों की जानकारी बढ़ाने के लिए लगातार कैम्प चलते रहने चाहिए। उन्होंने बताया कि मैनुअल कारण भी एक्सीडेंट के होते है। वाहन चलाते समय चालक को झपकी आना या फिर मोबाइल से बातचीत करने पर भी हादसे होते हैं। इस पर लोगों को खुद से जागरुक होना होगा।

जरा सी भी नींद आ रही हो तो ड्राइविंग कतई ना करें।

पुलिस वालों की होनी चाहिए ट्रेनिंग

आईआईटी कानपुर के प्रो. आदित्य के अनुसार दुर्घटनाओं की पहली सूचना सबसे पहले पुलिस वालों के पास ही पहुंचती है। पुलिस ऐसे मामलों में बेहद सामान्य तरीके से एफआईआर लिख कर आगे का काम शुरू कर देती है। वह एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं करती कि दुर्घटना कैसे हुई ? वाहन ने आगे से टक्कर मारी या फिर पीछे से। दुर्घटना के स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं होता है। ऐसे में उस स्थान पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए विभागीय लोग कोई कदम नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि दुर्घटना के मामले में पुलिस को बेहद संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि ऐसे मामलों को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें।

सौभाग्य योजना से भी नहीं मिला बिजली कनेक्शन का 'सौभाग्य'

आज भी अंधेरे में बीकेटी का चिलांगीपुरवा गांव, नाकाफी साबित हो रही सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई योजना

बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर आक्रोश जाहिर करते ग्रामीण

आईपीके, लखनऊः केंद्र और राज्य सरकार की हर घर बिजली की मुहिम राजधानी में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) भी सबको बिजली दिला पाने में नाकाफी साबित हो रही है। आजादी के 7 दशक बाद भी राजधानी क्षेत्र के ही एक गांव में बिजली सपना सरीखी हो गयी है। देश की आजादी के सात दशक बाद भी इस गांव के बच्चे ढिबरी की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं।

गांव के विद्युतीकरण के लिए ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के साथ विद्युत विभाग के अधिकारियों तक अपनी फरियाद लगायी, मगर ग्रामवासियों का अंधेरा दूर न हो सका। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना में 24 लाख कनेक्शन देने का दावा भले ही मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड करता है, मगर राजधानी के बीकेटी स्थित सिंघामऊ ग्राम पंचायत के मजरा चिलांगीपुरवा के लोग आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। बताते चलें कि विद्युत विभाग की ओर से ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना संचालित की जा रही है, बावजूद इसके राजधानी के ही ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं पहुंच सकी है। जिससे आज भी ग्रामीण बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं।

20 से 25 परिवार का है मजरा

बीकेटी के सिंघामऊ ग्राम पंचायत के चिलांगीपुरवा मजरे में करीब 20 से 25 परिवार रहते हैं। यहां के ग्रामीणों की मानें तो इटौंजा बिजली घर से लेकर विभाग के उच्चाधिकारियों और जनप्रतिनिधि तक अपनी फरियाद लगायी, लेकिन शिकायत के बाद भी मजरे का विद्युतीकरण नहीं हो सका।

डीडीयूजीजेवाई (न्यू) योजना में 13 गांव शामिल

विद्युत विभाग की ओर से लखनऊ जनपद के ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना संचालित की जा रही है। डीडीयूजीजेवाई न्यू योजना के तहत कुल 13 गांव शामिल किए गए थे। इसके तहत गरीब श्रेणी के 321 बीपीएल परिवारों तक बिजली पहुंचायी गयी। इसके लिए 6,314 लाख के करीब बजट खर्च किया गया। योजना में करीब 537 किमी हाईटेंशन लाइन और 41 किमी के करीब एलटी लाइन का भी निर्माण कराया गया।

आरजीजीवीवाई 12वीं योजना में 930 गांव शामिल

12वीं राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीआई) में कुल 930 गांव शामिल थे। इस योजना के तहत 1,942 घरों तक बिजली पहुंचायी गयी। इसके अलावा कुल 2,547 बीपीएल परिवारों तक बिजली पहुंचायी गयी। इसके लिए करीब 12,452 लाख रूपए का बजट खर्च किया गया। इन गांवों तक विद्युतीकरण कराने के लिए करीब 278 किमी हाईटेंशन लाइन और 1,200 किमी के लगभग एलटी लाइन का भी निर्माण कराया गया।

इन योजनाओं का काम हो चुका है पूरा

आरजीजीवीवाई की 10वीं, 11वीं और 12वीं योजना और डीडीयूजीजेवाई (न्यू) योजना में शामिल सभी काम पूरे हो चुके हैं। इन सभी योजनाओं की बंदी की प्रक्रिया चल रही है। आरजीजीवीवाई योजना के प्रभारी मुख्य अभियंता एसपी करगेती ने बताया कि डीडीयूजीजेवाई (न्यू) योजना में शामिल किए गए कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इस योजना का कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था मेधज के अनिल यादव ने बताया कि योजना में शामिल किए गए सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। विभागीय स्तर पर योजना को बंद किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

सौभाग्य योजना का भी कार्य पूरा

केंद्र सरकार की ओर से 2017 में शुरू की गयी सौभाग्य योजना में भी शामिल कार्यों को पूरा कर लिया गया है। राजधानी लखनऊ में सौभाग्य योजना का कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था टाटा पॉवर प्रा. लि. के परवेज आलम ने बताया कि सौभाग्य योजना में शामिल किए गए ग्रामीण इलाकों का काम दिसंबर में ही पूरा कर लिया गया है। योजना को बंद करने की विभागीय प्रक्रिया चल रही है।

विद्युतीकरण के लिए बजट की दरकार

सौभाग्य योजना के नोडल अधिकारी अधीक्षण अभियंता जेबी सिंह के अनुसार योजना में शामिल सभी गांवों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिन गांवों या मजरों में विद्युतीकरण कार्य नहीं हुआ है, उन्हें आगे की योजना में शामिल कर कार्य कराया जाएगा। वहीं सर्किल 10 के अधीक्षण अभियंता एके लाल के मुताबिक उक्त मजरे के विद्युतीकरण के लिए बजट मांगा गया है। बजट आवंटन होते ही विद्युतीकरण कराया जाएगा।

हर्बल रंग लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे

कंडों से होलिका दहन का बच्चों ने लिया संकल्प

आईपीके, लखनऊः इस बार होली का पर्व खुशियों की सौगात लाने के साथ-साथ पर्यावरण को संजीवनी देने वाला भी होगा। देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों ने इस बार होली के त्यौहार को प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त रखने का संकल्प लिया है। हर्बल रंगों के साथ-साथ पेड़ों की सुरक्षा और उन्हें बचाने के लिए बच्चों ने गोबर के कंडों से होलिका दहन की शपथ ली है।

इंडिया पब्लिक खबर ने हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार होली को इस बार पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ने का बीड़ा उठाया है। इस अभियान में हमने देश के स्वर्णिम भविष्य व सामाजिक संस्कारों से भारत की परिपाटी को विभूषित करने वाले बच्चों को जोड़ा है। जिससे उनके माध्यम से समाज में जागरूकता और त्यौहारों के असली अर्थ को लोगों तक पहुंचाया जा सके।

होली को बनाएंगे पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण

राजधानी के गोमती नगर के विनय खंड-3 में स्थित रेड रोज सीनियर सेकेंड्री स्कूल के बच्चों ने इंडिया पब्लिक खबर के इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने संकल्प मंत्र 'हम संकल्प लेते हैं कि इस बार होली के पावन पर्व पर हम सभी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए गाय के गोबर से बने कंडों का प्रयोग कर होलिका दहन करेंगे। हम अपने पेड़-पौधों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने में अपना योगदान देंगे। इसके साथ ही रासायनिक रंगों से परहेज करते हुए हर्बल प्राकृतिक रंगों से होली मनाएंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क और दो गज की दूरी का भी विशेष ध्यान रखेंगे और दूसरे लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे।' को दोहराया और स्वयं के साथ समाज के लोगों को भी जागरूक करने की भी बात कही। होली के त्यौहार पर कोरोना से बचाव व इस संकल्प को लेकर हमने बच्चों से भी बातचीत की।

▪ 11वीं की छात्रा आस्था श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार हम कोरोना वायरस से बचाव और पर्यावरण संरक्षण को सबसे पहली प्राथमिकता देंगे। हर्बल रंगों से त्यौहार मनाने के साथ ही गोबर के कंडों से ही होलिका दहन भी करेंगे।

▪ 12वीं की छात्रा सोनिका सिंह ने कहा कि गाय हमारी माता है और गोबर के कंडे हमारी प्रकृति को नुकसान भी नही पहुंचाते हैं। इस साल हम स्वयं और अन्य लोगों को गोबर के कंडों से होलिका दहन करने के लिए प्रेरित करेंगे। जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके।

▪ 12वीं के छात्र निष्कर्ष सिंह ने कहा कि बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण हम सभी के लिए खतरा है। इस बार हम होली में हर्बल रंगों का प्रयोग करेंगे, जिससे त्वचा को नुकसान भी न पहुंचे और हम सुरक्षित भी रहें।

▪ 12वीं के ही छात्र साहिल अफरीदी ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से न फैले, इसके लिए हम मास्क और दो गज की दूरी का विशेष ध्यान रखेंगे।

प्रकृति सुरक्षित तो हम भी रहेंगे सुरक्षित

गोमती नगर के विवेक खंड-2 में स्थित तुलसा देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में बच्चों ने इस अभियान में खासा उत्साह दिखाया और इस होली को प्रकृति के संरक्षण के त्यौहार के रूप में मनाने का संकल्प लिया। बच्चों ने इस बार होली के पर्व पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए गाय के गोबर से बने उपलों से होलिका दहन की बात कही। साथ ही बच्चों ने रासायनिक रंगों से दूरी बनाते हुए हर्बल प्राकृतिक रंगों से होली खेलने का संकल्प लिया। यहां पर तमाम बच्चों ने स्लोगन और कविताओं के माध्यम से भी अपने सहपाठियों को अभियान की महत्ता का पाठ पढ़ाया। बच्चों ने यहां भी खुलकर अपने विचार व्यक्त किए।

▪ 12वीं की छात्रा गौरी प्रजापति ने कहा कि सूखे रंगों का प्रयोग करने से हमारी त्वचा को नुकसान नही पहुंचता है। रासायनिक रंग हमारी त्वचा को काफी क्षति पहुंचाते हैं। इस बार होली को हम पर्यावरण संरक्षण के त्यौहार के रूप में मनाएंगे।

▪ 9वीं की छात्रा सीमा यादव ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हम दो गज की दूरी और मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे। इसके लिए लोगों को भी जागरूक करेंगे।

▪ 10वीं के छात्र दीपांशू ने कहा कि हम तभी तक सुरक्षित रहेंगे, जब तक प्रकृति सुरक्षित रहेगी। इसलिए हम सभी गाय के गोबर से बने कंडों से ही होलिका दहन करेंगे। जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नही होगा और हमारे पेड़-पौधे भी संरक्षित रहेंगे।

▪ 10वीं के छात्र अभिषेक यादव ने संकल्प लिया कि रासायनिक रंग काफी हानिकारक होते हैं, ऐसे में इस बार हम हर्बल रंगों का ही प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी और मास्क की अनिवार्यता भी सुनिश्चित करेंगे।

शपथ लेते रेड रोज सेकेंडरी स्कूल के बच्चे

प्रदूषण मुक्त होली

शपथ लेते टी.डी. गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्र व शिक्षक

आस्था श्रीवास्तव | निष्कर्ष सिंह | साहिल अफरीदी | सोनिका सिंह
अभिषेक यादव | दीपांशू | गौरी प्रजापति | सीमा यादव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

24वां दीक्षान्त समारोह

16 फरवरी, 2021

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षान्त समारोह दिनांक 16 फरवरी, 2021 को विश्वविद्यालय के महन्त अवैद्यनाथ संगोष्ठी भवन में मध्याहन् 12:00 बजे से आयोजित होना है। श्रीमती आनन्दीबेन पटेल, माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश समारोह की अध्यक्षता करेंगी। प्रो0 पंजाब सिंह, पूर्व कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।

विश्वविद्यालय के समस्त सम्मानित आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, महाविद्यालय शिक्षक संघ, परिषदों के सम्मानित सदस्य, पदाधिकारियों, विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, उपाधि धारकों एवं सम्बन्धित जनों को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 16.02.2021 को पूर्वाहन् 11:30 बजे विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में सादर आमंत्रित है। आप सभी से निवेदन है कि निमंत्रण पत्र अवश्य लायें। समारोह में मोबाइल फोन, पेन एवं काले रंग के कपड़ों का प्रयोग वर्जित है, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

सीवर निर्माण में सुस्ती ने बढ़ाई 'पौध' विक्रेताओं की मुसीबत

बुरी तरह प्रभावित हो रही आमदनी, शहर की हरियाली पर पड़ रहा विपरीत प्रभाव

दुकान पर पसरा सन्नाटा

आईपीके, लखनऊः राजधानी के कई इलाकों में सीवर लाइन डाली जा रही है। यह काम शहर को स्मार्ट बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन कच्छप गति से चल रहा निर्माण कार्य लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। इसकी वजह से फूलों के पौधे बेचने वाले लोगों की कमाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है, पर जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

बता दें कि हजरतगंज के करीब राणा प्रताप मार्ग में करीब 15 परिवार सालों से पौधे बेचने का काम करते हैं। इसी मार्ग पर पिछले दो माह से सीवर लाइन का काम चल रहा है। यहां पौधों की बिक्री एकदम घट गई है। पौधों की बिक्री घटना ही यह सबित करती है कि पर्यावरण पर इसका असर पड़ रहा है। निर्माण कार्यों के चलते शहर की हरियाली प्रभावित हो रही है। स्मार्ट सिटी कार्ययोजना के अंतर्गत शहर के राणाप्रताप मार्ग पर खुदाई चल रही है। इसमें पाइप लाइन डाली जानी है। इसका काम इतना धीमा है कि जहां खुदाई हो रही है, वहां महीनों से सड़क का पुनर्निर्माण नहीं हो सका है। इसका असर यह है कि अगर सड़क पर चलना है तो लोगों को धूल और गुबार का सामना करना ही पड़ता है। इन स्थानों पर अधिकतर जाम भी लगता है। यही नहीं लोगों की रोजी पर भी सीधे असर पड़ता है। धूल और गुबार वाले स्थानों पर खरीददार जाना ही नहीं चाहते हैं।

दुकानदारों ने बयां किया दर्द

राजेश दीक्षित

पप्पू राजपूत

हिमांशू

बुद्देश्वर निवासी राजेश दीक्षित का कहना है कि हम सालों से यहां फूल बेचने का काम कर रहे हैं। यहां काफी दिनों से खुदाई का काम चल रहा है। डायवर्जन होने से लोगों का आना-जाना लगभग बंद हो गया है। यहां पौधों की 15-20 दुकानें लगती हैं। यहां से लोगों का निकलना बंद है, लिहाजा पौधों की बिक्री भी ठप है। जितने पौधे रोज बिकते थे, वह शहर की हरियाली भी बढ़ाते थे, अब इस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। राजेश बताते हैं कि वह करीब 20 सालों से पौधे ही बेचते आए हैं। एक दिन में हजारों के पौधे बिकते थे, लेकिन अब दिन भर ग्राहक का इंतजार करना पड़ता है। बिक्री पूरी तरह से बंद है। यहां डहेलिया, गेंदा, डेंटस, केल और सूटलाइसियम महीनों से दुकान में डंप हैं। बालागंज निवासी पप्पू राजपूत बताते हैं कि सबसे ज्यादा संकट यहां पौधों के लिए पानी का है। पास में नल था, इससे पौधों को सींचा जाता था। अब मार्ग बंद होने से पानी दूर से आता है। 15 लीटर पानी के लिए 5 रुपये अदा करने होते हैं। ठाकुरगंज निवासी हिमांशू ने बताया कि पत्तियों पर धूल जमने से यह खराब भी हो जाते हैं, इसलिए इनको रोज धोना पड़ता है। यदि ऐसा न किया जाए तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है और इनको कोई खरीदेगा भी नहीं। यदि सड़क का सन्नाटा मिटे तो बिक्री भी बहाल होगी। जब लोग ज्यादा पौधे खरीदेंगे तो ज्यादा हरियाली दिखेगी।

प्रोब बिलिंगः सवालों के घेरे में बिलिंग एजेंसियों की कार्यप्रणाली

घटिया बिलिंग सॉफ्टवेयर व खराब क्वालिटी के मीटर जिम्मेदार

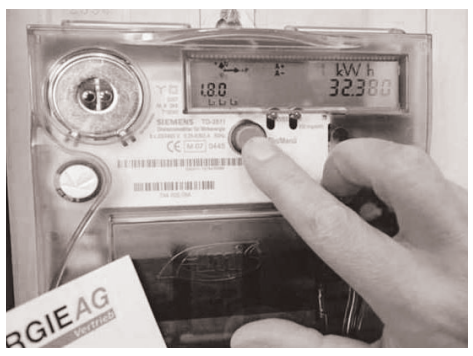

आईपीके, लखनऊः प्रदेश में डाउनलोड प्रोब बिलिंग को लेकर हंगामे के बाद बिलिंग एजेंसियों की कार्यप्रणाली और मीटरों को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। उपभोक्ता परिषद् ने प्रोब बिलिंग पर बिलिंग एजेंसियों की असफलता को लेकर कई अहम सवाल खड़े किए हैं।

घटिया बिलिंग सॉफ्टवेयर, घटिया क्वालिटी के मीटर को प्रोब बिलिंग न हो पाने का जिम्मेदार ठहराया गया है। बिलिंग एजेंसियों के टेंडर की जांच की मांग की गयी है। प्रोब बिलिंग को लेकर उपभोक्ता परिषद् ने खुलासा किया है कि वर्ष 2018-19 में बिलिंग एजेंसियों का टेंडर फाइनल हो रहा था तभी इस पर सवाल खड़े हुए थे कि जल्दबाजी में टेंडर प्रक्रिया पूरी की गयी। उपभोक्ता परिषद् की ओर से आरोप लगाया गया है कि कुछ उच्चाधिकारियों ने निजी स्वार्थ में आकर मनमाने तरीके से जल्दबाजी में टेंडर फाइनल किए। आज उसी का नतीजा है कि प्रदेश में 7 बिलिंग एजेंसियों द्वारा सिर्फ 20 से 22 प्रतिशत ही डाउनलोड प्रोब बिलिंग हो पा रही है, जबकि आर-एपीडीआरपी यानि शहरी क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं की डाउनलोड प्रोब बिलिंग 6 महीने में और नॉन आरएपी-डीआरपी यानि ग्रामीण क्षेत्र में 12 महीने में डाउनलोड प्रोब बिलिंग पूरी हो जानी चाहिए थी। बिलिंग एजेंसियों की इस लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ता भुगत रहे हैं। उपभोक्ता परिषद् ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग सरकार से की है।

नाकारा कम्पनियों से खरीदे मीटर

उपभोक्ता परिषद् के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार, निजी स्वार्थ में बिजली कम्पनियों ने करीब 78 मीटर निर्माता ऐसी कम्पनियों से मीटर खरीद डाले, जो कम्पनियां दूसरे राज्यों में नाकारा साबित हो चुकी हैं। उनके अनुसार तकनीकी खामियों वाले दर्जनों मीटर ऐसे हैं, जो प्रोब बिलिंग के मानक को ही पूरा नहीं करते हैं। वहीं कई जगह तो बिलिंग कम्पनियों के सॉफ्टवेयर भी मानक के अनुसार नहीं हैं। यह कहना गलत न होगा कि बिलिंग कम्पनियों के सॉफ्टवेयर और दर्जनों प्रकार के घटिया कंपनी के मीटर प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए समस्या बन गए हैं।

खुशखबरी : अब हर घर में चहचहाएंगी गौरैया

प्रदर्शनी में घरौंदे ने लोगों का मोहा मन, पर्यावरण के लिए चेन की तरह काम करते हैं पक्षी

आईपीके, लखनऊः राजभवन में आयोजित पुष्प, फल एवं शाकभाजी प्रदर्शनी में कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिली, जिनके निर्माताओं ने पर्यावरण के प्रति काफी स्नेह दिखाया है। इन युवाओं ने पशु-पक्षियों के प्रति स्नेह का उदाहरण पेश कर लोगों को घरों में रहने वाली गौरैया पालने के लिए प्रेरित किया है।

सालों पहले यह नन्हीं चिड़िया घोंसले बनाकर घरों में रहा करती थी, लेकिन अब इनके रहने के ठिकाने कम हो रहे हैं। पक्के मकानों में इनको रहने के लिए जगह नहीं है। गौरैया के घोसलों को अपने घर की मिट्टी की दीवारों के दरारों, बसों और रेलवे स्टेशनों की छतों में देखा जाता था। आज भी तमाम गलार नामक चिड़िया को दीवारों में जगह बनाकर रहते हुए देखा जा सकता है। आलमनगर-उत-रेटिया मालगाड़ी बाईपास पर बने कई पुलों में इन्होंने अपना ठिकाना बना रखा है। यह चिड़िया रेलवे पुल में बने छेद को अपना घर बनाकर रह रही हैं। इन पुलों में पानी के रिसाव को निकालने के लिए नन्हे छेद बनाए गए थे। तमाम बार यह उछल-कूद करते हुए लोगों की बाइक के सामने आ जाती हैं। लोग भी इनको बचाने के लिए बाइक रोकते हुए देखे जाते हैं। यह पंख उठाती हैं और अपने घरौंदों के इर्द-गिर्द बैठ जाती हैं। बताया जाता है कि ऐसी चिड़ियों का लगभग 10,000 वर्षों का इतिहास है। मनुष्य जीवन में इन पक्षियों की जगह कम हो रही है, इसलिए इनकी संख्या भी घट रही है। पेड़ों की कटाई, खेतों में कृषि रसायनों का अधिकाधिक प्रयोग, टेलीफोन टावरों से निकलने वाली तरंगें, घरों में शीशे की खिड़कियां इनके जीवन के लिए प्रतिकूल हैं।

साथ ही साथ, जहां कंक्रीट की संरचनाओं के बने घरों की दीवारें घोंसले को बनाने में बाधक हैं वहीं घर, गांव की गलियों का पक्का होना भी इनके जीवन के लिए घातक है, क्योंकि ये स्वस्थ रहने के लिए धूल स्नान करना पसंद करती हैं जो नहीं मिल पा रहा है। ध्वनि प्रदूषण भी गौरैया की घटती आबादी का एक प्रमुख कारण है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 2002 में इसे लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल किया था। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार कैबिनेट ने भी गौरैया को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भी इनकी घटती संख्या पर चिंता जताई है। इसलिए इंदिरा नगर निवासी प्रखर सक्सेना ने काठ और प्लास्टिक के बर्ड हाउस बनाए हैं। इनमें बुलबुल और गौरैया जैसी छोटी चिड़िया आसानी से रह सकती है। इनमें कई चिड़ियां एक साथ रह सकती हैं।

पर्यावरण के लिए चेन की तरह हैं पक्षी

लखनऊ प्राणि उद्यान में डॉ. अशोक का कहना है कि जब एक चेन को आप तोड़ते हैं तो नुकसान स्वाभाविक होता है। पक्षी भी पर्यावरण के लिए चेन की तरह ही काम करते हैं। गौरैया पहले झाड़ियों में रहती थीं। यह मिट्टी के घरों में लगी धन्नियों में बसती थी। अब इनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अगर इनके लिए ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन यह विलुप्त हो जाएंगी।

बकाया वेतन, पेंशन के लिए आमरण अनशन करेंगे जल निगम कर्मी

लखनऊः जल निगम कर्मियों-पेंशनरों को बीते 5 माह से बकाया वेतन, पेंशन का भुगतान न किए जाने, वर्ष 2016 से पेंशनरों के बकाया देयों का भुगतान न किए जाने और अमानवीय तरीके से मृतक आश्रित कोटे की भर्तियों पर लगी रोक को बहाल करने समेत अन्य मांगों को लेकर उप्र जल निगम संघर्ष समिति आगामी 16 फरवरी से क्रमिक अनशन करेगी। इसके अलावा जल निगम मुख्यालय पर आगामी 23 फरवरी को समिति प्रदर्शन के बाद आमरण अनशन शुरू करेगी।

जल निगम मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के मीडिया प्रभारी अजय पाल सिंह सोमवंशी ने बताया कि 18 जून 1975 से पहले स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग (1946), जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (1927) नामक एक राजकीय विभाग था। जिसे विश्व बैंक से 17,040 करोड़ रूपए के ऋण लेने के लिए उप्र जल सम्भरण व सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 के तहत उप्र जल निगम में बदल दिया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश के सभी जनपद जल की गुणवत्ता की समस्या से परेशान हैं। इसके चलते पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां महामारी का रूप ले रही हैं, वहीं गिरता भूजल स्तर, नदियों व झीलों पर बड़े पैमाने पर प्रदूषण व वायु प्रदूषण चुनौती बनकर सामने खड़ा हुआ है। इन समस्याओं से निपटने के लिए उप्र सरकार की ओर से द एनवॉयरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अंगीकृत किया गया है।

प्रदेश में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या मंत्रालय न होने के कारण इनका दायित्व एनजीटी के दिशा-निर्देशों के पालन समेत उप्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड या नगरीय निकायों के पास हैं। उप्र जल निगम पर प्रदेश की सभी नगरीय, ग्रामीण पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज व नदी प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का दायित्व था। अन्य विभागों के अधिष्ठान व्यय के अनुसार उप्र जल निगम को भी 22 प्रतिशत सेन्टेज राशि प्राप्त होती थी। जिसे शासन द्वारा एक अप्रैल 1997 को घटाकर मात्र 12.5 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया। जल निगम बोर्ड द्वारा बार-बार संशोधन की अपील के बाद भी शासन की ओर से इस पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन हर घर नल से जल की पूर्ति के लिए प्रदेश में लगभग 1.50 लाख करोड़ की पाइप पेयजल योजना क्रियान्वित करने के लिए उप्र जल निगम को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बदलना आवश्यक हो गया है।

खेती किसानी

नेपियर घास है चारे का विकल्प, दूर होगी दिक्कत

सीतापुर में पशुपालकों को मिल रही मदद, लखनऊ में पशु पालकों को है दरकार

आईपीके, लखनऊः पशु पालकों के सामने सालों-साल कई दिक्कतें आती हैं। इनमें हरा चारा भी प्रमुख है। किसान इसके लिए तमाम दिक्कतें उठाते है। बरसीम, मक्का, ज्वार जैसी फसलों से तीन-चार महीनों तक हरा चारा मिल सकता है, लेकिन जो लंबे समय तक साथ दे उसे भी अब ढूंढ़ निकाला गया है। थोड़ा सा प्रयास करने पर पशु पालकों के लिए नेपियर घास अच्छा विकल्प बन सकता है।

नेपियर घास को रोपने के बाद 4-5 साल तक हरा चारा मिल सकता है। सीतापुर जिले के बिसवां ब्लॉक में ऐसे पौधे लगाए गए हैं। इसके एक पौधे से कई पौधे तैयार हो गए हैं। अब यहां किसानों को साल भर हरा चारा उपलब्ध रहता है। किसानों के बीच यह तेजी से लोकप्रिय भी हो रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों को साल भर हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए नेपियर के लिए उत्साहित करता है। यहां से 3 हजार से भी ज्यादा किसान नेपियर ले गए। नेपियर पशुपालकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसकी खास बात यह होती है कि इसे साल में कभी भी लगा सकते हैं। एक पौधा लगाने पर उसी से सैकड़ों पौधे तैयार किये जा सकते हैं।

मेड़ पर लगा सकते हैं घास

किसान अब नेपियर को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे मेड़ पर लगाकर खेत में दूसरी फसलें लगा सकते हैं। यह 50 दिनों में पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इसमें ज्यादा सिंचाई की जरूरत भी नहीं पड़ती है। गन्ने की तरह दिखने वाले नेपियर घास लगाने के महज 50 दिनों में विकसित होकर अगले 4-5 साल तक लगातार पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत को पूरा कर सकता है। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर नेपियर घास पशुओं के लिए एक उत्तम आहार की जरूरत को पूरा करता है। दुधारू पशुओं को लगातार यह घास खिलाने से दूध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हाइब्रिड नेपियर की जड़ को 3-3 फीट की दूरी पर रोपित किया जाता है। इससे पहले खेत की जुताई और समतलीकरण करने के बाद घास की रोपाई की जाती है और रोपाई के बाद सिंचाई की जाती है। घास रोपण के मात्र 50 दिनों बाद यह हरे चारे के रूप में विकसित हो जाता है। एक बार घास के विकसित होने के बाद 4-5 साल तक कटाई कर इसका इस्तेमाल पशुओं के आहार के रूप में किया जा सकता है।

40 दिन में हो जाती है तैयार

नेपियर घास का उत्पादन प्रति एकड़ लगभग 300-400 क्विंटल होता है। इस घास की खासियत यह होती है कि इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। एक बार घास की कटाई करने के बाद उसकी शाखाएं पुनः फैलने लगती हैं और 40 दिन में वह दोबारा पशुओं के खिलाने लायक हो जाता है। प्रत्येक कटाई के बाद घास की जड़ों के आस-पास हल्का यूरिया का छिड़काव करने से इसमें तेजी से बढ़ोत्तरी भी होती है। वैसे इसके बेहतर उत्पादन के जिए गोबर की खाद का छिड़काव भी किया जाना चाहिए।

खेत की तैयारी और समय

नेपियर घास की रोपाई साल भर की जा सकती है। रोपाई के लिए खेत की जुताई करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। बीज की मात्रा प्रति एकड़ 50 सेमी लम्बी जड़ों की 2-3 गांठों वाले 11,000 टुकड़ों या पौध की प्रति एकड़ जरूरत पड़ती है। टुकड़े का आधा हिस्सा जमीन के ऊपर हवा में और बाकी जमीन के अंदर रहना चाहिए।

जरूरत होने पर करें पानी का छिड़काव

गर्मियों में 10-15 दिन के अंतराल पर व अन्य मौसम में वर्षा के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। कटाइयों की संख्या को जरूरत के हिसाब पर पहली कटाई रोपाई के दो महीने बाद व उसके बाद 45 दिन बाद करनी चाहिए।

ड्रैगन फ्रूट बनेगा किसानों की समृद्धि का जरिया

मुनाफे का सौदा है इसकी खेती

आईपीके, लखनऊः राजधानी के डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में इन दिनों ड्रैगन फ्रूट के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। यह पौधे दक्षिण भारत में उपजाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत के अलावा यूपी में भी इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। डॉक्टर रविशंकर वर्मा इन पौधों को बड़ी लगन के साथ तैयार कर रहे हैं। यहां यह पौधे भी तैयार हो रहे हैं, जो अभी तक दुर्लभ माने जाते रहे हैं। माना जा रहा है कि यह काफी मुनाफे वाले साबित होंगे।

पिछले कुछ दिनों से यहां आर्थिक ढांचा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आर्थिक समृद्धि के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। किसानों की आय दोगुनी कैसे हो ? इस पर जहां सरकार मंथन कर रही है, वहीं किसान वैज्ञानिक, हार्टिकल्चर व कृषि के जानकार कॉलेज स्तर पर भी तैयारी कर रहे हैं। बताया जाता है कि यह पौधा तैयार हो गया तो बड़ा मुनाफा देगा। इसके लिए किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। यह पौधा देखने में काफी आकर्षक है। यह नागफनी के आकार का दिखता है। एक पौधे में अनगिनत फल आते हैं। यह बड़े कीमती होते हैं। किसानों को इन्हें उगाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इनके लिए यहां की जलवायु अनुकूल है। पानी और मिट्टी इन पौधों के लिए अनुकूल है। एक पौधे में तमाम फल लगते हैं और यह बेहद कीमती होते हैं। लखनऊ के मॉल्स में इनकी बिक्री भी होती है। एक फल सौ रुपये तक बिक जाता है।

प्रोफेसर रवि बताते हैं कि यदि किसान ऐसी फसलें उगाएं तो उनकी आमदनी काफी बढ़ सकती है। साथ ही कुछ नया उगाने और नया खाने की परंपरा भी बढ़ जाएगी। किसानों को यहां जल्द ही एक कार्यशाला में तमाम तरह की जानकारियां भी दी जाएंगी। यह उनको आत्मनिर्भर बनाने और आमदनी दोगुना करने में मदद भी करेगी।

डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में उगाया जा रहा ड्रैगन फ्रूट

प्लाटिंग से प्रभावित हो रही खेती

आलू की पैदावार में आ रही गिरावट

आईपीके, लखनऊः राजधानी लखनऊ में आलू की खेती लगातार कम हो रही है। यह बात खुद यहां के किसान स्वीकार रहे हैं। इसका कारण माना जा रहा है शहर में मकानों की संख्या का हर साल बढ़ना। यही कारण है कि साल भर सब्जी में इस्तेमाल किए जाने वाला आलू महंगा भी हो रहा है। किसानों का मानना है कि जब से यहां 88 गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है, किसानों का खेती से मोहभंग हो गया है।

लखनऊ के किसानों को अब प्लाटिंग से ज्यादा लगाव हो रहा है। इसका कारण है कि उनको इसमें ज्यादा लाभ मिल रहा है। एक बार खेत बिक जाने से मोटी रकम हाथ आ जाती है। इससे तमाम काम आसान हो जाते हैं, जबकि खेती में सालों-साल जूझना पड़ता है। अनौरा गांव के किसान 65 वर्षीय देशराज यादव का कहना है कि वह आलू की खेती कर रहे हैं। उनका मुख्य काम भी खेती ही है। वह कहते हैं कि एक दशक पहले अनौरा में खेती का आनंद कुछ और था। घर-घर किसान हुआ करते थे। अब लोगों की जिंदगी जीने का अंदाज बदल गया। ट्रैक्टर चलाने वाले कार में घूम रहे हैं। लखनऊ कभी हजरतगंज में हुआ करता था। अब वह अनौरा को क्रास कर चुका है। यहां तक कि जब से 88 गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है, किसानों की बन पड़ी है। जमीनों पर सड़कें और मकान बनाकर खुद बेच रहे हैं या फिर महंगी दामों पर जमीन बेच रहे हैं। समझदार लोग महंगे खेत बेचकर दूर इलाके में खरीद लेते हैं। वह सस्ते में मिल जाते हैं। कुछ लोग इसे बेचकर दुकान और किराए के मकान बना रहे हैं। इस चालाकी में किसानी पीछे छूट रही है। फसलों का उत्पादन घट रहा है। देशराज कहते हैं कि वह ज्यादातर आलू ही बोते हैं। मिट्टी की मेड़ और नाली बनाकर समय-समय पर पानी और खाद देते रहते हैं। वह बताते हैं कि पानी का संकट हर क्षेत्र में है। सरकार का ध्यान भी नहर और नालियों पर नहीं है। इसमें भी प्लाटिंग ही सबसे बड़ा कारण है। जहां खेत बिक गए और प्लाटिंग हो गई, वहां नालियां भी अवरुद्ध हो गईं। कुछ मिलाकर खेत कम हो रहे हैं। इससे फसल भी घट रही है।

किसान देशराज यादव

अब गुलजार होंगी फूलों की बगिया

कोरोना के बाद फिर जोर पकड़ रही इसकी खेती

आईपीके, लखनऊः फूल अब लोगों की जरूरत बनते जा रहे हैं। इसके बिना शादी, ब्याह, समारोह अधूरे रह जाते हैं। फूलों की खेती में बीते साल कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन कोरोना महामारी में नियंत्रण के बाद से इसकी खेती में फिर बहार आने लगी है। इसकी खेती में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को फूलों के बीज और पौधों के कलम देने का वादा किया है।

बागवानी से किसानों को आय दोगुनी करने के साथ ही पर्यावरण स्वच्छ करने में काफी मदद मिलेगी। यह बात कुछ लोग जानते भी थे कि बागवानी के साथ फुलवाड़ी भी तैयार की जा सकती है। इसके लिए पिछले वर्ष 2019 में बागवानी मिशन चलाया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस पर काम रुक गया। किसानों को फूलों की खेती करने से उनकी आय भी बढ़ेगी। फूलों की कमी के कारण ही लोग आर्टिफिशियल झालर का इस्तेमाल करते हैं। अब जनपदवार लक्ष्य निर्धारित कर समय से खेती करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्यान विभाग एक हेक्टेयर फूलों की खेती करने पर किसान को 70 फीसद तक अनुदान देता है।

पौधों पर भी मिलता है अनुदान

एक हेक्टेयर गेंदा की खेती करने पर 40 हजार रुपये का खर्च आता है। गुलाब की खेती में एक लाख रुपये का खर्च आता है। किसान को पौधों पर अनुदान पाने के लिए उन्हें खरीदना होता है और उसका बिल उद्यान विभाग में जमा करना होता है। इसका अनुदान किसान के खाते में पहुंचाया जाता है।

फूलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित

अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 5 हेक्टेयर का लक्ष्य बताया गया है। किसानों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह एक निश्चित भूमि पर ही खेती करें। इसमें वह गेंदा और गुलाब लगाएं। यह जानकारी उद्यान विभाग को देनी होती है।

ग्लेडियोलस की खेती को बढावा

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ग्लेडियोलस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। 90 दिन में यह पौधे तैयार हो जाते हैं। इनकी एक स्ट्रिक 8-10 रुपये में बिकती है।

उत्पादन से ज्यादा है खपत

जनपद में गेंदा के फूल का उत्पादन उतना नहीं है, जितना कि प्रतिदिन खपत है। यहां 100 क्विंटल फूलों की खपत रोज है। बाजार में 80 रुपये प्रति किलो की दर से बिक्री हो जाती है। गुलाब के फूल का उत्पादन कम है। यह बाजार में 100-150 रुपये प्रति किलो तक बिकता है।

इन स्थानों पर बिकते हैं पौधे और फूल

आलमबाग में दुबग्गा रोड, आनंद नगर में उद्यान रोड, बांसमंडी चौराहा, राणा प्रताप मार्ग, निशातगंज चौराहा, कैंपवेल रोड, दुबग्गा, मलिहाबाद, रहमानखेड़ा, छितवापुर, बंगलाबाजार, तेलीबाग चौराहा, चौक चौराहा, डंडहिया में बड़ी संख्या में फूल वाले पौधे और फूलों की बिक्री होती है।

शौचालय निर्माण में बजट का 'अड़ंगा'

सभासद लगा रहे भेदभाव का आरोप, सर्वेक्षण से पहले काम पूरा होना है टेढ़ी खीर

आईपीके, लखनऊः राजधानी लखनऊ में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जोरों पर अभियान चल रहा है। इसमें जिला प्रशासन और नगर निगम अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। यह सर्वेक्षण मार्च में होना है, इसलिए शहर में उन सभी खामियों को फरवरी में ही दूर कर लेना है जो गंदगी की पहचान हैं। वह राजधानी की गरिमा के खिलाफ भी हैं, लेकिन यह काम केवल पॉश इलाकों में ही किया जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जो नगर निगम के बजट पर ही आश्रित हैं। शहर के कई क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां दी गई हैं। यही नहीं तमाम इलाकों में स्वच्छ शौचालय भी बनवाए जा रहे हैं। इसके विपरीत कई इलाकों में गंदगी की भरमार है। इनमें टूटे हुए पुराने शौचालय हैं।

नगर निगम से मांग की गई थी, डिमांड भी भरा गया था, लेकिन बजट नहीं मिल सका। ये हालात तब हैं जब दिन भर अधिकारी केवल स्वच्छ लखनऊ-स्वस्थ की डींगे हांकते हैं। कई वार्डों में पार्षद भेदभाव का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि शौचालय तो दूर, कूड़ा उठाने की गाड़ी तक नहीं मिल सकी है। राजधानी में करीब 400 शौचालय की आवश्यकता बताई जा रही है, जबकि कुछ चौराहों पर ही इनका निर्माण किया जा सका है।

नगर निगम लखनऊ का 2020-21 के लिए बजट एक अप्रैल को जारी किया गया था, जिसे 7 मार्च को पास कर दिया गया था। इस बजट में शहर के पॉश इलाकों में शौचालय की मरम्मत, महिला शौचालय का निर्माण भी शामिल था। कहा गया था कि गंदगी किसी हाल में दिखनी नहीं चाहिए। मरम्मत कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये तत्काल पास किए गए थे, जबकि कई काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत होने थे। मार्च से ही तत्कालीन नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी और महापौर संयुक्ता भाटिया में अनबन भी शुरू हो गई थी। इसके चलते नगर निगम के पास किए गए बजट का 50 फीसदी रोक दिया गया। यह वह दौर था, जब कोरोना महामारी में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई थी।

नगर निगम में पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अरविंद्र को टूटे और खराब शौचालयों के जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। उनका कहना है कि शहर के कई इलाकों में अति खराब पड़े शौचालय आधुनिक किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि नगर निगम की ओर से बनाए जाने वाले शौचालय कई जगह पर दिख रहे हैं। कोरोना काल में काम रुका हुआ था, इसलिए प्रगति देखने को नहीं मिल रही है।

खास इलाकों पर दिया जा रहा ध्यान

राजधानी को स्वच्छता मिशन में अच्छे अंक दिलाने के लिए पूर्व के नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी काफी सक्रिय रहे थे। बताया जाता है कि केंद्र सरकार ने जिस इज्जतघर नाम को सिलेक्ट किया था, वह उनका ही दिया हुआ था। इस मिशन को नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी आगे बढ़ा रहे हैं। यह बात अलग है कि वह केवल कुछ खास इलाकों पर ही ध्यान दे रहे हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन के योगदान से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई क्षेत्रों में शौचालय बनाए जा रहे हैं। इनमें जहां महिलाओं को विशेष सुविधा दी जाएगी। यह काम भी फरवरी तक पूरा कर लेना है। जो मिशन नगर निगम के अधिकारी और जिला प्रशासन चला रहे हैं वह कितना पूरा होगा, यह तो देखने वाली बात होगी।

सभासदों की सुनिए

हजरतगंज क्षेत्र और उससे जुड़े वार्ड में करीब 25 शौचालय के लिए काम चल रहा है। यहां के सभासद नागेंद्र सिंह चौहान कहते हैं कि स्वच्छ स्लोगन के लिए काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत यहां का विकास जोरों पर है। करीब 25 शौचालय आधुनिक हो रहे हैं। यह स्वच्छता अभियान में लखनऊ को अच्छे अंक दिलाने में मददगार होंगे। दूसरी ओर आचार्य नरेंद्र देव वार्ड से सभासद राजकुमार सिंह काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि यह विकास वहीं हो रहा है, जहां के पार्षद सत्ताधारी पार्टी के हैं। जो बजट एक जनवरी को पास होना था, वह फरवरी तक नहीं मिला है। उनका कहना है कि क्षेत्र में सफाई दूर करने के लिए डस्टबिन तक नहीं मिले। यहां कूड़ा उठाने की गाड़ी तक की कमी है। अनदेखी का आलम यह है कि कई क्षेत्रों में शौचालय बनाए जाने हैं, लेकिन काम अड़ंगे में फंसा हुआ है। सभासदों का पूरा बजट अभी तक पास ही नहीं हुआ है। कई सभासद महापौर पर भी क्षेत्र से भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं।

सभासद जमीन दे रहे थे और शौचालय की मांग भी कर रहे थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर दी गई। स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी का भी नगर निगम में बंटवारा है।

बोले जिम्मेदार

▪ स्वच्छता अभियान अर्चना द्विवेदी देख रही हैं। उनके पास ही इसकी जिम्मेदारी है।

राकेश कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त

▪ स्वच्छता अभियान में सभी का सहयोग लिया जा रहा है। भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है। लखनऊ का नाम होगा तो हर किसी का सिर ऊंचा होगा।

अर्चना द्विवेदी, अपर नगर आयुक्त

हमारी सुरक्षाः मोबाइल हाथ में, 1090 साथ में

महिला सुरक्षा के लिए डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम का शुभारंभ

आईपीके, लखनऊः उत्तर प्रदेश वीमेन पॉवरलाइन '1090' ने एक डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम हमारी सुरक्षा का शुभारंभ किया। जिसमें '1090' डिजिटल रूप से लोगों तक पहुंचता है, जागरूकता पैदा करता है और डिवाइस इंटीग्रेशन समाधानों के लिए डेटा संकेतों को कैप्चर करता है।

राजधानी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में एडीजी नीरा रावत ने उत्तर प्रदेश में डिजिटल चक्रव्यूह (महिला सुरक्षा के लिए 360 डिग्री इकोसिस्टम) के लिए एक डिजिटल आउटरीच रोडमैप साझा किया। उन्होंने डिजिटल आउटरीच को लागू करने के फायदे बताते हुए आउटरीच के पारंपरिक तरीकों की कमियों की भी बात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों में जागरूकता पैदा करने के वृहद कार्य को अंजाम देने के लिए क्रॉस चैनल डिजिटल रणनीति के बारे में डेटा वैज्ञानिकों की एक टीम का उल्लेख किया। इस टीम की रणनीति ग्रामीण महिलाओं के साथ जुड़ाव, साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग द्वारा अपराधियों को लक्ष्य करने, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने, सामुदायिक

भागीदारी को बढ़ावा देने और सामान्य लोगों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करने में सहायता करेगी। उन्होंने संगठन के ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यों के बीच एकीकरण पर जोर दिया। '1090' में पर्याप्त तकनीकी शक्ति है और अब सेवाओं की बेहतरी के लिए 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'मशीन लर्निंग' जैसी तकनीकों को अपनाने के लिए चुना गया है। उन्होंने बताया कि फेसबुक का उपयोग कर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और साथ ही फेसबुक प्रमोशन के अपने पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों को भी साझा किया। कार्यक्रम का समापन शंखध्वनि से किया गया।

बारिश न होने से किसान मायूस

आईपीके, लखनऊः इस बार गेहूं की बुवाई करने वाले किसान मायूस हैं, इसका कारण है बारिश का न होना। किसानों का मानना है कि कितना भी पानी खेतों में लगा दिया जाए, बारिश के पानी से ही दाना बढ़ता है। मौसम विज्ञान 4-5 फरवरी को बारिश की संभावना जता रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। 5 फरवरी की रात हवा के साथ हल्की बूंदा-बांदी हुई, लेकिन खेत नम भी नहीं हो सके। पिछले हफ्ते दो-तीन दिनों से हो रही बूंदा-बांदी से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बरसात से किसानों की गेहूं की फसल पर अच्छा प्रभाव दिखाई दिया। कैराना क्षेत्र के किसानों का मानना है कि इस मौसम में बारिश का होना गेहूं की फसल के लिये अमृत समान है। सब्जी की फसल को भी बारिश का लाभ मिल रहा है। किसानों का मानना है कि यदि और बारिश होती है तो सब्जी की फसल को नुकसान हो सकता है। किसान अशोक भुर्जी एवं महेन्द्र यादव ने बताया कि बारिश से गेहूं की पैदावार बढ़ जाती है। इस समय फसल को सिंचाई की आवश्यकता है।

सिर्फ 12 डॉक्टरों के भरोसे चल रहा भाऊराव देवरस सिविल अस्पताल

आईपीके, लखनऊः हजारों मरीजों के इलाज का जिम्मा संभाल रहा राजधानी का भाऊराव देवरस महानगर सिविल अस्पताल सिर्फ 12 डॉक्टरों के भरोसे ही चल रहा है। तमाम चिकित्सकों के पद खाली होने की वजह से यहां पर आने वाले मरीजों को मुकम्मल इलाज नहीं मिल पा रहा है तो तमाम मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। उपेक्षा के चलते अस्पताल पर बना जनऔषधि केंद्र भी हाथी दांत साबित हो रहा है।

इंडिया पब्लिक खबर ने मंगलवार 9 फरवरी को सिविल अस्पताल की पड़ताल की तो स्वास्थ्य विभाग के दावों की कलई खुल गई। शहर में महानगर जैसे महत्वपूर्ण इलाके में स्थापित भाऊराव देवरस सिविल अस्पताल के ऊपर हजारों मरीजों के इलाज का जिम्मा है। यहां पर प्रतिदिन ओपीडी में ही 1,100 से ज्यादा मरीजों का आना होता है, पर पिछले 4 सालों से यहां पर चिकित्सकों के तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। इतने बड़े अस्पताल पर सिर्फ 12 डॉक्टरों की ही तैनाती है, जिससे मरीजों का इलाज करने में खासी परेशानी झेलनी पड़ रह है। यहां के

सीएमएस आरपी सिंह की मानें तो डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर 4 सालों से मांग की जा रही है, लेकिन यह मांग सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह गई है। यही नही अस्पताल में कई चिकित्सकों द्वारा बाहर से मरीजों को दवाएं लिखी जा रही हैं, जिससे उन्हें निजी मेडिकल स्टोरों के हाथों लुटने को मजबूर होना पड़ रहा है।

अभी तक नही संचालित हो पाए 100 बेड

सिविल अस्पताल में करीब 4-5 वर्ष पहले ही बेड का विस्तार किया गया था, लेकिन अभी तक यह बेड संचालित नही हो सके हैं। अभी तक सिर्फ 70 बेडों की ही व्यवस्था सुनिश्चित हो पाई है। इसको लेकर सीएमएस बताते हैं कि मैनपॉवर की कमी की वजह से अभी तक सभी बेडों को संचालित नही किया जा सका है। शासन की ओर से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए मंजूरी दे दी गई है, जल्द ही इसके संचालित होने की उम्मीद है। बताया कि यहां जल्द ही इमरजेंसी कॉम्पलेक्स भी बनेगा और मॉड्यूलर ओटी का निर्माण भी शुरू हो गया है। जिससे जल्द ही मरीजों को ऑपरेशन की बेहतर सेवाएं मिलने लगेंगी।

ओपीडी में आते हैं प्रतिदिन 1,100 से ज्यादा मरीज

अस्पताल पर हर दिन ओपीडी में 1100-1500 मरीजों का आना होता है।

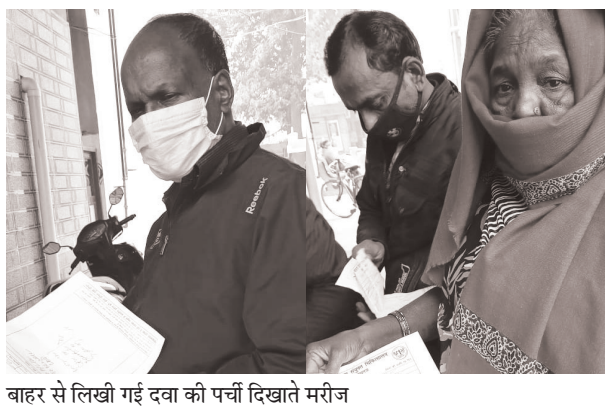

बाहर से लिखी गई दवा की पर्ची दिखाते मरीज

कोरोना के समय तो मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद मरीज काफी संख्या में यहां आ रहे हैं। चिकित्सकों की कमी की वजह से तमाम मरीजों को यहां से निराश होकर वापस लौटना पड़ता है।

बाहर की लिखी जा रही दवाएं

चिकित्सकों की कमी के अलावा यहां पर आने वाले मरीजों को पर्याप्त मात्रा में दवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। तमाम मरीजों को अस्पताल में दवाएं न होने की बात कहकर चिकित्सक बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। जिसकी वजह से मरीजों व तीमारदारों को निजी मेडिकल स्टोरों पर लुटना पड़ रहा है। अस्पताल पर मौजूद सुदामा व रामशंकर के हाथ में अस्पताल के पर्चे के साथ एक और पर्चा भी था, पूछने पर उन्होंने बताया कि यह दवाएं बाहर से लेनी हैं। हालांकि जिम्मेदार अस्पताल पर पर्याप्त दवाओं के भंडार होने का दावा कर रहे हैं।

शोपीस साबित हो रहा जनऔषधि केंद्र

अस्पताल में आने वाले मरीजों को सस्ते दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया जनऔषधि केंद्र

बंद पड़ा जनऔषधि केंद्र

हाथी दांत साबित हो रहा है। केंद्र के बंद होने की वजह से मरीजों को तमाम दवाएं महंगे दामों पर बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। इसको लेकर तमाम बार मरीजों ने शिकायत भी की, पर इसको लेकर जिम्मेदार उदासीन बने हुए हैं।

मरीजों के लिए नई सुविधाओं का हो रहा विस्तार

चिकित्सकों की कमी और अन्य अव्यवस्थाओं के अलावा यहां पर मरीजों के लिए सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। अस्पताल पर जल्द ही इमरजेंसी सेवा में 10 बेड लगाए जाएंगे। मरीजों के स्वास्थ्य को मॉनिटर करने के लिए जगह-जगह कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सुविधा की जाएगी। इसके अलावा 10 बेड का अलग से महिला विंग भी बनाने की व्यवस्था बन रही है। हाल ही में अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने के लिए भी बजट मिल गया है।

मिली शिकायत तो होगी कार्रवाईः सीएमएस

इमरजेंसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू हो गया है। इमरजेंसी के मद्देनजर सीटी स्कैन मशीन भी मांगी गई है, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन की डिमांड भी की गई है। जल्द ही मरीजों को 100 बेड की सुविधा मिलेगी। चिकित्सकों की कमी की वजह से समस्या है, उम्मीद है जल्द ही वह दूर होगी। यदि किसी चिकित्सक द्वारा बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं, तो जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

निर्बाध बिजली के लिए 31 मार्च से पहले पूरे करें कामः ऊर्जा मंत्री

आईपीके, लखनऊः उपभोक्ताओं को गर्मियों में निर्बाध बिजली के लिए सभी कार्य आगामी 31 मार्च तक पूरे कर लिए जाएं। उच्चाधिकारी अपने स्तर से भी तैयारियों को लेकर डिस्कॉम्स के समर प्लान की समीक्षा करें, साथ ही जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर भी कार्रवाई करें। जूनियर इंजीनियर से लेकर चेयरमैन तक की परफॉर्मेंस को एसीआर से जोड़ा जाए।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह निर्देश पॉवर कॉर्पोरेशन की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। साथ ही सुधारों के लिए 100 दिन की कार्ययोजना का भी लक्ष्य तय किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और राजस्व से जुड़े सभी लक्ष्यों का निर्धारण जेई स्तर तक सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आईटी टूल्स का भी उपयोग किया जाए, जिससे प्रत्येक जेई को लक्ष्य डैशबोर्ड पर दिखे। ऊर्जा मंत्री ने समर प्लान की तैयारियों की सतत निगरानी के निर्देश अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्युत कनेक्शन तय समय में जारी कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि

डिस्कनेक्शन कोई विकल्प नहीं है, इसलिए बकाएदारों को भुगतान के लिए प्रेरित करें। उपभोक्ताओं को सही और समय पर बिल मिले और उसके भुगतान की सुविधा गांव या मोहल्ले में ही दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जन सुविधा केंद्र, स्वयं सहायता समूह, सरकारी राशन की दुकान के जरिए बिल जमा कराया जाए।

गलत बिल झटपट पोर्टल पर होंगे सही

ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि झटपट पोर्टल को और उपभोक्ता हितैषी बनाया जाए। पोर्टल पर लोड बढ़ाने-घटाने की सुविधा, स्थान परिवर्तन की सुविधा, नाम परिवर्तन की सुविधा के साथ ही गलत बिलों को ठीक कराने की शिकायत और सुधार की भी सुविधा मिले। इसके लिए पोर्टल में आवश्यक तकनीकी सुधारों पर 100 दिन के भीतर काम कर लिया जाए।

बिजली इंजीनियरों ने किया पीएम के बयान का स्वागत

ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आईएएस के सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्ति पर सवाल खड़े करने और इसे अनुपयोगी बताने के बयान का स्वागत किया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से ऊर्जा निगमों में सीएमडी और प्रमुख सचिव ऊर्जा के पद पर ऊर्जा निगमों के योग्य व अनुभवी अभियंताओं की तैनाती किए जाने की मांग की है। ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे, अभियंता संघ के अध्यक्ष वीपी सिंह और महासचिव प्रभात सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए सार्वजनिक उपक्रमों और तकनीकी विभागों में आईएएस की नियुक्ति को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है।

गैस की बढ़ती कीमतों ने बिगाड़ा घर का बजट

राम भरोसे गैस सब्सिडी, उपभोक्ता परेशान

आईपीके, लखनऊः लगातार बढ़ रहे घरेलू सिलेंडरों की कीमत ने लोगों के घर का बजट पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। आए दिन बढ़ रहे दाम को लेकर गृहणियों में काफी रोष व्याप्त है और वह सरकार को कोस रही हैं। यही नही घरेलू सिलेंडरों में मिलने वाली सब्सिडी भी राम भरोसे ही है, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है।

बता दें कि बीते कुछ माह में महंगाई दर में काफी अधिक वृद्धि देखने को मिली है। घरेलू कंपनियों ने एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया है। सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर (14.2) की कीमत में 25 रूपये का इजाफा होने से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की जनता पर इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है। चालू माह में दो बार गैस के दाम बढ़ने से 732 रूपये प्रति सिलेंडर से 757 रूपये पर पहुंच गया है। दिसम्बर 2020 में घरेलू गैस सिलेंडर में एकमुश्त 100 रूपये दाम बढ़ने से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है।

घरेलू सिलेंडर के दाम में ऐसे आया उछाल

दिनांक	कीमत	बदलाव
फरवरी 2021	757	25 बढ़े
जनवरी 2021	732	----
दिसम्बर 2020	732	----
नवम्बर 2020	632	100 बढ़े
अक्टूबर 2020	632	----
सितम्बर 2020	632	07.50 घटे
अगस्त 2020	639	----
जुलाई 2020	639	03.50 बढ़े
जून 2020	636	47.00 बढ़े

(पिछले 8 माह में सिलेंडर के दाम में 121 रूपये की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है, जबकि सब्सिडी में भारी गिरावट दर्ज की गई है।)

खाते में नहीं आ रही सब्सिडी

लॉकडाउन के समय गैस सिलेंडरों की मांग बरकरार थी। कीमतें भी बढ़ रही थीं, लेकिन सब्सिडी आ रही थी। पिछले कई महीनों से ग्राहकों के खाते में सिलेंडर की सब्सिडी का पैसा भी नहीं आ रहा है। इसके बाद जुलाई से सब्सिडी जमा नहीं की गई। हर बार जब लोग सिलेंडर बुक करते हैं, तो वे सब्सिडी का इंतजार करते हैं। सरकार ने इसके पीछे कारण यह बताया था कि गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के कारण सब्सिडी राशि को समायोजित किया गया है। सिलेंडर 732 रुपये हो गया है और 35 रुपये सब्सिडी के रूप में खाते में जमा किए जा रहे थे। अब जबकि 25 रूपये सिलेंडर के दाम और बढ़ गए हैं, तो देखना होगा सरकार सब्सिडी के रूप में कितना धन ग्राहकों के बैंक खातों में जमा करवाती है। इसकी शिकायत करने पर भी उसका निदान नही हो पा रहा है। जिसको लेकर उपभोक्ता काफी परेशान हैं।

गृहणियों ने उठाए सवाल

आकांक्षा | ममता सिंह | अपर्णा | संतोष कुमारी

▪ सरकार गैस के दाम तो बढ़ा रही है, लेकिन लोगों को कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसका किसी को पता नहीं है। रसोई गैस के दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ रहा है। इतना ही नही पेट्रोल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं।

आकांक्षा, जानकीपुरम, लखनऊ

▪ गैस सिलेंडर के दाम लगातार ही बढ़ रहे हैं, जिससे हम गृहणियों के किचन का बजट बिगड़ गया है। मध्यमवर्गीय परिवार पर जब हर तरफ से महंगाई की मार पड़ रही हो तो सरकार को चाहिए कि इसे कम करने के लिए ठोस कदम उठाए।

ममता सिंह, नंदना, बक्शी का तालाब, लखनऊ

▪ दाम बढ़ने से जहां आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है, वहीं हमारा तो रसोई का बजट बिगड़ गया है। उस पर सब्सिडी भी न के बराबर देकर सरकार ने हम मध्यमवर्गीय परिवार की रीढ़ ही तोड़ दी है। 10-20 हजार की आमदनी वाले परिवारों के लिए तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है।

अपर्णा, इंदिरा नगर

▪ गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। इस बार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। सब्सिडी भी सिर्फ 35 रूपये दी जा रही। गैस की कीमत 757 रूपये हो गई है, जो परेशान करने वाला है।

संतोष कुमारी, विशाल खंड-1, गोमतीनगर

खत्म हुआ इंतजार, स्कूल हुए गुलजार

स्कूल खुलने से अभिभावकों के साथ बच्चों में खुशी, विद्यालय प्रबंधनों ने भी बचाव के किए खास इंतजाम

आईपीके, लखनऊः कोरोना के चलते पिछले 11 माह से राजधानी के स्कूलों में छायी वीरानगी विगत 10 फरवरी को दूर होती दिखी। स्कूल प्रशासन व अभिभावकों में खुशी तो छात्र-छात्राओं में उत्साह देखने को मिला। स्कूल अभी पूरी तरह से तो नहीं खुले हैं, लेकिन कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्कूलों को सशर्त खोल दिया गया है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूलों को एक मार्च से खोलने के निर्देश आ चुके हैं।

विद्यालय प्रबंधनों से बात करने पर पता चला कि राजधानी के कुछ स्कूल तो खुल चुके हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन परीक्षाएं चल रहीं हैं। जिसकी वजह से उन्होंने अभी स्कूल न खोलने का निर्णय लिया है। अलीगंज सेक्टर क्यू स्थित सेंट एंटोनी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चों की ऑनलाइन परीक्षाओं के चलते और सभी अभिभावकों से पूछ कर स्कूल खोलना है, अतः हम स्कूल अगले सत्र से ही खोलेंगे। जिन स्कूलों ने सरकार की गाइडलाइन के तहत स्कूल खोलने का निर्णय लिया है उसमें से एक निराला नगर स्थित ब्राइटलैंड स्कूल है। स्कूल के इंचार्ज अमित सिंह ने बताया कि स्कूल खोलने से पहले हमने स्कूल को पूरी तरह सेनेटाइज करवाया है और क्लास को रोज दो बार सेनेटाइज करवाते हैं।

अभिभावकों की सुनिए

▪ कोरोना की वैक्सीन आ गई है और बचाव के उपाय अपनाते हुए अब हमें कोरोना के भय से उबरना होगा। पिछला

पूरा साल बच्चों का खराब हो चुका है। ऑनलाइन पढ़ाई से थोड़ी रिकवरी समझी जा सकती है, लेकिन जो पढ़ाई का माहौल स्कूल में मिलेगा, वह ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं मिल पाता। स्कूल में की गई तैयारी से मैं पूरी तरह सहमत हूं, मेरी बेटी भी अपनी सहेलियों से मिलने को लेकर उत्साहित हैं।

प्रियंका चौरसिया कपूरथला

▪ स्कूल का खुलना एक सही कदम है। मेरा बेटा आर्नव कक्षा चार में

ब्राइटलैंड स्कूल में पढ़ता है। ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षक और अभिभावक दोनों को ही उनकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पा रहा था। दोनों ही पढ़ाई को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। जो पढ़ाई स्कूल में हो सकती है वह ऑनलाइन नहीं हो सकती। फिर भी एक नई तकनीकी सीखना भी अलग तरह का अहसास रहा। मैं स्कूल को खोले जाने और स्कूल की तैयारियो से पूरी तरह संतुष्ट हूं।

रीना वर्मा, बक्शी का तालाब

▪ कोरोना लगभग खत्म हो चुका है। अब स्कूल खुलना चाहिए। बस हम सब

अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है और बच्चों को भी इस बीमारी की गम्भीरता अब तक समझ आ चुकी है। स्कूल भी इसे लेकर पूरी तरह मुस्तैद हैं। सरकार भी अपनी तरफ से कदम उठा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बच्चों को स्कूल में सुरक्षित माहौल मिलेगा।

रश्मि श्रीवास्तव, अलीगंज

स्कूल मैनेजमेंट भी तैयार

▪ हमें करीब 80 फीसदी अभिभावकों की सहमति मिल चुकी है और विद्यालय आने वाले छात्र-छात्राओं के अलावा जो छात्र स्कूल आ पाने में किसी भी वजह से असमर्थ हैं, उनके लिए हमने उसी समय पर ऑफलाइन क्लासेज के साथ ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था भी की है। क्योंकि सरकार के निर्देशानुसार हम एक कक्षा में 15 बच्चे ही बिठा रहे हैं, इसलिए एक बच्चे का टर्न स्कूल आने का केवल दो बार ही हो पाएगा। उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेज साथ-साथ चल रही हैं।

रीना मानस, निदेशक, ब्राइटलैंड स्कूल, निराला नगर

▪ सुबह स्कूल लगने से पहले व स्कूल में छुट्टी के बाद दिन में दो बार क्लास को सेनेटाइज किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही बच्चों को क्लास में बैठाया जा रहा है। बच्चों को भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने की सलाह दी गई है। स्कूल ने खुद भी इसकी व्यवस्था की है, लेकिन बच्चों को अपना खुद का सैनेटाइजर और मास्क लाने को कहा गया है। बच्चों को कोरोना वायरस की गंभीरता के बारे में भी शिक्षित किया गया है और बार-बार हाथ को सेनेटाइज करने की सलाह भी दी गई है।

नीलम शुक्ला, प्रिंसिपल, रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल विकास नगर

'खुदा खैर करे' की प्रस्तुति 19 को

लखनऊः नौशाद संगीत डेवलपमेंट सोसायटी की ओर से संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आत्माराम सावंत के लिखे मूल मराठी नाटक 'खुदा खैर करे' का श्रीधर जोशी द्वारा किए हिन्दी रूपांतरण का मंचन प्रसिद्ध रचनाकार हसन काजमी के निर्देशन में किया जा रहा है।

सोसायटी के अध्यक्ष अतहर नबी ने बताया कि संगीत नाटक अकादमी गोमतीनगर स्थित वाल्मीकि रंगशाला में शुक्रवार 19 फरवरी की शाम होने वाले इस मंचन से पहले मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डॉ. अनीस अंसारी और विशिष्ट अतिथि पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी व डॉ. विक्रम सिंह संस्कृति व रंगक्षेत्र में कार्यरत विजय वास्तव, डॉ. अनिल रस्तोगी, राजा अवस्थी जैसे लोग उनके योगदान के लिए नौशाद सम्मान से अलंकृत करेंगे। इस असवर पर प्रस्तुत होने वाले लेखक श्रीधर जोशी दूरदर्शन और लखनऊ रंगमंच से जुड़े रहे और 'चेल्काश' जैसी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। उनके द्वारा रूपांतरित इस हास्य नाटक को 30 दिन की गहन प्रशिक्षण नाट्य कार्यशाला में तैयार किया जा रहा है। कार्यशाला में रंगकर्म के विभिन्न पक्षों पर विशेषज्ञ काम कर रहे हैं।

महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह का होगा आयोजन

गाजीपुरः जिलाधिकारी एम. पी. सिंह ने शासन के निर्देश पर आगामी 16 फरवरी को जनपद में महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह का आयोजन कराए जाने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में सभी महत्वपूर्ण शहीद स्थल एवं शहीद स्मारकों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राजेश कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजीपुर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि शासन द्वारा जारी उपर्युक्त दिशा-निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन एवं तद्नुसार कार्यक्रम आयोजित कराया जाए। बसंत पंचमी के दिन महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह पर शहीद स्थलों एवं शहीद स्मारकों पर भव्य कार्यक्रम तथा स्थलों की गरिमापूर्ण सजावट की जाए। शहीद स्थलों व शहीद स्मारकों पर सांय 05:30 से 06:00 बजे तक पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रधुन तथा राष्ट्रभक्ति गीतों पर बैंड वादन किया जाए। शहीद स्थलों एवं शहीद स्मारकों पर सायं 06:30 बजे दीप प्रज्जवलन का कार्यक्रम किया जाए एवं विद्युत झालरों व रंगीन प्रकाश से शहीद स्मारकों को प्रकाशमान किया जाए।

अब यूपी करेगा 'टमाटर महोत्सव' की मेजबानी

व्यंजन, पेय व अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने की तैयारी | 'बनारसी' टमाटर चाट होगा मुख्य आकर्षण

वाराणसीः उत्तर प्रदेश में फरवरी फल और सब्जी के त्यौहारों के महीने के रूप में उभर रहा है। स्ट्रॉबेरी, शकरकंद और ड्रैगन फ्रूट के त्यौहारों के बाद, योगी आदित्यनाथ सरकार टमाटर, उसके व्यंजन, पेय और विभिन्न उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में 'टमाटर महोत्सव' की मेजबानी करने वाली है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, 'टमाटर महोत्सव' की तारीख को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

महोत्सव में प्रसिद्ध 'बनारसी टमाटर चाट' कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा। संभागीय आयुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि टमाटर महोत्सव आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। महोत्सव के आयोजन स्थल और तिथियों को जल्द ही घोषित किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा कृषि, बागवानी, संस्कृति, पर्यटन विभागों की भूमिकाओं को निर्धारित करने के लिए वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वाराणसी नगर निगम और वाराणसी विकास प्राधिकरण के साथ बैठकें कर हैं। जिला बागवानी अधिकारी, संदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि टमाटर और प्याज दो सब्जियां हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर कीमतों में उतार-चढ़ाव होते हैं। जब कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो बड़े पैमाने पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं, लेकिन ज्यादातर टमाटर की कीमत नहीं बढ़ती है और किसान इसे 3 रुपये से 10 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने के लिए मजबूर होते हैं। टमाटर उत्पादकों के लिए जोखिम भी अधिक है क्योंकि यह खराब हो जाता है और इसे लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है।

खपत बढ़ाने में करेगा मदद

श्री गुप्ता ने बताया कि मोटे अनुमान के अनुसार, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली के नौगढ़ बेल्ट, गाजीपुर और वाराणसी में 5,000 हेक्टेयर में टमाटर की खेती की जाती है और औसतन 350 क्वि. हाइब्रिड टमाटर का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का एक अच्छा कदम है। टमाटर की स्थानीय और औद्योगिक खपत बढ़ाने में मदद करेगा, जो किसानों के लिए अच्छी कीमत सुनिश्चित करेगा।

इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सुनिए

टमाटर महोत्सव को करवाने का जिम्मा जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को सौंपा गया है, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गर्ग ने कहा कि यह एक अनूठा कार्यक्रम होगा। गृहणियां और मास्टर शेफ अपने स्वयं के व्यंजन पकाएंगे। जबकि होटल, रेस्तरां और विक्रेता भी अपने टमाटर से बने व्यंजन का प्रदर्शन करेंगे। यह कार्यक्रम कृषि उद्योगों को आकर्षित करने पर केंद्रित होगा।

पूर्व सांसद तबस्सुम, विधायक नाहिद पर लगा गैंगस्टर एक्ट

बोलीं पूर्व सांसद, आवाज उठाने पर बनाया जा रहा निशाना

शामलीः कैराना से पूर्व सांसद तबस्सुम हसन (50) और समाजवादी पार्टी से उनके विधायक बेटे नाहिद हसन (32) सहित 38 अन्य समर्थकों के खिलाफ शामली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कैराना पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में विधायक को गैंग लीडर बताया गया है। कैराना के एसएसओ प्रेमवीर राणा द्वारा दर्ज प्राथमिकी में दावा किया गया है कि इलाके में इस गैंग का आतंक फैला हुआ है और डर के मारे लोग इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। इस बीच तबस्सुम हसन ने कहा कि यह एफआईआर उनके खिलाफ रची गई एक साजिश है। आम आदमी के लिए चिंता जताने और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे लड़ने के लिए हम कानून की मदद लेंगे। साल 2018 के उपचुनाव में राष्ट्रीय लोक दल की तबस्सुम हसन 2014 के बाद से लोकसभा में प्रवेश करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली मुस्लिम उम्मीदवार बनीं थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी मृगांका सिंह को हराया था। 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने मृगांका के पिता और भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह को हराया था, तब वह बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ थीं। हालांकि साल 2019 के चुनाव में भाजपा के प्रदीप चौधरी ने उन्हें मात दे दी। तीन बार सांसद और दो बार विधायक रह चुके उनके पति मुनव्वर हसन 2004 में लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन 2008 में एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। कैराना से दो बार विधायक रह चुके हसन के बेटे नाहिद को जनवरी, 2020 में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी।

दलितों, पिछड़ों के साथ हो रहा अत्याचारः डॉ. राजपाल

प्रयागराजः घूरपुर थाना क्षेत्र के बसवार गांव में विगत 4 फरवरी को पुलिस द्वारा निषाद समाज के लोगों के ऊपर किए गए अत्याचार, उनकी नावों को तोड़े जाने एवं महिलाओं, बच्चों सहित कईयों को लाठी-डंडे से पीटने की घटना की सही जानकारी जुटाने एवं पीड़ितों की आर्थिक सहायता करने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा गठित एक टीम शुक्रवार 12 फरवरी को घटनास्थल पर पहुंची।

आठ सदस्यीय टीम में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधान परिषद् सदस्य डॉ. राजपाल कश्यप, एमएलसी बासुदेव यादव, विधान परिषद् सदस्य रामबृक्ष यादव, विधायक उज्जवल रमण सिंह, पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत निषाद, संदीप यादव, पप्पू लाल निषाद, संदीप पटेल शामिल रहे। जिलाध्यक्ष योगेश चन्द्र यादव एवं महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेख़ार हुसैन ने टीम के सदस्यों के साथ घटनास्थल एवं पीड़ितों के घरों में जाकर उनसे मुलाकात की और पूरी जानकारी जुटाई। सपा मीडिया प्रभारी दान बहादुर मधुर के अनुसार सपा की टीम द्वारा पार्टी फंड से पीड़ितों को 20-20 हजार का चेक प्रदान किया गया तथा घायलों को नकदी धनराशि देकर उनकी मदद की गई। घटनास्थल से वापस आने के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉ. राजपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा शासन में लगातार दलितों, पिछड़ों खासकर निषाद, मल्लाह बिरादरी के लोगों के साथ अत्याचार की घटनाएं हुईं हैं। प्रयागराज में सूखी जगह खड़ी नावों को तोड़ दिया गया, नाव मालिकों एवं उनके परिवार के महिलाओं, बच्चों तक को मारा पीटा गया।

कहा कि पिछले दिनों गोरखपुर फिर वाराणसी में भी इसी तरह की बातें आयीं हैं। लगातार बढ़ रहे पुलिसिया अत्याचार से निषाद, मल्लाह बिरादरी के लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हम लोगों को भेजा है। इसकी पूरी रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाएगी। यह मामला देश की संसद में उठ चुका है और आने वाले समय में विधानसभा एवं विधान परिषद् में भी उठाया जाएगा। टीम के सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि घायलों को चिकित्सकीय परीक्षण कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ितों के ऊपर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं व तोड़ी गई नावों के मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाए। टीम के सदस्यों के साथ सपा जिलाध्यक्ष योगेश चन्द्र यादव, महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेख़ार हुसैन, महेंद्र निषाद, नाटे चौधरी, भागीरथी बिंद, महावीर यादव, डॉ. पंचू राम निषाद आदि मौजूद रहे।

कमिश्नर, डीएम समेत आला अधिकारियों ने लगवाया टीका

कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित व प्रभावीः डीएम

झांसीः कलेक्ट्रेट परिसर में मंडलायुक्त सुभाष चंद शर्मा द्वारा कोविड वैक्सीनेशन बूथ का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के दूसरे दौर में कमिश्नर सुभाष चंद शर्मा व जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी समेत जिले के आला अधिकारियों ने टीकाकरण कराया।

इस दौरान जिलाधिकारी ने टीकाकरण के बाद संदेश दिया कि टीकाकरण पूरी तरह प्रभावी और असरदार है। इसे लेकर किसी तरह का भ्रम या भय न पालें। टीका लगवाने के बाद भी कोरोना संबंधी नियमों का पालन करें। जनपद के कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुरुवार 11 फरवरी को कोविड वैक्सीन बूथ का मंडलायुक्त सुभाष चंद शर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के पश्चात मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने कोविड वैक्सीन लगवायी और लोगों को भी वैक्सीन की जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरी तरह सुरक्षित है,

अफवाह पर कतई ध्यान न दें। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. रविशंकर ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद हाथ धोने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के नियमों का भली-भांति पालन भी करना है। उन्होंने बताया कि अब तक जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है। उन्हें दूसरी डोज के लिए उनके मोबाइल नंबर तक मैसेज पहुंचेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. जी. के. निगम ने कहा कि उन्हें भी टीका लगवाए लगभग 20 दिन हो गए और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। टीके को लेकर किसी तरह का भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

ड्रीमलैंड मेले में ठेंगे पर सफाई अभियान

आईपीके, झांसीः शहर में आयोजित किया गया ड्रीमलैंड मेला अव्यवस्थाओं का केंद्र बन गया है। मेले में स्वच्छता अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन की अनदेखी के चलते यहां पर आने वाले लोगों की जान भी खतरे में है।

दरअसल, शहर में आयोजित किए गए ड्रीमलैंड मेले में हर दिन सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, पर यहां पसरी बदइंतजामी के चलते लोगों की जान खतरे में है। ठेकेदारों द्वारा मोटी रकम लेकर मेले में दर्जनों की संख्या में दुकानें लगवाई गई हैं, लेकिन साफ-सफाई व अन्य व्यवस्थाएं समुचित तरीके से नहीं की गई हैं। जिसका नतीजा यह है कि दुकान लगाने वाले-दुकानदार अपनी दुकान के पीछे ही कूड़े-कचरे का ढेर फेंक दे रहे हैं। जिससे उनसे उठने वाली सड़ांध से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यहां पर साफ-सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदारों की है, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नही है। जिसका नतीजा यह है कि मेले में स्वच्छता अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके अलावा सिर्फ एक निकासी द्वार होने की वजह से लोगों को मेले से निकलने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। दरअसल, जब कभी बड़ा मेला आयोजित किया जाता है तो कम से तीन-चार निकासी द्वार बनाए जाते हैं, जिससे कभी भगदड़ या किसी अन्य आपातकालीन परिस्थिति में लोग आसानी से वहां से निकल सकें, पर यहां पर जिम्मेदारों ने ऐसी कोई व्यवस्था नही की है। इसके अलावा मेले में अग्निकांड से बचने के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे आग लगने की दशा में किसी बड़े हादसे से इंकार नही किया जा सकता है। यहां पर लगी दुकानों से ठेकेदारों द्वारा मोटा किराया वसूल किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर इंतजाम नाकाफी हैं।

दुकानों के पीछे फैली गंदगी

खुले में शौच के लिए मजबूर हैं लोग

मेले में व्याप्त अव्यवस्था का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहां पर सिर्फ एक शौचालय की व्यवस्था की गई है। ऐसे में यहां हर दिन आने वाले सैकड़ों लोगों को मजबूरन खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यही नही सुदूर क्षेत्रों से यहां दुकान लगाने के लिए आए दुकानदार यहीं पर रहते भी हैं, उन्हें भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ लोगों ने बताया कि जो एक शौचालय स्थित भी है, वह दिन में 11-12 बजे खुलता है और शाम होते ही बंद हो जाता है।

पुल के कार्यों में विभागीय अधिकारी लाएं तेजी : डीएम

शिफ्टिंग के कार्यों को पुनः रिव्यू करें विभाग, एनओसी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश

आईपीके, झांसीः जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने शनिवार 13 फरवरी को कैंप कार्यालय पर ग्वालियर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर सेतु निगम द्वारा पुल बनाए जाने के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संबंधित विभाग अपनी तैयारियां कर लें, ताकि जैसे ही रेलवे से सहभागिता का अप्रूवल प्राप्त होता है तो कार्य जल्द प्रारंभ कराया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्य को गुणवत्ता के साथ जल्द पूर्ण करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि पुल की लागत रु12051.80 लाख (120 करोड़) है। रेलवे विभाग के अधिकार वाले क्षेत्र में कार्य की लागत लगभग 22 करोड़ 81 लाख है। उन्होंने बताया कि माह दिसंबर 2020 को सहभागिता हेतु अप्रूवल शासन को प्रेषित किया गया है, रेलवे विभाग द्वारा मार्च में सहभागिता अप्रूवल मिलने की संभावना है। उन्होंने जल निगम, विद्युत विभाग, जल संस्थान, बीएसएनएल, वन विभाग को निर्देश दिए कि शिफ्टिंग कार्य में तेजी लाएं और जो शिफ्टिंग एस्टीमेट बनाया गया है उसका रिव्यू कर लें, ताकि अप्रूवल प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ हो सके। उन्होंने बैठक में जल निगम द्वारा लाइन शिफ्टिंग के लिए 8.50 करोड़ का स्टीमेट सेतु निगम को प्रेषित किया। सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर वेद प्रकाश ने कहा कि जल निगम यदि लाइन डायाग्राम दे तो लाइन को मॉडिफाई करते हुए कम लागत में शिफ्ट किया जा सकता है। विद्युत पोल व लाइन हेतु विद्युत विभाग ने 42 लाख का स्टीमेट, जल संस्थान द्वारा पाइप लाइन शिफ्टिंग के लिए सेतु निगम को 51 लाख तथा बीएसएनएल द्वारा लाइन शिफ्टिंग हेतु 21 लाख का स्टीमेट प्रेषित किया गया है। सेतु निर्माण में वन विभाग द्वारा एनओसी के संबंध में बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सेतु निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन करें ताकि समय से एनओसी प्राप्त हो सके। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी शैलेष कुमार, नगर आयुक्त अवनीश कुमार राय, अधिशासी अभियंता विद्युत डी यादुवेंद्र, अधिशासी अभियंता जल संस्थान कुलदीप सहित जल निगम, वन विभाग, बीएसएनएल के अधिकारी उपस्थित रहे।

फिल्म कलाकारों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

बोले सीएम योगी, यूपी के बलिदानियों पर बनें फिल्में

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म निर्माता राहुल मित्रा, अभिनेता रणदीप हुड्डा, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और निर्देशक नीरज पाठक ने उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म से जुड़ी टीम से यूपी के बलिदानियों, यहां के ऐतिहासिक नायकों के जीवन की कहानियों पर भी फिल्म बनाने का आग्रह किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पधारे सभी कलाकारों से प्रदेश में अधिक से अधिक फिल्मों के निर्माण के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शूटिंग के दौरान कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। योगी ने फिल्म से जुड़ी टीम से यूपी के बलिदानियों, यहां के ऐतिहासिक नायकों के जीवन की कहानियों पर भी फिल्म बनाने का आग्रह किया। इसके अलावा योगी ने कई अन्य कहानियों और विचारों पर भी फिल्म निर्माण के लिए आमंत्रित किया। योगी के साथ अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी इस एक घंटे की विशेष बातचीत में मौजूद रहे। ज्ञात हो कि मुम्बई फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सितारे रणदीप हुड्डा अपनी वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश की शूटिंग के लिए लखनऊ में हैं। इंस्पेक्टर अविनाश यूपी एसटीएफ की सक्सेज स्टोरी को बयान करती हुई वेब सीरीज है। वेब सीरीज में यूपी एसटीएफ के कई सक्सेज केसों को लेकर तैयार किया गया है। इसमें रणदीप हुड्डा सुपर कॉप अविनाश मिश्र के किरदार में नजर आएंगे।

प्रसिद्ध मुम्बई फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से सजी टीम जिओ स्टूडियोज निर्मित वेब सीरीज की शूटिंग लखनऊ में हो रही है। इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज एक पुलिस थ्रिलर है जो यूपी के ही एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी अविनाश मिश्रा और यूपी एसटीएफ की सक्सेज स्टोरी पर आधारित है। इससे पहले भी कई वेब सीरीज यूपी पुलिस की सक्सेज स्टोरी पर बन चुकी हैं। वेब सीरीज के बारे में बताते हुए रणदीप हुड्डा ने कहा, 'सुपर कॉप अविनाश मिश्रा के तौर पर एक्टिंग करना रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। इस सीरीज के साथ इस साल की शुरूआत करने को लेकर मैं काफी खुश हूं। रणदीप हुड्डा ने प्रदेश सरकार की फिल्म नीतियों की भी काफी तारीफ की। उन्होंने यूपी फिल्म सिटी निर्माण को योगी सरकार का बड़ा कदम बताया। रणदीप हुड्डा इससे पहले भी अपनी एक वेब सीरीज की शूटिंग यूपी में कर चुके हैं। आभिनेता रणदीप हुड्डा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। उन्होंने प्रदेश की ओर से नमामि गंगे परियोजना के तहत डालफिन संरक्षण को लेकर उठाए गए सरकार के कदमों की सराहना की। रणदीप हुड्डा यूनाइटेड नेशन के डालफिन संरक्षण के लिए चलाई जा रही मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गंगा समेत अन्य नदियों को अविरल करने की जो मुहिम चलाई है, वह बहुत ही कारगर साबित हो रही है। गंगा में डालफिन अटखेलियां करती हुई नजर आ जाती है। यह सरकार के डालफिन संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों की बदौलत है।

कमिश्नर के औचक निरीक्षण में बंद मिला ट्रीटमेंट प्लांट

झांसीः कमिश्नर श्री सुभाष चंद्र शर्मा ने शुक्रवार 12 फरवरी को लक्ष्मी ताल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्लांट संचालित नहीं था और जल निगम का कोई अभियंता भी उपस्थित नहीं मिलने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। इस दौरान कमिश्नर ने कंपनी के एक सिविल इंजीनियर तथा लैब टेक्नीशियन से प्लांट चालू कराया। लक्ष्मी ताल और दो नालों के बीच खाली जगह में नालों से सीधा गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट किये नारायण बाग की तरफ बह रहा था, इस स्थिति पर सहायक अभियंता आरके गुप्ता से फोन पर वार्ता कर तत्काल व्यवस्था में सुधार करने के लिये सख्त हिदायत दी और ट्रीटमेंट प्लांट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए निर्देश दिए। यह राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में जल निगम का प्लांट है, जहां गंदे पानी को फिल्टर करके पानी को साफ किया जाता है।

मृतक जीवित होने के लिए काट रहा तहसील के चक्कर

चर्चा में लेखपाल की कारगुजारी

जौनपुरः अधिकारियों की मनमानी का नतीजा आम लोगों को किस तरह भुगतान पड़ता है, इसका जीता-जागता उदाहरण हैं जिले के गोदना गांव निवासी मंगरू। जिंदा होने के बावजूद भी वह खुद को जीवित बताने के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं।

दरअसल, उक्त तहसील के हल्का लेखपाल द्वारा राजस्व अभिलेखों में मृत घोषित कर दूसरे को वरासत कर दिए जाने पर मृतक महीनों से तहसील के चक्कर काट रहा है। लेखपाल की कार्यप्रणाली तहसील में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तहसील क्षेत्र के गोदना गांव निवासी मंगरु पुत्र सितंबर के नाम आराजी नंबर 823 का पट्टा हुआ था। मंगरु का आरोप है कि हल्का लेखपाल श्रेयस गंगवार को उक्त असंक्रमणीय को संक्रमणीय करने का अनुरोध किया था, लेकिन पैसे की व्यवस्था न होने पर लेखपाल ने उसे मृतक घोषित कर मुसहर जाति की केला देवी पत्नी रमई पर पराजित राम पुत्र रमई के नाम वरासत कर दिया जबकि पाटीदार अनुसूचित जाति का है। तहसील में खतौनी लेने के बाद भुक्तभोगी के होश उड़ गए। लेखपाल द्वारा की गई इस जालसाजी को लिखित शिकायत अपने अधिवक्ता विनय प्री पांडे के माध्यम से मृतक ने तहसीलदार अमित कुमार त्रिपाठी से 6 फरवरी को किया तो तहसीलदार ने लेखपाल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

सॉफ्ट हिन्दुत्व से 'मिशन 2022' फतह की तैयारी में कांग्रेस

हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में लगी हैं प्रियंका गांधी | भाजपा को काउंटर करने की बना रहीं रणनीति

सहारनपुर में किसान पंचायत में हिस्सा लेतीं प्रियंका

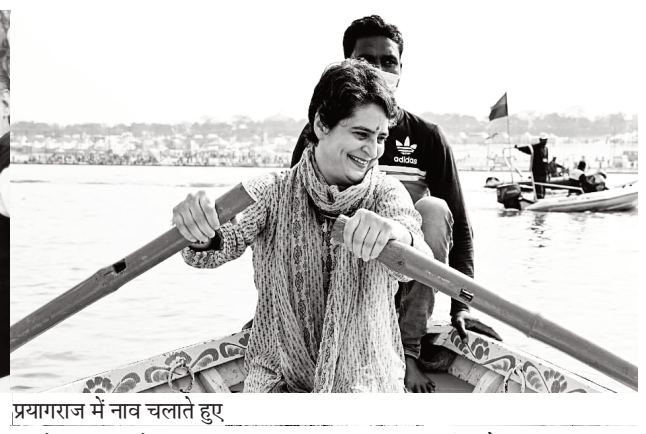

प्रयागराज में नाव चलाते हुए

लखनऊः उत्तर प्रदेश में करीब तीन दशक से सत्ता से विमुख कांग्रेस अब हिन्दुओं के बीच में जगह बनाने के प्रयास में लग गयी है। उसे लगता है कि सॉफ्ट हिन्दुत्व के सहारे 2022 का रण जीतना आसान होगा, इसीलिए वह अब इस कार्य में तेजी से लग गयी है।

बुधवार 11 फरवरी को किसान पंचायत में हिस्सा लेने सहारनपुर पहुंचीं कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा को देखकर तो ऐसा ही लगा कि पार्टी हिन्दुत्व के लिए भी एक सॉफ्ट कोना तैयार कर रही है। सहारनपुर पहुंचीं प्रियंका के हाथों में रुद्राक्ष की माला और मंदिरों के दर्शन-पूजन यही संकेत दे रहे थे। किसान पंचायत से पहले प्रियंका गांधी ने बाबा भूरा देव के दर्शन किए। इसके बाद शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचीं। यहां पूजा अर्चना की और करीब 25 मिनट तक फर्श पर ध्यान में बैठी रहीं। इस दौरान भी उनके गले में रूद्राक्ष की माला देखी गई। शाकंभरी देवी मंदिर से प्रियंका खानकाह भी पहुंचीं। उत्तर प्रदेश में लगातार ठोकरें खाती जा रही कांग्रेस अब सधे कदमों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। उसी क्रम में प्रियंका ने मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम में आस्था की डुबकी लगायी और बगैर वीआईपी प्रोटोकॉल के सामान्य स्नानार्थी की तरह संगम में गंगा स्नान किया, जो हिंदू वोटरों को पार्टी की तरफ आकर्षित करने का कदम माना जा रहा है।

हिंदू वोट बैंक पर नजर

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल कहते है कि अब राजनीतिक दलों के लिए मुस्लिम वोट बैंक नहीं रह गया है। इसके पहले मुस्लिम वोट बैंक की तरह प्रयोग होता है। भाजपा ने इस राह को खत्म कर दिया है। मुस्लिम समाज भी एक पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। धीरे-धीरे वह पार्टी से अलग होकर अपना वोट देता है। ऐसे में मुस्लिम समाज को अपनी ओर आकर्षित करना लाभप्रद नहीं लग रहा है। इसीलिए पार्टियां बहुसंख्यक हिन्दू समाज में अपना कोना तलाश रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मंदिर-मंदिर जा रहे हैं। वह अयोध्या को मॉडल सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। कृष्ण और परशुराम की पूजा करना शुरू कर दिया है।

भाजपा को काउंटर करने की रणनीति

बसपा प्रमुख मायावती ने भी मुस्लिम लीडरशिप से किनारा कर लिया है। अब कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से हिन्दू समाज के साथ जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है। जो कि इस बात को दर्शाता है कि भाजपा को काउंटर करने के लिए हिन्दूवाद ज्यादा मुफीद होगा। कांग्रेस को लगता है कि अगर हमने मुस्लिम समाज से जोड़ा तो फिर एक बार हिन्दू भाजपा की ओर लामबंद हो जाएंगे। इससे अच्छा हिन्दुत्व को लेकर चलना ठीक है। जो हिन्दू भाजपा को किसी कारण पसंद नहीं करते हैं तो वह इन पार्टियों का रूख कर सकते हैं। इसी रणनीति पर काम भी चल रहा है।

सनातनधर्मी रहा है नेहरू-गांधी परिवार

कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता किशोर वाष्णेय कहते हैं हिन्दुत्व किसी पार्टी की जागीर तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी वाले राम की भक्त है। हम राम के नाम को बेचते नहीं हैं। हम लोग भगवान के नाम को बेचते नहीं हैं। कांग्रेस ने हमेशा पूजा-पाठ में विश्वास रखा है। इसीलिए राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया था। उन्होंने बताया कि 1975 में इंदिरा भी संगम पहुंची थीं। 2001 में सोनिया गांधी संगम आयी थीं। उन्होंने संगम स्नान किया था। 18 मार्च 2019 को प्रियंका गांधी संगम पहुंची थीं। उन्होंने लेटे हनुमान जी के दर्शन किये थे। संगम में गंगाजल का आचमन किया था। स्वाती हरि चैतन्य ब्रम्हचारी महाराज ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार सनातनी धर्मी रहे हैं। नेहरू, इंदिरा जी कई बार संगम स्नान करने आए हैं। गांधी नेहरू परिवार शुरू से पूजा-पाठ करता चला आ रहा है।

संपादकीय

प्रमादि संवत्सर विक्रम संवत 207, शक संवत 1942

राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम, शिवम, सुन्दरम से प्रेरित है।

भारत के राष्ट्रवाद से हारा चीन

भारत-चीन सीमा पर पिछले 9 महीने से चल रहा सबसे बड़ा तनाव खत्म होता दिख रहा है। इस तनाव के दौरान 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, वहीं 45 चीनी सैनिक भी मारे गए थे। तब से प्रत्येक भारतीय के मन में चीन और चीन में बने सामानों के प्रति नाराजगी सिर चढ़कर बोल रहीं थी। आम लोगों ने चीनी कम्पनियों का बहिष्कार करने की मुहिम शुरू कर दी थी, साथ ही केंद्र सरकार ने भी तमाम ऐप्स पर प्रतिबंध लगा कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। अपना व्यावसायिक नुकसान देखकर चीन को भारतीय राष्ट्रवाद के आगे घुटने टेकने पर विवश होना पड़ा। 10 फरवरी को चीनी रक्षा मंत्रालय द्वारा चीनी सेनाओं की वापसी की घोषणा के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को तनाव खत्म होने और पूर्वी लद्दाख में मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल होने की जानकारी दी। चीनी सैनिकों की वापसी पर भारत की नजर रहनी चाहिए और दूसरी विवादित सीमा पर भी बातचीत शुरू करने का प्रयास करना चाहिए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि चीनी सैनिक झील के उत्तरी तट पर फिंगर-8 के पूर्व की तरफ लौट जाएंगे, यानी अप्रैल-मई 2020 से पहले वाली स्थिति में आ जायेंगे। वहीं, भारत अपने सैनिकों को फिंगर 3 के पास स्थित परमानेंट बेस पर तैनात रखेगा। यह भी तय हुआ है कि अप्रैल 2020 के बाद, झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर बनाए गए किसी भी स्ट्रक्चर को दोनों सेनाएं नष्ट करेंगी। जो स्थिति उस वक्त थी, वही स्थिति बहाल की जाएगी। यानी, इस समझौते में भारत ने कुछ नहीं खोया है, मगर चीन ने उत्तरी तट पर जो एडवांस पोजीशन हासिल की थी, उसे छोड़नी होगी। वैसे भी फिंगर-8 तक का इलाका भारत में आता है तो चीन को भी अपनी इस हरकत से कुछ हासिल नहीं हुआ है। यदि चीन यह मान रहा है कि वह उग्रता का प्रदर्शन करके अपनी बात मनवा लेगा तो आज के युग में ऐसा होने वाला नहीं है। भले ही वह विश्व महाशक्ति बनने को आतुर हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके अधिकांश पड़ोसी देश उसे क्षेत्रीय और विश्व शांति के लिए खतरा मानने लगे हैं। वह केवल दक्षिण चीन सागर से जुड़े देशों को ही नहीं धमका रहा, बल्कि ताइवान को भी आंखें दिखा रहा है। अब तो वह हांगकांग पर भी अपने तानाशाही भरे कानून थोपने के लिए जोर-जबरदस्ती कर रहा है। इसके नतीजे में वह केवल दुनिया भर में बदनाम है, जिस कारण उससे दूरी बनाने वाले देशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे देशों में भारत की गिनती होना स्वाभाविक है। चीन अपनी भारत विरोधी हरकतों से भारतीयों के मन-मस्तिष्क में अपने लिए अविश्वास भरने का ही काम कर रहा है। यदि चीन एशिया की एकमात्र शक्ति बनने के नशे में मनमानी करना जारी रखता है तो फिर भारत के पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह उससे दूरी बनाने के ठोस कदम उठाए। ये कदम तब तक उठाए जाने चाहिए, जब तक चीनी नेतृत्व यह समझने को तैयार नहीं होता कि एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार चीन से तो निर्वाह हो सकता है, अड़ियल-अविश्वसनीय और तानाशाह चीन से नहीं हो सकता है। भारत-चीन की तकरीबन 4056 किमी की सीमा आपस में मिलती हैं। ये सीमाएं भारत के चार राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणांचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से मिलती हैं। चीन हमेशा सीमा से लगी भारतीय भूमि पर कब्जे की ताक में रहता है। अमेरिकन सांसद माइकल मैक्कॉल ने ट्वीट किया, 'अपने संप्रभुता के बचाव में भारत मजबूती से खड़ा है, जिसे देखकर खुशी हो रही है। दोनों ओर से लगभग 50-50 हजार सैनिक आमने-सामने तैनात थे। चीन की दो मोटराइज़्ड डिवीजन या टैंकों-बख्तरबंद गाड़ियों की मिली-जुली तादाद पूर्वी लद्दाख के सामने तैनात है। दोनों देशों की सेनाओं के कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत 24 जनवरी को 16 घंटे तक हुई थी और उसके बाद ही सेनाओं की वापसी पर फैसला लिया जा सका।

इतनी असहिष्णुता क्यों ?

बीते दिनों दो खबरें सुर्खियों में रहीं। पहला, देश के 9 राज्यों में हिंदू 'अल्पसंख्यक' हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के एक युवक की हत्या की। प्रश्न उठता है कि जिस तरह एक समूह द्वारा निर्ममता पूर्वक हत्या की गई उसे 'लिंचिंग' मानना चाहिए या नहीं ? दूसरी ओर समाज के कथित बौद्धिक समूहों में सन्नाटा छाया हुआ है, कुछेक आवाजें जो आयीं उन्होंने पुलिस के बयान को प्रमुखता से सामने रखा जिसमें हत्या की वजह आपसी झगड़ा बताया गया है। मंगोलपुरी दिल्ली का निवासी रिंकू शर्मा की हत्या धार्मिक उन्माद और सम्प्रदाय विशेष के प्रति कुछ लोगों के दिलों में नफरत के सिवाय कुछ नहीं है। जिस तरह रिंकू शर्मा को बदमाशों ने चाकूओं से घोप कर हत्या कर की, उससे उनकी क्रूरता स्पष्ट होती है।

रिंकू एक प्राइवेट अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था और बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य भी था। पुलिस ने रिंकू की हत्या के आरोप में 5 को गिरफ्तार कर लिया है.. जिनके नाम हैं..ताजुद्दीन, दानिश, ज़ाहिद, इस्लाम और नाटू। इसके बाद पूरे मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। मरने वाले का नाम अगर हामिद होता और हत्यारे अगर रिंकू, संदीप, महेश और दिनेश होते तो हमारे समाज की प्रतिक्रिया इस पर क्या होती ? बात-बात पर पुरस्कार वापस करने वाले, कैंडल मार्च करने वाले कहां गए ? इस असहिष्णुता पर चुप क्यों हैं ? क्या इसे मामूली विवाद मानकर छोड़ दिया जाए या फिर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बता कर काम चला लिया जाए ? भारतीय अल्पसंख्यकों में डर का भय दिखाकर समय समय पर सुर्खियों में रहने वाले स्वनामधन्य लोग आखिर कहां है ? पुलिस ने इस घटना पर एक बयान जारी कर बयानवीरों की राह जरुर कुछ आसान कर दी है। रिंकू शर्मा के भाई का कहना है कि आरोपी के साथ हमारी पिछले एक साल से विवाद था। अगस्त में, हमने श्रीराम मंदिर के लिए एक छोटा आयोजन किया था। जिससे वे लोग इससे नाराज थे, लेकिन हमने उन्हें नजरंदाज कर दिया। हम हमेशा अच्छे पड़ोसी रहे हैं। आरोपी के परिवार के एक महिला जब गर्भवती थी तो खून की जरूरत पड़ी। रिंकू ने उसे खून दिया था। यानी उन दरिंदों ने रक्तदान को कलंकित किया हुआ। काश अपना काम करेगा, लेकिन उन राक्षसों ने विश्वास की हत्या की, मानवता की हत्या की है, जो दोनों संप्रदायों के बीच खाई बढ़ाने का काम करेगा।

कृषि कानून में नहीं, नेताओं के मन में काला

किसान नेताओं के अपने तर्क हैं। न मंच टूटेगा और न किसान मोर्चा टूटेगा। 26 जनवरी से भी बड़ा आंदोलन होगा। पहले 4 लाख ट्रैक्टर लाए थे, अब 40 लाख लाएंगे। एक किसान नेता कह रहा है कि सरकार गिराने का उसका इरादा नहीं, सरकार बस किसानों की समस्या हल करे। किसान मोर्चा के दो नेता कह रहे हैं कि जब हरियाणा सरकार गिरेगी तब केंद्र को किसानों की ताकत का पता चलेगा। बात जोर-आजमाइश की हो रही है। समूचा किसान आंदोलन भटका हुआ है।

किसान आंदोलन सुर्खियों में है। सड़क से लेकर संसद तक किसान आंदोलन चर्चा के केंद्र में है। केंद्र सरकार द्वारा पास तीन कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। उसे काला कानून बताकर वापस लेने की मांग की जा रही है। जो दल आज कह रहा है कि सत्ता में आए तो तीनों कानून रद्द करेंगे, जब उस दल की सरकार थी तो इसी तरह का कानून लाने की वकालत कर रही थी। आज वह विपक्ष में है तो इस कानून में काला नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि रंग नहीं, कानून का संदर्भ देखो। विरोध में संदर्भ देखने की परंपरा नहीं है। विरोध तो बस खत्म करने में यकीन रखता है। किसान नेताओं के अपने तर्क हैं। न मंच टूटेगा और न किसान मोर्चा टूटेगा। 26 जनवरी से भी बड़ा आंदोलन होगा। पहले 4 लाख ट्रैक्टर लाए थे, अब 40 लाख लाएंगे। एक किसान नेता कह रहा है कि सरकार गिराने का उसका इरादा नहीं, सरकार बस किसानों की समस्या हल करे। किसान मोर्चा के दो नेता कह रहे हैं कि जब हरियाणा सरकार गिरेगी तब केंद्र को किसानों की ताकत का पता चलेगा। बात जोर-आजमाइश की हो रही है। समूचा किसान आंदोलन भटका हुआ है।

सत्ता पक्ष को पता है कि यह आंदोलन सभी किसानों का नहीं है, मुट्ठी भर बड़े किसानों का है, लेकिन इसके राजनीतिकरण को लेकर वह परेशान भी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि माओवादियों, खालिस्तानी आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर आंदोलनजीवियों ने किसानों के आंदोलन को अपवित्र कर दिया है। टेलीफोन वायर तोड़ने, टोल प्लाजा पर कब्जा करने पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। आंदोलनजीवियों पर निशाना भी साधा है, यह भी कहा है कि जो लोग अपना आंदोलन खड़ा नहीं कर पाते, वे किसी के भी आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। चौधरी चरण सिंह, डॉ. मनमोहन सिंह के नजरिये का उल्लेख कर उन्होंने आंदोलनजीवियों को आईना भी दिखाया है। कांग्रेस पर तो सीधा हमला किया है और यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस न अपना भला कर सकती है और न देश का। संसद में हंगामे की वजह उन्होंने विपक्ष के भय को बताया है। उनके हिसाब से हंगामा इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि जो झूठ किसान कानूनों को लेकर उन्होंने फैलाया है, उसे लोग जान न जाएं। उसका पर्दाफाश न हो जाए। उन्होंने किसानों से भी यह पूछा है कि नए कानूनों के पास होने के बाद उनका कौन-सा पूर्व का अधिकार छिन गया है। उन्होंने विपक्ष के तर्कों पर भी प्रहार किया है कि जब किसान कृषि सुधार कानून मांग ही नहीं रहे तो आप कानून क्यों ले आए? इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने आन्दोलनजीवियों और आंदोलनकारियों के बीच का फर्क किए जाने पर जोर दिया है।

इससे सबक लेने की बजाय राजनीतिक दल आंदोलनजीवी की बांग लगाने लगे हैं। कुछ खुद को आंदोलनवादी कहने लगे हैं। आंदोलन पवित्र तभी होता है, जब उसमें मिलावट न हो। राजनीतिक घाल-मेल न हो। इस आंदोलन को तो पहले दिन से ही राजनीतिक समर्थन रहा है। आज भी है। किसान आंदोलन तो बहाना है, निशाना कहीं और है। जिस तरह इस आंदोलन को विदेशी फंडिंग हो रही है, उसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। राकेश टिकैत एक ओर तो यह कहते नजर आते हैं कि सरकार आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, दूसरी ओर वे खुद अक्टूबर-नवम्बर तक आंदोलन को चलाने की बात कर रहे हैं। इस विरोधाभास को किस तरह देखा जाएगा? किसान आंदोलन के चलते विपक्ष देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करना चाहता है लेकिन जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है? अच्छा होता कि आंदोलन की पवित्रता-अपवित्रता के मकड़जाल में फंसने की बजाय उसे खत्म करने-कराने पर विचार होता। अर्द्धसत्य दुख ही देते हैं, इसे जितनी जल्दी समझ लिया जाएगा, उतना ही उचित होगा। जब सर्वत्र ताकत दिखाने का खेल चल रहा हो तो स्याह-सफेद होना स्वाभाविक है। कानून काला नहीं है, कालिमा तो मन में है, उसका शोधन होना चाहिए। जब सब पैंतरे पर हों तो बात वैसे भी नहीं बनती। राजनीतिक दल अपनी फितरती पैतरों से बाज आएं, तभी इस देश के किसानों का भला हो सकेगा। आशंकाओं की राजनीति देश का बेड़ा गर्क ही करेगी।

सियाराम पांडेय

अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता 'इंटरनेट शटडाउन'

डिजिटल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप 'टॉप-10 वीपीएन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वर्ष भारत में कुल 75 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। कुल 8,927 घंटे तक इंटरनेट पर लगी पाबंदी से जहां 1.3 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए, वहीं इससे देश को करीब 2.8 बिलियन डॉलर (204.89 अरब रुपये) का नुकसान हुआ।

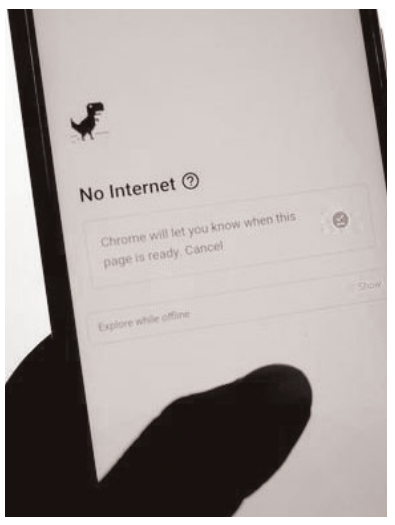

26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद हरियाणा के कई जिलों सहित सिंघू, गाजीपुर तथा टीकरी बॉर्डर पर सरकार के निर्देशों पर इंटरनेट सेवा बाधित की गई थी, जो विभिन्न स्थानों पर करीब दस दिनों तक जारी रही। हरियाणा में दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए थे। इंटरनेट आज न केवल आम जनजीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, बल्कि इस पर पाबंदी के कारण हरियाणा में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ। इंटरनेट सुविधा पर पाबंदी के कारण छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं बंद हो गई थीं, इंटरनेट पर आधारित व्यवसाय ठप हो गए थे।

विभिन्न सेवाओं और योजनाओं के माध्यम से एक ओर जहां सरकार 'डिजिटल इंडिया' के सपने दिखा रही है, अधिकांश सेवाओं को इंटरनेट आधारित किया जा रहा है, वहीं बार-बार होते इंटरनेट शटडाउन के चलते जहां लोगों की दिनचर्या प्रभावित होती है और देश को इसका बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जिस तरह इंटरनेट शटडाउन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को बार-बार नेटबंदी का शिकार होना पड़ रहा है, उससे भारत की छवि पूरी दुनिया में प्रभावित हो रही है। ब्रिटेन के डिजिटल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप 'टॉप-10 वीपीएन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वर्ष भारत में कुल 75 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। कुल 8,927 घंटे तक इंटरनेट पर लगी पाबंदी से जहां 1.3 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए, वहीं इससे देश को करीब 2.8 बिलियन डॉलर (204.89 अरब रुपये) का नुकसान हुआ। इंटरनेट पर जो पाबंदियां 2019 में लगाई गई थीं, वे 2020 में भी जारी रहीं और भारत को 2019 की तुलना में गत वर्ष इंटरनेट बंद होने से दोगुना नुकसान हुआ। फेसबुक की पारदर्शिता रिपोर्ट में बताया गया था कि जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019 के बीच तो भारत दुनिया में सर्वाधिक इंटरनेट व्यवधान वाला देश रहा था।

'शीर्ष 10 वीपीएन' की रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते वर्ष विश्व भर में कुल इंटरनेट शटडाउन 27,165 घंटे का रहा, जो उससे पिछले साल से 49 प्रतिशत ज्यादा था। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया शटडाउन 5,552 घंटे रहा। ब्रिटिश संस्था द्वारा इंटरनेट पर पाबंदियां लगाने वाले कुल 21 देशों की जानकारियों की समीक्षा करने पर पाया गया कि भारत में इसका जितना असर हुआ, वह अन्य 20 देशों के सम्मिलित नुकसान के दोगुने से भी ज्यादा है और नुकसान के मामले में 21 देशों की इस सूची में शीर्ष पर आ गया है। वर्ष 2020 में 1,655 घंटों तक इंटरनेट ब्लैकआउट रहा तथा 7,272 घंटों की बैंडविथ प्रभावित हुई, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में सर्वाधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया भर में नेटबंदी से होने वाले कुल 4.01 अरब डॉलर के नुकसान के तीन चौथाई हिस्से का भागीदार बना है। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत के बाद दूसरे स्थान पर बेलारूस और तीसरे पर यमन रहा। बेलारूस में कुल 218 घंटों की नेटबंदी से 336.4 मिलियन डॉलर नुकसान का अनुमान है। रिपोर्ट में 'इंटरनेट शटडाउन' को परिभाषित करते हुए इसे 'किसी विशेष आबादी के लिए या किसी एक स्थान पर इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार को इरादतन भंग करना' बताया गया है और इस ब्रिटिश संस्था के अनुसार ऐसा 'सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण' कायम करने के लिए किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि भारत में सरकार द्वारा इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग कानूनों का सहारा लिया जाता है, जिनमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (सीआरपीसी) 1973, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 तथा टेंपरेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 शामिल हैं। पहले सूचना के प्रचार-प्रसार सहित इंटरनेट शटडाउन का अधिकार इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 तथा धारा-144 के तहत सरकार व प्रशासन को दिया गया था, लेकिन टेंपरेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 के अस्तित्व में आने के बाद इंटरनेट शटडाउन का फैसला अब अधिकांशतः इसी प्रावधान के तहत लिया जाने लगा है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जो इंटरनेट को मानवाधिकार की श्रेणी में शामिल करता है और सरकारों द्वारा इंटरनेट पर रोक लगाने को सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन बताता है, लेकिन यह प्रस्ताव किसी भी देश के लिए बाध्यकारी नहीं है। इंटरनेट शटडाउन किए जाने पर सरकार और प्रशासन द्वारा सदैव एक ही तर्क दिया जाता है कि किसी विवाद या बवाल की स्थिति में हालात बेकाबू होने से रोकने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अफवाहों, गलत संदेशों, खबरों, तथ्यों व फर्जी तस्वीरों के प्रचार-प्रसार के जरिये विरोध की चिंगारी दूसरे राज्यों तक न भड़कने देने के उद्देश्य से ऐसा करने पर विवश होना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया के ज़रिये कुछ लोगों द्वारा झूठे संदेश और फर्जी वीडियो वायरल कर माहौल खराब करने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उन पर शिकंजा कसने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाने के अलावा प्रशासन के पास और भी तमाम तरीके होते हैं। विश्व भर में कई रिसर्चरों का दावा है कि इंटरनेट बंद करने के बाद भी हिंसा तथा प्रदर्शनों को रोकने में इससे कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती है। हां, लोगों का काम-धंधा अवश्य चौपट हो जाता है और व्यक्तिगत नुकसान के साथ सरकार को भी बड़ी आर्थिक चपत लगती है। इंटरनेट पर बार-बार पाबंदियां लगाए जाने का देश को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।

सरकार द्वारा इंटरनेट के जरिये अफवाहों और भ्रामक तथा भड़काऊ खबरों का प्रसार रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, लेकिन इससे लोगों की जिंदगी थम सी जाती है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी को चलाए रखने से जुड़ा हर कार्य अब इंटरनेट पर निर्भर जो हो गया है। ऐसे में ये सवाल उठने स्वाभाविक हैं कि एक ओर जहां सरकार हर सुविधा के डिजिटलीकरण पर विशेष बल दे रही है और बहुत सारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, वहीं आंदोलनों को दबाने के उद्देश्य से नेटबंदी किए जाने के कारण लोगों के आम जन-जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी को अपना आधार कार्ड बनवाना या ठीक कराना हो, किसी सरकारी सेवा का लाभ लेना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, खाने का ऑर्डर करना हो या फिर ऑनलाइन कैब, टैक्सी, रेल अथवा हवाई टिकट बुक करनी हो, बिना इंटरनेट के इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाना असंभव है। इंटरनेट शटडाउन के चलते एक ओर जहां ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है, वहीं सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। नेटबंदी की स्थिति में कोई अपनी फीस, बिजली व पानी के बिल, बैंक की ईएमआई इत्यादि समय से नहीं भर पाता तो बहुत से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने तथा इंटरनेट का उपयोग कर उनकी तैयारी करने में खासी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।

एक अनुमान के अनुसार, देश में आज 480 मिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जिनमें से अधिकांश इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। आज हमें जीवन के हर कदम पर इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज का सारा सिस्टम काफी हद तक कम्प्यूटर और इंटरनेट की दुनिया से जुड़ चुका है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कुछ समय पूर्व बताया था कि देश में इंटरनेट शटडाउन के कारण हर घंटे करीब ढाई करोड़ रुपये का नुकसान होता है। 'सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर' (एसएलएफसी) भी चिंता जताते हुए कह चुका है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में हम 'डिजिटल डार्कनेस' की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट शटडाउन से लोगों की जिंदगी किस कदर प्रभावित होती है और देश की अर्थव्यवस्था को इसके कारण कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है कुछ ऐसे विकल्प तलाशे जाने की, जिससे पूरी तरह इंटरनेट शटडाउन करने की जरूरत न पड़े। मसलन, प्रभावित इलाकों में पूरी तरह इंटरनेट बंद करने के बजाय फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल साइटों पर अस्थायी पाबंदी लगाई जा सकती है, जिससे विषम परिस्थितियों में भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर लोग अपने जरूरी काम कर सकें।

योगेश कुमार गोयल

बिना बैंड-बाजा के बारात

यूपी की राजधानी में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण के पटाखे फोड़े जा रहे हैं। रैंकिंग में नंबर वन के लिए अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं, उनके चेहरे उत्साह से लबरेज हैं। इन अधिकारियों ने तय किया था कि आफिस में बैठ कर लखनऊ को नंबर वन तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए सड़क पर उतरना होगा। भले ही बारात निकालनी पड़े। बैठक में क्या चल रहा है, यह सुनने के लिए दीवारों से कुछ सेनानी कान लगाए खड़े रहे। उन्होंने मौके पर ही मेहमानों की लिस्ट भी दे डाली। खर्च कितना आएगा और कहां से जुटाया जाएगा, अंदरखाने में इसका समाधान भी कर लिया गया था। इसमें सबसे ज्यादा तनाव मंत्रियों को बुलाने पर था। लखनऊ में मंत्री आवास हैं। इनको छोड़ना मानो बाद में मुसीबत लेने जैसा था। बहरहाल, किसी ने सुझा दिया कि लखनऊ के सांसद, विधायक और नगर निगम से ताल्लुक रखने वालों को ही रैली का न्योता दिया जाए। अगर अन्य विभाग के मंत्री को बुला लिया गया तो नगर निगम में कर्मचारियों की गुटबाजी का गुब्बारा फूट पड़ेगा। वैसे भी कैमरे के सामने दिखने के लिए तमाम लोग बिना बुलाए पहुंच ही जाते हैं। अब लखनऊ की स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम था, तो सभासदों को तो बुलाना स्वाभाविक था। चिंता थी कि अगर सभी सभासदों को न बुलाया गया तो बजट के दौरान तलवारें खिंच सकती हैं। यदि रैली में मारपीट या गाली-गलौज हुआ तो महापौर और नगर आयुक्त की नाक नीची हो जाएगी। बहरहाल, बड़ी जद्दोजहद के बाद इनको भी बुलाने पर सहमति बनी। सभी में राय बन गई कि 1090 पर एक बारात सरीखा रैली निकाली जाएगी। अब सवाल यह भी उठा कि मंच पर भाषण तो होना ही चाहिए तो बोलने वालों की भी लिस्ट बना ली जाए। मंच बनेगा तो मुख्य अतिथि भी होना चाहिए। परंपरा यही रही कि यदि मुख्य अतिथि होगा तो अध्यक्षता करने वाला खूब पढ़ा लिखा हो। इस पर भी सहमति बन गई।

10 फरवरी को कुछ मंत्रियों के अलावा तमाम अतिथिगण यहां सुबह ही पहुंच गए थे। महापौर, नगर आयुक्त के अलावा कुछ भाजपा नेता भी यहां मौजूद रहे। बड़ा सा मंच एक दिन पहले ही बना लिया गया था। मंच पर भाषण तो मंच के बाहर चाय का सिलसिला चला। नेता चिल्ला-चिल्लाकर सफाई की दुहाई दे रहे थे और उनके समर्थक नारे लगा रहे थे। कुछ ही देर में रैली निकली गई तो कैमरे और सेल्फी वालों का उत्साह उबाल पर आ गया। इस दौरान तो लगा कि भगदड़ न मच जाए। कुछ छुटभैया नेता धक्का-मुक्की करने लगे। कैसे टीवी में दिख जाएं और अखबार में फोटो छप जाए? बारात की शोभा बनाने के लिए कुछ सफेद घोड़े मंगवाए गए थे। उनके सवार इंतजार करते रहे कि कब रैली के आगे चलने के लिए बुलाया जाए। अगवानी में भी घोड़ा और दूल्हा हमेशा आगे ही चलता है। यहां सब उलटा-पलटा रहा। मंत्रियों और महापौर की गाड़ी निकल चुकी थी। तब तक इनको बताया भी नहीं गया कि कब किसके पीछे चलना है। किसी ने बुलाया कि अरे निकलो सब निकल गए। वह बेचारे मानो जहाज में उड़ान भरने लगे। जल्दी चलने के चक्कर में एक घोड़ा बिदक गया। मुश्किल से उसे संभाला गया। अपर नगर आयुक्त तो काफी देर तक रैली निकलवाने के लिए खड़ी रहीं। कुछ कर्मियों को उनकी चिंता थी। मगर उन्होंने कहा कि वह सबको निकाल कर बढ़ेंगी। पैदल चलने वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी टोली किसके पीछे चलेगी। जो टोली इंतजार में रुकी रही, बाद में उसको दौड़ लगानी पड़ गई। कुछ युवक माइक पर नारे लगाना चाह रहे थे, मगर उनको बताया भी नहीं गया था कि नारे में क्या बोलना है। दो-तीन, चार पहिया वाहन खुले मंगाए गए थे, उनमें नेताओं का कब्जा था। कुछ भाजपाई यहां भी जै श्रीराम के नारे लगाने लगे। संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, नगर विकास मंत्री आषुतोष टंडन, महापौर संयुक्ता भाटिया रैली की शोभा बने। जो बैंडबाजा मंगाया गया था वह तो काफी देर से आगे बढ़ा। बेचारे जनरेटर भी नहीं संभाल पाए कि बारात निकल गई। वह दौड़कर मंत्रियों के पीछे जाना चाह रहे थे, मगर ब्रास बैंड में जनरेटर भी था। इसने सारा खेल बिगाड़ दिया। लाते-पहुंचते पसीना-पसीना हो गए। 1090 पर खड़े पुलिस वालों ने उनको जल्दी जाने के लिए कहा तो वह भड़क गए। चौराहे पर ही बाजा बजाने लगे। बड़ी मुश्किल से माने और रैली से 200 मीटर दूर पहुंच गए। कुछ नगर निगम के कर्मचारी नंबर वन बनाना है के नारे लगा रहे थे। रैली बढ़ते ही उनकी संख्या भी कम हो गई। 2015 से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हुआ था। पिछले साल लखनऊ नगर निगम 12 नंबर पर था। इस बार मंत्री संविधान के अनुच्छेद 51-ए कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने का पाठ भी पढ़ा गए। आंकड़े दिए गए कि सवा दो करोड़ शौचालय यूपी में और देश में बारह करोड़ बनाए जा चुके हैं। अधिकारी भी अब गदगद हैं कि यह बात कह कर उनकी मेहनत को ताज पहना दिया जाएगा। गोमतीनगर, डालीबाग, हजरतगंज के अलावा कई क्षेत्र साफ सुथरे हैं। कुछ सभासद गुस्सा रहे हैं, उनका कहना है कि नंबर वन कहने वालों की जेब में है नंबर वन! गैर भाजपा वाले सभासदों के क्षेत्र में सफाई जा कर देख लो। रैली वहीं निकाली जाए, जहां सफाई की जरूरत है। जहां गंदगी है, वहीं अभियान चलाया जाए।

शरद त्रिपाठी

बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को करें प्रसन्न

आध्यात्म

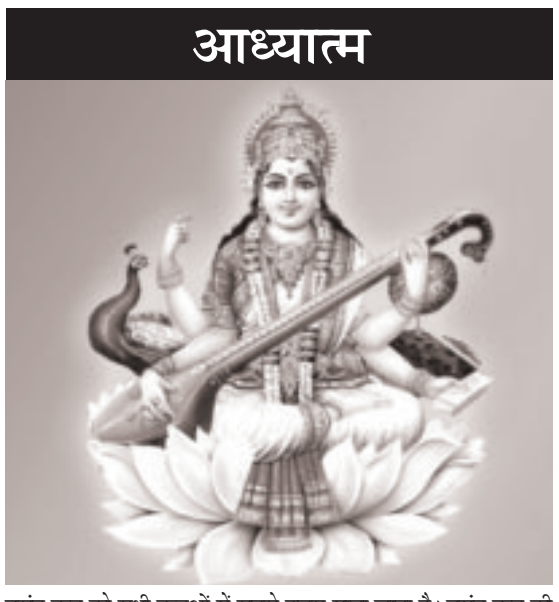

बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं में सबसे उत्तम माना जाता है। बसंत ऋतु की शुरूआत बसंत पंचमी के दिन से मानी जाती है। बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरूआत हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन मां देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन लोग पीले वस्त्रों को धारण करके माता सरस्वती की पूजा करते हैं। इस बार बसंत पंचमी का पर्व 16 फरवरी दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। जानते हैं बसंत पंचमी के पूजन का शुभ मुहूर्त और महत्व।

बसंत पंचमी का महत्व

बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन ज्ञान प्रदायिनी विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार, ज्ञान की देवी मां सरस्वती आज ही के दिन यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही ब्रम्हा जी के मुख से प्रकट हुईं थीं, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। चूंकि,माता सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसलिए शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरूआत करने के लिए आज का दिन शुभ माना जाता है। आज का दिन वैसे हर शुभ कार्य के लिए काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में लोग इस दिन गृह प्रवेश या कोई और मांगलिक कार्य भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कामदेव पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए जो पति-पत्नी इस दिन भगवान कामदेव और देवी रति की पूजा करते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में कभी मुश्किलें नहीं आती हैं। साथ ही आज के दिन विवाह का मांगलिक कार्य करना भी शुभ माना जाता है।

ऐसे करें मां सरस्वती की पूजा

इस दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करें। जिसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजन की शुरूआत करें। पूजा करते समय मां सरस्वती को पीला वस्त्र बिछाकर उस पर स्थापित करें। साथ ही रोली, केसर, हल्दी, चावल, पीले फूल, पीली मिठाई, मिश्री, दही, हलवा आदि प्रसाद के रूप में उनके पास रखें। मां सरस्वती को श्वेत चंदन पीले तथा सफेद पुष्प दाएं हाथ से अर्पण करें। केसर मिश्रित खीर अर्पित करना सर्

रास्ते पर आया चीन, पैंगोंग झील से हटने लगी सेना

भारत की सख्ती ने ढीले किए चीन के तेवर, कूटनीति के साथ सैन्य रणनीति ने दिलाई सफलता

आईपीके, लखनऊः भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीने से चल रहा विवाद अब समाप्ति की ओर अग्रसर लग रहा है। दोनों देश पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण से सैनिकों को हटाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी को राज्यसभा में दी।

रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ निरंतर वार्ता से पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट से सेना हटाने पर सहमति बनी है। समझौते के बाद, भारत-चीन चरणबद्ध और समन्वित तरीके से फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पीछे हटाएंगे। पिछले साल अप्रैल से शुरू हुआ ये विवाद अब अंत की ओर है। इस पूरे विवाद पर नज़र डालें तो पूरे विवाद के समय एलएसी पर लगातार तनाव बना रहा, यहां हजारों की संख्या में जवानों की तैनाती भी हुई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देशों के बीच गोलियां भी चलीं, लेकिन अब फिलहाल इस विवाद पर सहमति बन गई है। ऐसे में जानते हैं कि कैसे भारत ने अपनी सूझ-बूझ और सख्ती से चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।

भारत ने दिया चीन को मुंहतोड़ जवाब

चीन की चुनौतियों से पार पाने के लिए भारत ने कई मोर्चों पर तैयारी की, जिसका नतीजा रहा कि आज इसका हल निकला है। इसकी शुरूआत अप्रैल में हुई। अप्रैल में जब पूर्वी लद्दाख के पास चीन ने चुनौती देना शुरू किया और पूर्व की स्थिति न लागू करने की बात कही तो भारत ने भी एलएसी पर अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ा दिया था। इसके बाद चीन ने जब अपने करीब 10 हजार सैनिकों को एलएसी पर तैनात कर दिया तो भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए इतने ही जवानों को एलएसी पर तैनात कर दिया। भारत ने चीन को अपनी ताकत दिखाते हुए चीनी सीमा पर टैंकों की भी तैनाती कर दी। इसके बाद जब आए दिन तनाव बढ़ता गया तो भारत ने सितंबर-अक्टूबर तक अपने 60 हजार सैनिकों की सीमा पर तैनाती कर दी। तनाव की स्थिति को देखते हुए भारत की ओर से टाइप 15 लाइट टैंक्स, इंफैंट्री फाइटिंग व्हिकल्स, AH4 हॉवित्जर गन्स, HJ-12 एंटी टैंक्स गाइडेड मिसाइल्स, NAR-751 लाइट मशीनगन, W-85 हैवी मशीनगन की तैनाती कर दी गई थी। दोनों देशों के बीच ये तनाव जून में काफी बढ़ गया था। क्योंकि गलवान घाटी में चीन और भारत के जवान आमने-सामने आ गए थे। जिसके बाद चीन द्वारा किए गए हमले में भारत के 20 जवान भी शहीद हो गए थे। वहीं भारत की जवाबी कार्यवाही में चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था और उसके भी कई जवान मारे गए थे, लेकिन इस बार के तनाव के कारण ऐसा कई दशकों के बाद हुआ था कि चीन सीमा पर हिंसा में किसी जवान की जान गई हो। लद्दाख के आसमान में तेजस, राफेल, मिग, अपाचे, चिनूक समेत कई सेनाओं के विमानों और एयरफोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाला और चीन को साफ संदेश देने का काम किया। भारत ने ये दिखा दिया कि भारत अब कहीं से भी कमजोर नहीं है।

भारत ने ऐसे की घेराबंदी

भारत ने चीन को केवल सैन्य बल के ज़रिये ही चुनौती नहीं दी, बल्कि दिल्ली में सरकार की ओर से भी इस पूरे मसले पर कड़ा रुख अख्तियार किया गया। आक्रामक रुख अपनाते हुए मोदी सरकार की ओर से सबसे पहले सेना को खुली छूट दी गई और सैन्य लेवल पर ही मसले को सुलझाने पर जोर दिया, लेकिन बात नहीं बनते देख कर सरकार ने चीन मामले के विशेषज्ञ कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल को मोर्चे की जिम्मेदारी दी। साथ ही विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री लेवल पर भी सरकार ने अपनी ओर से वार्ता की। इतना ही नहीं भारत ने चीन को हर तरफ से घेरा। कूटनीति चलते हुए भारत ने चीन को वैश्विक स्तर पर बड़ा झटका देते हुए भारत में चीन के कई ऐप्स और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही कारण रहा कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व में चीन के प्रति एक अलग माहौल खड़ा हुआ और कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब के बाद भी चीन इस मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं था बल्कि चीन एलएसी पर अलग-अलग तरीके से अपनी ताकत बढ़ा रहा था, जिसको देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में है। तब भारत की सेना ने अलग-अलग पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। भारत के इस कदम से चीन भी एक बार घबरा गया और उसे झुकना पड़ा। भारतीय सेना ने मागर हिल, गुरुंग हिल, रेजांग ला राचाना ला, मोखपारी और फिंगर 4 रिज लाइन की कई पहाड़ियों पर कब्जा किया था। जिसके बाद चीन की अक्ल ठिकाने आई और अंततः चीन सैन्य लेवल पर बात करने और पीछे हटने पर मजबूर हो गया।

शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धः राजनाथ

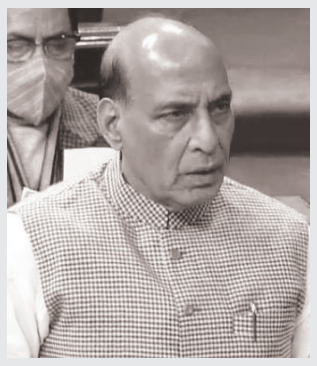

संसद में समझौते के बारे में बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन उत्तर पैंगोंग झील के फिंगर 8 के पूर्व में अपने सैनिकों को रखेगा। भारत अपने सैनिकों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी बेस पर रखेगा। रक्षा मंत्री ने कहा हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ने हमेशा द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सेनाएं कमांड पोस्ट पर लौट आएंगी, एक इंच जमीन नहीं दी जाएगी और टकराव के बाद भारत ने कुछ भी नहीं खोया है। अंत में रक्षा मंत्री ने सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया है कि वे देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और राष्ट्र हमेशा सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद रखेगा।

बजट में गरीबों, बेरोजगारों की अनदेखी : चिदंबरम

नई दिल्लीः पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट प्रस्तावों में गरीबों, बेरोजगारों और एमएसएमई क्षेत्र की अनदेखी की है। राज्यसभा में बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सबसे योग्य को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है- गरीब, किसान, प्रवासी श्रमिक, एमएसएमई क्षेत्र, मध्यम वर्ग और बेरोजगार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बजट को 'अस्वीकार' कर दिया, क्योंकि इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि सभी को उम्मीद थी, लेकिन गरीबों के लिए नकद हस्तांतरण नहीं हुआ। चिदंबरम ने कहा कि बजट में रक्षा क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और इसमें अनुमानित संख्या सही नहीं है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रक्षा का उल्लेख नहीं किया, जो अभूतपूर्व है। 2021-22 में रक्षा के लिए बजटीय आवंटन 3,47,088 करोड़ रुपये है, जबकि चालू वर्ष में संशोधित अनुमान 3,43,822 करोड़ रुपये है।

किसान कानून वैकल्पिक हैं, अनिवार्य नहीं: पीएम मोदी

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को घोषणा की कि ये कानून 'वैकल्पिक हैं और अनिवार्य नहीं' हैं। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार तीन नए कृषि कानूनों पर किसानों के तार्किक सुझावों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए यह घोषणा की। दो महीने से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में मोदी ने कहा कि 'अफवाह फैलाई जा रही है कि ये कानून किसानों के खिलाफ हैं।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून संसद में कृषि क्षेत्र में सुधार के मद्देनजर पारित किए गए क्योंकि यह समय की आवश्यकता है। उन्होंने पूछा कि क्या इन तीनों कृषि कानूनों से किसानों की सुविधाओं को छीना जा रहा है, जो उन्हें पहले मिल रहे थे? पीएम ने कहा कि किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये कानून किसानों के विकास में बाधा पैदा नहीं करते हैं। ये कानून वैकल्पिक हैं, अनिवार्य नहीं हैं। ये कानून न तो पुराने 'मंडियों' को रोकते हैं और न ही इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उपज की खरीद प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को हमेशा सम्मानित किया है और सरकार उन्हें भविष्य में भी सम्मान देना जारी रखेगी। सरकार उनके साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी इन कानूनों पर उनके तार्किक सुझावों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनके साथ विभिन्न दौर की बातचीत की, जहां वे 26 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि हम अभी भी किसानों के साथ खुले दिल से बातचीत करने और इन तीनों कृषि कानूनों पर उनके सुझाव पर अमल करने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस कर रही गुमराह

यह दोहराते हुए कि 'इन कानूनों के पारित होने के बाद न तो कोई 'मंडियां बंद हुईं और न ही एमएसपी की खरीद प्रभावित हुईं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके विपरीत हमारे पास इस बजट में मंडियों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है और एमएसपी पर खरीद भी पहले की तुलना में बढ़ी है। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने लगातार उनके संबोधन के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की और विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता के व्यवधान उत्पन्न करने का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह 'हंगामा पूर्व-निर्धारित रणनीति के तहत एक प्रयास है।' उन्होंने कहा कि यह लोगों का समर्थन हासिल करने में आपकी (कांग्रेस) मदद नहीं करेगा। कृषि सुधार बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह आवश्यक है। कांग्रेस सदस्यों को इन कृषि कानूनों के कंटेंट और इरादे (कंटेंट एंड इंटेंट) पर चर्चा करनी चाहिए थी, उन्हें किसानों को गुमराह नहीं करना चाहिए और अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए।

एमएसपी पर नही पड़ेगा कोई प्रभाव

अयोध्या बनेगा विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल

ग्लोबल कंसल्टेंट को मिली अहम जिम्मेदारी

अयोध्याः रामनगरी अयोध्या को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सरकार ने ग्लोबल कंसल्टेंट एलईए एसोसिएट्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को 'भव्य अयोध्या' की योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। एलईए के साथ एलएंडटी व सीपी कुकरेजा कंसोर्टियम पार्टनर होगी। इन कंपनियों के पास अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों को सजाने-संवारने का अनुभव है।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि प्री क्वालीफाइड बिडर्स की तकनीकी बिड्स के परीक्षण व प्रस्तुतिकरण में शासन की ओर से प्रमुख सचिव (आवास) दीपक कुमार की अध्यक्षता में गठित बिड-इवैल्यूएशन कमिटी ने आरईपी के मानकों के अनुसार बिडर्स को अंक दिए। इसमें 70 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले तीन बिडर्स कंसोर्टियम मेसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, मेसर्स एलईए एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रा.लि. व मेसर्स आईपीइ ग्लोबल लिमिटेड को फाइनेंसियल बिड के लिए अर्ह पाया गया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ के सभागार में 10 फरवरी को सभी अर्ह पाए गए बिडर्स कंसोर्टियम, उनके प्रतिनिधियों व बिड-इवैल्यूएशन कमेटी की उपस्थिति में फाइनेंसियल बिड खोली गई। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 26 दिसंबर 2020 को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) प्रकाशित किया। इसके माध्यम से ग्लोबल कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए देश समेत अन्य सभी प्रमुख देशों के मीडिया, अखबार व अन्य प्रचार माध्यमों से निविदा आमंत्रित की गई। सभी से आरएफपी के माध्यम से 'भव्य अयोध्या' के विकास के लिए विजन डाक्यूमेंट, इम्प्लिमेंटेशन स्ट्रेटजी और इंट्रीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना मांगी गई, ताकि एक ग्लोबल कंसल्टेंट का चयन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई साल से अयोध्या के समन्वित विकास पर मंथन कर रहे थे। जिला प्रशासन समेत सरकार के कई विभागों और निजी एजेंसियों ने इसके लिए योजनाएं दीं, मगर कहीं न कहीं खामी के चलते भव्य अयोध्या का खांका उलझ जाता था।

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 अप्रैल से

लखनऊः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने 10 फरवरी को वर्ष 2021 के इम्तिहान की तिथियों का ऐलान कर दिया है। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई को खत्म होंगी। हाईस्कूल की परीक्षाएं 12 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 10 मई को समाप्त होंगी, वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 12 मई को खत्म होंगी।

उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि वर्ष-2021 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक 24 अप्रैल, 2021 से प्रारम्भ होंगी। हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा 12 कार्य दिवसों में संपन्न होकर दिनांक 10 मई को समाप्त होगी, वहीं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 15 दिवसों में संपन्न होकर दिनांक 12 मई 2021 को समाप्त होंगी। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष 2020 में भी हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा 12 कार्य दिवसों में तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में संपन्न हुई थी।

2 साल तक जारी रहेगी सांसद निधि पर रोक

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच सांसद निधि पर 2 वर्षों तक रोक जारी रहेगी। दो वर्षों से पहले सांसद निधि जारी करने की कोई तैयारी नहीं है। सरकार ने यह जवाब कुछ सांसदों की ओर से राज्यसभा में सांसद निधि पर लगी रोक को लेकर उठाए गए सवाल पर दिया है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले साल कोविड-19 का हवाला देते हुए सांसद निधि जारी करने पर रोक लगा थी। राज्यसभा में सांसद सस्मित पात्रा, ए विजय कुमार और बी लिंग्याह यादव ने गुरुवार 11 फरवरी को एक अतारांकित सवाल में पूछा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपी-एलएडी) योजना को अब तक रोके जाने के क्या कारण हैं ? निधि जारी करने की मांगों पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि इससे राज्यों में स्थानीय विकास की परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है। क्या ऐसी कोई संभावना है कि कोविड-19 के कारण रोकी गई सांसद निधि निर्धारित दो वर्षों के पहले जारी की जाएगी ?

इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने दो वर्षों के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया है। सरकार ने राज्यसभा में यह भी बताया है कि कोविड-19 के कारण रोकी गई सांसद निधि को दो वर्ष से पहले जारी करने की कोई संभावना नहीं है।

योगी सरकार का दावा, हो चुका 97 .07 फीसदी गन्ना बकाया का भुगतान

गन्ने को 'ग्रीन गोल्ड' बनाने के प्रयास में सरकार

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दावा किया है कि गन्ना बकाए का 97.07 फीसद भुगतान हो चुका है। विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, अब तक गन्ना बकाए का 97.07 फीसद (34847.60 करोड़ रुपए) का भुगतान हो चुका है। भुगतान की यह प्रक्रिया रोज जारी है। अत्याधुनिक नई मिलें, पुरानी मिलों की बढ़ी क्षमता, खांडसारी इकाईयां और एथनाल इसमें और मददगार साबित होने जा रही हैं। मालूम हो कि प्रदेश में गन्ना किसानों की बड़ी संख्या के नाते राजनीतिक रूप से यह बेहद संवेदनशील फसल है। गन्ना मूल्य के बकाये से लेकर पेराई न होना आदि बड़ा मुद्दा बन जाता है। मार्च-2017 में योगी सरकार के आने के पहले बकाया बड़ा मुद्दा था। सरकार ने आने के साथ ही पहला फोकस बकाये के भुगतान पर किया और रिकॉर्ड भुगतान भी किया।

योगी सरकार ने किए सराहनीय कार्य

गोरखपुर के पिपराइच, बस्ती के मुंडेरवा और बागपत के रमाला में अत्याधुनिक और अधिक क्षमता की नई मिलें लगायी गयीं। उल्लेखनीय है कि बसपा और सपा शासनकाल में 2007 से 2017 के दौरान बंद होने वाली 29 मिलों को देखते हुए नयी मिलों को खोलना और पुरानी मिलों का आधुनिकीकरण किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम रहा। स्थानीय स्तर पर गन्ने की पेराई हो, इसके लिए 25 साल बाद पहली बार किसी सरकार ने 100 घंटे के अंदर खांडसारी इकाईयों को ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था की। सरकार के अनुसार, मौजूदा समय में 105 से अधिक इकाईयों को लाइसेंस निर्गत किया जा चुका है। इससे पेराई क्षमता में 27850 टीडीएस की वृद्धि हुई है। लोग गुड़ के गुण और स्वाद को जानें इसके लिए सरकार ने मुजफ्फरनगर में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। करीब 6 दर्जन मिलों के को-जेनरेशन प्लांट से 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

यूपी देश का सर्वाधिक आपूर्ति करने वाला राज्य

सरकार एथनॉल के जरिए गन्ने को ग्रीन गोल्ड बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयास से अब उप्र देश का सर्वाधिक (126.10 करोड़ लीटर वार्षिक) आपूर्ति करने वाला राज्य बन चुका है। कुल 50 आसवानियां एथनॉल बना रही हैं। पिछले वर्ष दो मिलें हैवी मोलासिस से एथनॉल बना रही थीं। इस साल इनकी संख्या बढ़कर 20 हो गयी। पेराई और भुगतान के साथ सरकार ने चीनी की रिकवरी (11.46 फीसद) के क्षेत्र में भी रिकॉर्ड बनाया। गन्ने की ढुलाई का मानक प्रति क्विंटल करने से भी किसानों को लाभ हुआ। पहले सरकार 8.75 रुपये प्रति किमी की दर से भुगतान करती थी, इसे बदलकर 42 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया गया। फर्जी बांड गन्ना माफियाओं का सबसे प्रभावी हथियार था। सरकार ने दो लाख से अधिक फर्जी बांड रद्द कर इन माफियाओं की कमर तोड़ दी।

भारत के कारण ही कोरोना पर जीत पा सकेगी दुनियाः कनाडा

नई दिल्लीः कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 10 फरवरी को कोविड-19 टीके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, जिसे भारत ने अपने वैक्सीन कूटनीति के तहत 20 देशों को उदारतापूर्वक गिफ्ट किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ट्रूडो ने मोदी को भारत से कोविड-19 टीके के लिए कनाडा की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाया कि भारत कनाडा के टीकाकरण प्रयासों में मदद करने की पूरी कोशिश करेगा, जैसा कि उसने पहले ही कई देशों के लिए किया है।

ट्रूड्रो ने सराहना करते हुए कहा कि अगर दुनिया कोविड-19 पर जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल करती है तो यह भारत की जबरदस्त फार्मास्यूटिकल क्षमता के कारण होगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस क्षमता को दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ साझा किया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्रूडो को उनकी सराहना, भावनाओं के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा द्वारा कई महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक मुद्दों पर साझा किए गए आम परिप्रेक्ष्य को भी दोहराया। वे जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभावों जैसी वैश्विक चुनौतियों से लड़ने में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग को जारी रखने पर सहमत हुए। दोनों नेता इस साल के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे से मिलने और आपसी हित के सभी मुद्दों पर अपनी चर्चा जारी रखने को लेकर उत्सुक हैं।

3 महीनों में हुई 2 .47 लाख घरेलू हिंसा की शिकायतें

नई दिल्लीः कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में थे, तब महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं भी काफी हुईं। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 11 फरवरी को राज्यसभा में बताया कि लॉकडाउन के तीन महीनों में कुल 2.47 लाख से अधिक शिकायतें महिला हेल्पलाइन पर दर्ज हुईं।

दरअसल, भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. विकास महात्मे ने पूछा था कि लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच की अवधि के दौरान कितनी महिलाओं ने घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत के लिए राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हेल्पलाइन का प्रयोग किया है? इस अतारांकित सवाल का लिखित जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने बताया कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं को आपातकालीन सहायता देने के लिए महिला हेल्पलाइन स्थापित है, जिसका टोल फ्री नंबर 181 है। अप्रैल 2020 से जून 2020 की अवधि के दौरान महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 2.47 लाख से अधिक फोन कॉल दर्ज हुई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि महिला हेल्पलाइन देश के सात सौ जिलों में स्थापित वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के कोआर्डिनेशन में कार्य कर रहे हैं।

साप्ताहिक राशिफल

15 से 21 फरवरी

इस सप्ताह फिर आपके लिए प्रस्तुत है, आपकी लग्नराशि पर आधारित कलाशांति ज्योतिष साप्ताहिक राशिफल। जानिए, यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपको क्या-कुछ देने वाला है। आपके लिए इस हफ्ते क्या-क्या करना फायदेमंद रहेगा और परेशानियों से बचने के लिए कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी।

मेष लग्नराशिः इस सप्ताह धन के आवागमन को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग बनेंगे। विधार्थी वर्ग को अच्छे समाचार मिल सकते हैं। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। कई प्रकार के विचारों के चलते मन विचलित रह सकता है। कार्यक्षेत्र में भाग-दौड़ बनी रह सकती है। हफ्ते का अंतिम भाग कुछ तनाव दे सकता है, वाणी पर संयम रखें।

वृषभ लग्नराशिः इस सप्ताह धन लाभ को लेकर स्थिति अच्छी बनी रहेगी। इस हफ्ते सरकारी तथा प्रॉपर्टी के कार्यों में आपको लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह उत्तम समाचार और आर्थिक लाभ की संभावना है। मन में एक अद्भुत उमंग रहेगी। दोस्तों और परिवार वालों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिकारी गण प्रसन्न रहेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं।

मिथुन लग्नराशिः इस हफ्ते भाग्य का साथ आपको कोई लाभ दिला सकता है। नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग द्वारा दिए गए इंटरव्यू में सफलता मिलने की उम्मीद है। धन से जुड़ी समस्याओं में इस हफ्ते आपको राहत मिलेगी। अचानक से अटका हुआ पैसा इस हफ्ते आपको मिल सकता है। सेहत को लेकर सतर्कता बनाए रखें। हफ्ते का अंत कुछ समस्या दे सकता है।

कर्क लग्नराशिः इस सप्ताह व्यापारिक साझेदारों से वैचारिक मतभेद रह सकता है। मन को शांत रखने का प्रयास करें, उत्तम रहेगा। रुके हुए कार्यो को गति मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। इस हफ्ते पराक्रम बहुत बढ़ा-चढ़ा रहेगा। प्रेम संबंध में अनबन हो सकती है। संतान की सेहत को लेकर आप कुछ परेशान हो सकते हैं। धन का निवेश सोच-समझ कर करें।

सिंह लग्नराशिः इस सप्ताह की शुरुआत में कुछ व्यर्थ के खर्च और भाग-दौड़ आपको परेशान कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं। सेहत संबंधी मामलों में सुधार होगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। कार्य से संबंधित कोई यात्रा का योग बन सकता है। भाग्य का साथ बना रहने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। क्रोध से बचें।

कन्या लग्नराशिः नौकरी-पेशा वर्ग को थोड़ी सावधानी के साथ अपना कार्य करना पड़ सकता है। सरकारी कार्यों में चल रही परेशानी समाप्त होगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। संतान की ओर से परेशानी रह सकती है। पेट संबंधी कोई विकार रह सकता है। आलस्य से बचें। जीवन-साथी से लाभ मिल सकता है।

तुला लग्नराशिः इस सप्ताह लोगों से मतभेद रह सकता है। नौकरी-पेशा वाले जातकों को थोड़ा संभलकर रहना पड़ सकता है। बेरोजगार जातकों को रोजगार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर इस हफ्ते आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लोग कुछ नए कार्य में दिमाग लगा सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा।

मीन लग्नराशिः इस सप्ताह धन को लेकर स्थितियां पहले से और अधिक मजबूत होती नजर आ सकती हैं। कार्यों के मनोनुकूल परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा। नौकरी और व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह हफ्ता बहुत बढ़िया गुजर सकता है। स्वास्थ्य की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। उपहार और सम्मान की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आलस्य से बचें।

वृश्चिक लग्नराशिः इस सप्ताह आपके पराक्रम में कमी रहेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहने की संभावनाएं बन सकती हैं। नौकरी कर रहे जातकों को इस हफ्ते अच्छा लाभ मिल सकते है। माता से प्रेमभाव बढ़ेगा। भाग-दौड़ रहने से शारीरिक कमजोरी रह सकती है। ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है।

धनु लग्नराशिः स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और चल रही कोई पुरानी बीमारी में राहत मिल सकती है। नौकरी कर रहे जातकों के लिए लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। नौकरी से संबंधित नए विकल्प सामने आ सकते हैं। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहने वाला है।

मकर लग्नराशिः इस सप्ताह नौकरी कर रहे जातकों को अतिरिक्त कार्य मिल सकते हैं। शादी-शुदा जिंदगी में चल रही परेशानियों में राहत मिल सकती है। धनलाभ के योग बन सकते हैं। मकान, जमीन और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में अड़चनें दूर हो सकती हैं। व्यर्थ के कार्यों से दूर रहें। छात्र वर्ग को इस हफ्ते अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। संतान से मन-मुटाव संभव है। निवेश से बचें।

कुंभ लग्नराशिः इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय अच्छा बना रहेगा और कार्यक्षेत्र में आप नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। किसी प्रकार की व्यापारिक डील आपके पक्ष में आ सकती है। अटके हुए पैसों को लेकर स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं।

(ज्योतिषी विशाल वाष्णेय कलाशांति ज्योतिष के संस्थापक हैं। यह साप्ताहिक राशिफल आपकी लग्नराशि के आधार पर आधारित है। ये समस्त राशिफल सामान्य हैं। किसी भी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए ज्योतिषी से दशा-अंतर्दशा और जन्मपत्री का पूर्ण रूप से अध्ययन कराना उचित रहता है।)

इस बार सरकार लेगी 12 लाख करोड़ का कर्ज

आय से ज्यादा होता है सरकार का खर्च, कोरोना ने बिगाड़ी देश के खजाने की सेहत

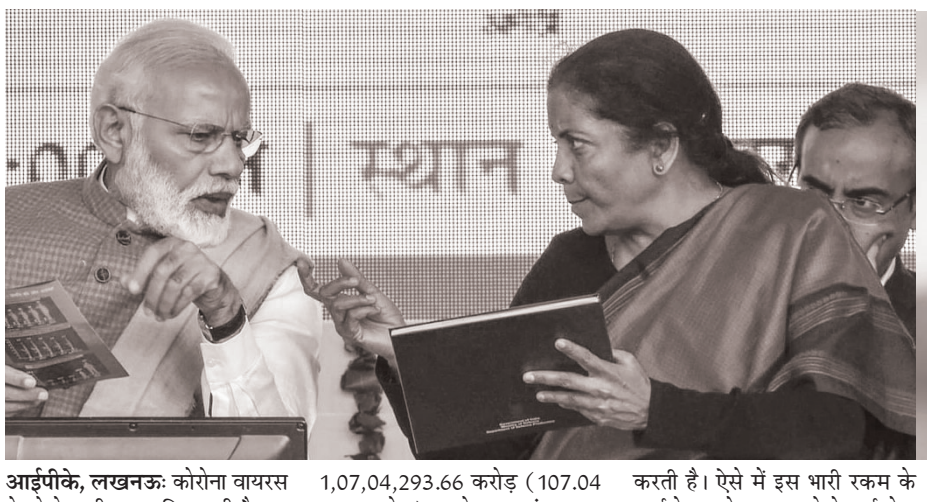

आईपीके, लखनऊः कोरोना वायरस ने पूरे देश की हालत बिगाड़ दी है। हर क्षेत्र में इस महामारी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में देश के खजाने की हालत भी काफी दयनीय हो गई है। अब इस हालत को दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार भारी रकम कर्ज में लेने जा रही है। इस बार के बजट में सरकार ने यह ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार करीब 12 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। आपको बता दें कि मौजूदा साल यानी 2020-21 में भी सरकार ने करीब इतना ही कर्ज लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार ये कर्ज क्यों लेती है और कैसी लेती है ?

इसलिए लेना पड़ता है कर्ज

कर्ज की वजह से ही मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड 9.5 फीसदी होगा और यह अगले साल 6.8 फीसदी होगा। सितंबर 2020 तक भारत का कुल सार्वजनिक कर्ज 1,07,04,293.66 करोड़ (107.04 लाख करोड़) रुपये तक पहुंच गया। जो कि जीडीपी के करीब 68 फीसदी के बराबर है। इसमें आंतरिक कर्ज 97.46 लाख करोड़ और बाह्य कर्ज 6.30 लाख करोड़ रुपये का था। यही नहीं वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में कर्ज-जीडीपी अनुपात 67-68 फीसदी के बीच रहा है। सार्वजनिक कर्ज में केंद्र और राज्य सरकारों की कुल देनदारी आती है, जिसका भुगतान सरकार के समेकित फंड से किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार कर्ज लेती क्यों है ? सरकार कर्ज इसलिए लेती है, क्योंकि असल में सरकार का खर्च उसकी आय से हमेशा ज्यादा होता है। चूंकि हर साल सरकार परिस्थितियों के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे कल्याण और विकास कार्यों पर एक बड़ी रकम खर्च करती है। ऐसे में इस भारी रकम के खर्च के चलते सरकार को ये कर्ज लेना पड़ता है।

सरकार कैसे लेती है कर्ज

अब बात करते हैं कि सरकार कर्ज कैसे लेती है ? आपको बता दें कि सरकार दो तरह से कर्ज लेती है, इंटर्नल और एक्सटर्नल। इंटर्नल यानी की देश के भीतर लिया गया कर्ज और एक्सटर्नल कर्ज वो कर्ज जो देश के बाहर से लिया गया हो। आंतरिक कर्ज कर्ज बैंकों, बीमा कंपनियों, रिजर्व बैंक, कॉरपोरेट कंपनियों, म्यूचुअल फंडों आदि से लिया जाता है, वहीं बाहरी कर्ज मित्र देशों, आईएफएम विश्व बैंक जैसी संस्थाओं, एनआरआई आदि से लिया जाता है, लेकिन सरकार बाहरी कर्ज को ज्यादा नहीं लेना चाहती है क्योंकि बाहरी कर्ज सरकार को अमेरिकी डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा में चुकाना पड़ता है। बाहरी कर्ज सरकार इसलिए भी नहीं लेना चाहती क्योंकि विश्व बैंक के अनुसार अगर किसी देश में बाहरी कर्ज उसके जीडीपी के 77 फीसदी से ज्यादा हो जाए तो उस देश को आगे चलकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।ऐसा होने पर किसी देश की जीडीपी 1.7 फीसदी तक गिर जाती है, जो किसी भी सरकार के लिए काफी बुरा है। वहीं आंतरिक कर्ज की बात करें तो सरकार सरकारी प्रतिभूतियों यानी सिक्यूरिटीज के द्वारा कर्ज लेती है। मार्केट स्टेबिलाइजेशन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल स्पेशल सिक्योरिटीज, गोल्ड बॉन्ड, स्माल सेविंग स्कीम, कैश मैनेजमेंट बिल आदि के द्वारा जो भी पैसा आता है, वह सरकार के लिए एक कर्ज ही होता है। दरअसल, जब कोई किसी जी-सेक या सरकारी बॉन्ड में निवेश करता है तो वह एक तरह का सरकार को कर्ज ही देता है, जिसे सरकार एक निश्चित समय के बाद लौटा देती है। साथ ही एक निश्चित ब्याज भी देती है। जो जी-सेक एक साल से कम अवधि के होते हैं, उन्हें ट्रेजरी बिल कहते हैं वहीं एक साल से अधिक अवधि वाले जी-सेक को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है। इसके अलावा राज्य सरकारें केवल बॉन्ड जारी कर सकती हैं, जिन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहा जाता है। साल 2001 से इसमें आम निवेशकों यानी सभी लोगों को निवेश करने का अधकार दिया गया, लेकिन आम निवेशकों के लिए सिर्फ 5 फीसदी हिस्सा मिलता है। यानी यदि कोई जी-सेक 100 करोड़ रुपये का है तो सिर्फ 5 करोड़ रुपये आम जनता से लिए जाएंगे।

ऑफ बजट कर्ज भी लेती है सरकार

ये सारे कर्ज तो सरकार के बजट में आते हैं, इनका सरकार को बजट में ज़िक्र करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा कुछ कर्ज ऐसा होता है जिसका सरकार बजट में कोई ज़िक्र नहीं करती, इसे 'ऑफ बजट' कहा जाता है। दरअसल ये कर्ज सीधे केंद्र सरकार नहीं लेती है, इसलिए इसका असर राजकोषीय घाटे में नहीं दिखाया जाता है। ये कुछ सार्वजनिक कंपनियों, सरकारी संस्थाओं के लोन या डेफर्ड पेमेंट के रूप में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोन संस्थान सरकार के निर्देश पर ही लेते हैं, लेकिन इसे चुकाने की जवाबदेही सरकार पर नहीं होती इसलिए इसे बजट में शामिल नहीं किया जाता।

कर्ज से पड़ता है ये फर्क

अब सबसे अहम सवाल जिसका जवाब सभी को जानना चाहिए कि सरकार के कर्ज लेने से क्या फर्क पड़ता है ? आपको बता दें कि जब केंद्र या राज्य सरकारों का कर्ज सीमा से बाहर हो जाता है तो रेटिंग एजेंसियां सरकार या राज्य सरकार की रेटिंग घटा देती हैं। अब इससे नुकसान ये होता है कि विदेशी निवेशक एफडीआई के रूप में निवेश से हिचकते हैं और कंपनियों के लिए भी कर्ज महंगा हो जाता है। होता ये है कि सरकार जब सभी संस्थाओं से कर्ज लेने लगती है तो कॉरपोरेट कंपनियों के लिए उधार के लिए पैसा कम बचता है या महंगा मिलता है। सरकार की उधारी पर सबकी नजर होती है, क्योंकि इसके बाद सभी कॉरपोरेट बॉन्ड या अन्य ब्याज दरें सरकारी ब्याज दर से ज्यादा ही रखी जाती हैं। यानी सरकारी बॉन्ड की ब्याज दर अगर बढ़ती है तो इसका मतलब यह है कि बाकी के लिए कर्ज और महंगा हो जाएगा।

कोक, पेप्सी और बिसलेरी पर 72 करोड़ का जुर्माना

15 दिन के अंदर जुर्माने के भुगतान का आदेश

आईपीके, लखनऊः गर्मियों में सभी को राहत देने वाली कोल्ड ड्रिंक कंपनियां कोक, पेप्सी और बिसलेरी पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गाज गिरा दी है। सीपीसीबी ने इन पर प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल और कलेक्शन की जानकारी सरकारी बॉडी को नहीं देने पर 72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब इन कंपनियों को 15 दिन के भीतर जुर्माने की राशि भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

सीपीसीबी ने बिसलेरी पर 10.75 करोड़ रुपये, पेप्सिको इंडिया पर 8.7 करोड़ रुपये और कोका कोला बेवरेजेस पर 50.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि प्लास्टिक कचरों के मामलों में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी एक पॉलिसी पैमाना है, जिसके आधार पर प्लास्टिक का निर्माण करने वाली कंपनियों को प्रोडक्ट के डिस्पोजल की जिम्मेदारी लेनी होती है। तीनों कंपनियों में सबसे ज्यादा का जुर्माना कोका कोला बेवरेजेस पर लगाया गया है। कोका कोला पर 50.66 करोड़ का जुर्माना लगा है। कोका कोला के पास 4,417 टन प्लास्टिक कचरा था, जिस पर 5 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगा है। इतना कचरा सिर्फ जनवरी से सितंबर 2020 के दौरान का था। इनके अलावा पतंजलि पर भी करीब 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि बिसलेरी पर 5 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया गया है। बिसलेरी का प्लास्टिक का कचरा करीब 21 हजार 500 टन था। वहीं पेप्सी के पास 11,194 टन प्लास्टिक कचरा था, जिस पर 8.7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ईपीआर का लक्ष्य 1 लाख 5 हजार 744 टन कचरे का था। कोका कोला ने सीपीसीबी से मिले नोटिस की पुष्टि करते हुए कहा कि हम सीपीसीबी के आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और संबंधित अथॉरिटी के साथ इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। वहीं पेप्सिको ने कहा कि हम प्लास्टिक कचरे के मामले में ईपीआर के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन करते हैं, फिर भी नोटिस मिला है तो उस पर विचार करेंगे।

राहतः फास्टैग में मिनिमम बैलेंस की बाध्यता खत्म

नई दिल्लीः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने फास्टैग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी है। जिससे फास्टैग वॉलेट में मिनिमम बैलेंस न होने पर भी आपकी गाड़ी हाईवे के टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगी। इससे वाहन चालकों को काफी सुविधा होगी और टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार नहीं लगेगी। हालांकि, अभी यह सुविधा वाहन कार, जीप, वैन को ही मिली है।

इस बारे में एनएचएआई ने बुधवार 10 फरवरी को सूचना जारी की है। फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की तरफ से सिक्योरिटी मनी के अलावा मिनिमम बैलेंस की भी बाध्यता की गई थी। जिसके कारण वाहन चालकों को कई बार टोल प्लाजा पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होने पर वह हाईवे के टोल प्लाजा से गुजर नहीं पाते थे। एनएचएआई ने यह निर्णय लिया है कि अगर किसी यूजर का खाता निगेटिव नहीं है, भले ही उसमें मिनिमम बैलेंस न हो, फिर भी वह टोल प्लाजा से गुजर सकता है। यदि टोल से गुजरने के बाद उसके खाते में पैसा नहीं बचता, तो फिर बैंक सिक्योरिटी मनी से धनराशि बैंक काट सकता है।

हालांकि, यूजर को अगली बार रिचार्ज के समय सिक्योरिटी मनी मेंटेन करना होगा। 2.54 करोड़ यूजर्स के साथ देश में कुल टोल कलेक्शन में फास्टैग का योगदान 80 प्रतिशत है। प्रतिदिन फास्टैग के माध्यम से टोल कलेक्शन 89 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। 15 फरवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल टैक्स भरना अनिवार्य हो जाएगा। एनएचएआई का लक्ष्य सौ प्रतिशत कैशलेस टोल टैक्स वसूली पर है। जिससे व्यवस्था सफल हो सके।

कोरोना काल में 456 फीसदी बढ़ा गेहूं निर्यात

आपदा को अवसर में बदलने का सटीक उदाहरण

नई दिल्लीः आपदा को अवसर में बदलने की सोच के साथ काम रही भारत सरकार ने कोरोना काल में देश के कृषि उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति दर्ज की है। चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के निर्यात में बीती तीन तिमाहियों में करीब 53 फीसदी का इजाफा हुआ है। खास तौर से गैर-बासमती चावल का निर्यात पिछले साल के मुकाबले करीब 123 फीसदी बढ़ा है जबकि गेहूं के निर्यात में 456 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से 10 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आरंभिक 9 महीनों में 22,856 करोड़ रुपये (306.8 करोड़ डॉलर) मूल्य का गैर-बासमती चावल का निर्यात किया है, जो पिछले साल के मुकाबले रुपये के मूल्य में 122.61 फीसदी ज्यादा है जबकि डॉलर के मूल्य में गैर-बासमती चावल का निर्यात पिछले साल 111.81 फीसदी बढ़ा है। पिछले वित्तवर्ष 2019-20 में देश से 10,268 करोड़ रुपये (144.8 करोड़ डॉलर) मूल्य का गैर-बासमती चावल का निर्यात हुआ था। भारत नेपाल, बेनीन, संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया, गिनिया के अलावा एशिया और यूरोप के कई देशों व अमेरिका को निर्यात करता है।

बासमती चावल और गेहूं के निर्यात में हुआ इजाफा

हालांकि, बासमती चावल का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान करीब 22,038 करोड़ रुपये (294.7 करोड़ डॉलर) मूल्य का हुआ जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले रुपये के मूल्य में 5.31 फीसदी जबकि डॉलर के मूल्य में 0.36 फीसदी का इजाफा हुआ है।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान आरंभिक 9 महीनों में 20,926 करोड़ रुपये (293.6 करोड़ डॉलर) मूल्य का बासमती चावल निर्यात हुआ था। भारत बासमती चावल का निर्यात मुख्य रूप से ईरान, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और यूरोपीय देशों को करता है। वहीं, गेहूं के निर्यात में बीती तीन तिमाहियों में जोरदार इजाफा हुआ है। भारत ने 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान 1,870 करोड़ रुपये (25.2 करोड़ डॉलर)मूल्य का गेहूं निर्यात किया है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में गेहूं का निर्यात 336 करोड़ रुपये (480 लाख डॉलर) मूल्य का हुआ। इस प्रकार गेहूं निर्यात में रुपये के मूल्य में 456.41 फीसदी जबकि डॉलर के मूल्य में 431.10 फीसदी का इजाफा हुआ है। भारत ने जिन देशों को गेहूं निर्यात किया है उनमें नेपाल, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

सभी अनाजों के निर्यात में हुआ 52.90 फीसदी का फायदा

सभी अनाजों की बात करें तो चालू वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में भारत ने 49,832 करोड़ रुपये मूल्य का अनाज निर्यात किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 52.90 फीसदी अधिक है। मक्का व अन्य मोटे अनाज का निर्यात आलोच्य अवधि के दौरान 3,067 करोड़ रुपये मूल्य का हुआ है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 189.09 फीसदी अधिक है। भारत ने मक्का व अन्य मोटे अनाज का निर्यात नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका, जर्मनी और जापान को किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले संगठन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगामुथु ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान निर्यात सुनिश्चि करने को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से चावल के निर्यात में जोरदार इजाफा हुआ। उन्होंने कहा, "कोविड-19 के दौरान सेहत संबंधी चुनौतियों को देखते हुए हमने सुरक्षा व हाईजीन की दृष्टि से कई कदम उठाए।''

लद्दाख में शुरू होगी भारत की पहली भू-तापीय ऊर्जा परियोजना

नई दिल्लीः एनर्जी प्रमुख ओएनजीसी लद्दाख में भारत की पहली भू-तापीय क्षेत्र विकास परियोजना (जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट) शुरू करेगी। योजना को औपचारिक रूप देने के लिए ओएनजीसी एनर्जी सेंटर (ओईसी) और केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद् के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा, ओएनजीसी की इस परियोजना से भारत भू-तापीय बिजली के मामले में वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा।

ओएनजीसी के बयान के अनुसार, भू-तापीय संसाधनों के विकास से लद्दाख में खेती में क्रांति आ सकती है। फिलहाल इस क्षेत्र में पूरे साल ताजी सब्जी, फल की आपूर्ति बाहर से होती है। प्रत्यक्ष ऊष्मा ऊर्जा अनुप्रयोग इसे लद्दाख के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। बयान के अनुसार, ओएनजीसी ने तीन चरणों में इसके विकास की योजना बनाई है। कंपनी ने अपने बयान में कहा, पहले चरण में 500 मीटर की गहराई तक कुंओं की खुदाई की जाएगी। यह खोज-सह-उत्पादन अभियान होगा। इसमें पायलट आधार पर एक मेगावाट तक की क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरे चरण में भू-तापीय क्षेत्र के लिए और गहराई में खोज की जाएगी। इसके तहत अनुकूलतम संख्या में कुओं की खुदाई की जाएगी और उच्च क्षमता के संयंत्र लगाए जाएंगे तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बयान में बताया गया, तीसरे चरण में भू-तापीय संयंत्र का वाणिज्यिक विकास किया जाएगा। इस समय पूर्वी लद्दाख में पुगा और चुमाथांग भारत में सबसे अधिक आशाजनक भू-तापीय क्षेत्र हैं।

नौसेना में हैं महिलाओं के लिए अपार अवसर

एयर ट्रैफिक कन्ट्रोलर में बना सकते हैं बेहतरीन करियर, सबसे अधिक होती है पायलटों की सैलरी

आईपीके, लखनऊः आज का समय बदल रहा है और महिलाएं भी अब हर क्षेत्र में पुरुषों के कदम से कदम मिला कर चल रही हैं। अब देश की सेवा करने में भी महिलाएं आगे आ रही हैं। ऐसे में अब महिलाएं भारतीय सेना की नौसेना विंग में भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि 1992 से पहले महिलाएं नौसेना सेना में शामिल नहीं हो सकती थीं, लेकिन 1992 से अब महिलाएं नौसेना में भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं।

नौसेना में महिलाओं के लिए कई अवसर हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना शार्ट सर्विस कमीशन प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों को शामिल करती है। उनकी एसएससी अवधि पूर्ण होने पर महिला नौसैनिक अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा सकता है, जो कि रिक्तियों की संख्या, मेरिट और उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित होता है। नौसेना में कई क्षेत्र हैं जिनमें महिलाएं आवेदजन कर सकती हैं।

एटीसी

नौसेना में जाने की इच्छुक महिलाओं के लिए एटीसी में महत्वपूर्ण स्थान हैं। एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कन्ट्रोलर। एटीसी के अंतर्गत वो महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जो आयु सीमा साढ़े 19 साल से 25 साल के अंतर्गत आती हैं। इस पद पर आवेदन करने वाली उम्मीदवारों के पास शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से विज्ञान संकाय अर्थात भौतिक शास्त्र/गणित/इलैक्ट्रोनिक्स में स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए।

ऑब्जर्बर

ऑब्ज़र्बर पद के लिए महिला उम्मीदवारों को 19 से 23 वर्ष के आयु समूह के अंतर्गत होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक उपाधि एवं 10+2 स्तर पर गणित एवं भौतिक शास्त्र का होना अनिवार्य है।

नॉवल आर्कीटेक्चर

भारतीय नौसेना की नेवल आर्कीटेक्चर विंग में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 21 से 25 वर्ष के आयु समूह में आना जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें न्यूनतम 60 प्रतिशत कुल अंकों के साथ नेवल आर्कीटेक्चर, मैकेनिकल, सिविल, एरोनौटिकल, मेटालर्जीकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बी.टेक/बी.ई उत्तीर्ण किया होना चाहिए। भारतीय नौसेना में महिला इंजीनियर एसएससी/यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम द्वारा ली जाती हैं।

पायलट जनरल

जो उम्मीदवार पायलट जनरल के पद में नौकारी करना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पद के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा 19 से 24 वर्ष है। उम्मीदवारों को 12 वीं कक्षा में भौतिकी और गणित के साथ किसी भी विषय में बीई/बीटेक की डिग्री होनी चाहिए।

लॉ

भारतीय नौसेना से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं की देख-रेख के लिए महिला उम्मीदवार सेवा की कानूनी विंग में शामिल हो सकती हैं। कोई भी महिला स्नातक, जो कि 22 से 27 वर्ष के आयु समूह में है इस पद पर आवेदन करने के लिए योग्य हैं। इसके लिए उम्मीदवारों के पास कानून की उपाधि अनिवार्य रूप से कुल 55 प्रतिशत अंकों के साथ पूर्ण की होनी चाहिए।

नौसेना आयुध निरीक्षक (एनआईए)

जो उम्मीदवार नौसेना आयुध निरीक्षक (एनआईए) में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उन महिलाओं की न्यूनतम आयु 19 वर्ष है और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। महिला उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी, केमिकल, धातुकर्म, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीई में बीटेक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

लॉजिस्टिक्स

नौसेना में लॉजिस्टिक्स में दिलचस्पी है तो आपके लिए अच्छे अवसर हैं। महिला उम्मीदवार जिनके पास वैध आर्कीटेक्चर, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मरीन, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग स्नातक उपाधि (बी.टेक/बी.ई) है, वे इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। वैकल्पिक रूप से उम्मीदवार जिन्होंने मैटीरियल मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम पूर्ण किया है वे भी पात्र हैं। इसके लिए आवश्यक आयु साढ़े 19 साल से 25 वर्ष है, जो कि विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार होती है।

एजुकेशन

भारतीय नौसेना की शिक्षा शाखा भी महिला उम्मीदवारों को कार्य प्रदान करती है। इस कार्य के लिए महिला उम्मीदवारों को 21 से 25 वर्ष तक के आयु समूह के अन्दर होना चाहिए। शैक्षणिक रूप से उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कम्प्यूटर सांइस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकेनिकल में बी.टेक/बी.ई पूर्ण किया होना चाहिए या गणित, भौतिक शास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं अन्य में एम.एससी. होना चाहिए।

सैलरी

भारतीय नौसेना में देश की सेवा करने का अवसर तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ ही नौसेना में चयनित उम्मीदवारों को तनख्वाह भी अच्छी-खासी मिलती है। इसमें शुरूआत 15,000 रुपये महीने से होती है। उसके बाद पद के हिसाब से सैलरी बढ़ती रहती है और 40 से 50 हजार भी हो सकती है। वहीं पायलटों की सैलरी सबसे अधिक होती है।

हादसे में खो दिए दोनों हाथ, आज हैं सफल बिजनेसमैन

आईपीके, लखनऊः वो कहते हैं न कि अगर हौसले बुलंद हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मजबूत इरादों के आगे भगवान भी झुक जाते हैं और किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो बहादुर होते हैं और अपने हौसले बुलंद रखते हैं। ऐसे ही एक बहादुर और जाबांज हैं मूदबिदरी-कर्कला की जानी-मानी फर्म जीके डेकोरेटर्स के मालिक गणेश कामथ। गणेश के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन आज वो एक सफल बिजनेसमैन हैं, उनकी कंपनी का लाखों का टर्नओवर है। अपने दोनों हाथ गंवाने के बाद भी गणेश ने ये मुकाम हासिल किया है। आइए जानते हैं गणेश के संघर्ष की ये कहानी जो कई और लोगों को भी प्रभावित करेगी।

हादसे में खो दिए दोनों हाथ

वर्तमान समय में गणेश कर्नाटक के कर्कला में जीके डेकोरेटर्स नाम की एक फर्म चलाते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है। आज गणेश ज़रूर इस मुकाम पर हैं, लेकिन गणेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण गणेश ने 7वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जिसके बाद रोजगार कमाने के लिए गणेश ने इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रेक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन साल 2011 में गणेश के साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसने गणेश की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साल 2001 में कार्कला में एक आयोजन में गणेश को बल्ब ठीक करने को कहा गया। गणेश को एक फ्लड लाइट पर लाइट बल्ब ठीक करने के लिए 29 फीट ऊंचे मंच पर चढ़ने को कहा गया। जब वो लाइट ठीक कर रहे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे आ गिरे। नीचे गिरते ही गणेश बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया, तब जो उन्होंने देखा वो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि करंट के कारण वो अपने दोनों हाथ खो चुके हैं। गिरते वक्त गणेश पास में लगे पोल के तार के संपर्क में आ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें करंट लग गया और उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए। इस घटना ने गणेश की पूरी जिंदगी को हिला कर रख दिया। घर की पूरी जिम्मेदारी गणेश के ऊपर थी और गणेश की हालत ये थी। ऐसे में गणेश काफी परेशान रहने लगे। हमेशा अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगे जिससे गणेश पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए।

गणेश कामथ हैं सफलता की प्रतिमूर्ति

करने जा रहे थे आत्महत्या, ऐसे मिली सफलता

गणेश ने 13 साल तक जिस फर्म के लिए अपनी सेवाएं दी उस फर्म ने भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में गणेश का साथ छोड़ दिया। ऐसे में गणेश काफी परेशान रहने लगे, जिसके चलते गणेश ने परिस्थितियों से हार मान कर आत्महत्या करने का फैसला लिया, लेकिन गणेश की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। गणेश को एक रिश्तेदार ने आत्महत्या करने से रोक लिया। उसके बाद गणेश की ज़िंदगी ने एक और मोड़ लिया और गणेश की जिंदगी फिर से पूरी बदल गई।

करंट लगने के बाद एक्सीडेंटल बीमा से जो पैसा मिला, उससे उन्होंने काम शुरू किया। गणेश ने दो म्यूजिक सिस्टम्स खरीदे और उन्हें शादी व अन्य आयोजनों में किराए पर देना शुरु कर दिया। शुरुआत में तो उन्हें 350 रुपये तक मिल जाते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनका यह बिज़नेस चल पड़ा और आज उनकी फर्म जीके डेकोरेटर्स का टर्नओवर लाखों में है। वो लाखों में पैसा कमा रहे हैं। गणेश की फर्म में 40 लोग काम कर रहे हैं। किस्मत का खेल देखिये कि जिस व्यक्ति के खुद के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन वो 40 लोगों को खाना खिला रहे हैं। गणेश के संघर्ष और सफलता की ये कहानी कई लोगों को प्रभावित करेगी और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखायेगी।

अंकिता रैना: नई टेनिस सनसनी

ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली 5वीं भारतीय, महिला युगल में मिला सीधा प्रवेश

आईपीके, लखनऊः इस समय टेनिस जगत में जो नाम चर्चा का विषय बना हुआ है वो है भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना का। अंकिता ने काफी कम समय में बड़ी पहचान बना ली है। अब अंकिता ने एक और इतिहास रचा है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला युगल के ड्रॉ में जगह बना ली है।

इस तरह अंकिता किसी ग्रैंडस्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली 5वीं भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बन गयी हैं। 28 वर्षीय अंकिता ने रोमानिया की मिहेला बुजारनेकु के साथ जोड़ी बनायी है और उन्हें महिला युगल में सीधा प्रवेश मिला है। अंकिता से पहले निरुपमा मांकड़ (1971), निरुपमा वैद्यनाथन (1998), सानिया मिर्जा और भारतीय अमरीकी शिखा ओबरॉय (2004) ने ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई थी।

सानिया के बाद दूसरी भारतीय

अंकिता रैना 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा के बाद ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के महिला युगल में भाग लेगे वाली दूसरी भारतीय हैं। सबसे पहले साल 1998 में निरुपमा ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में ही एकल के मुख्य ड्रा में जगह बनायी थी। अपनी इस उपलब्धि पर अंकिता काफी खुश हैं। अपने इस कीर्तिमान के बारे में बात करते हुए अंकिता ने कहा, 'यह ग्रैंडस्लैम का मेरा पहला मुख्य ड्रॉ है। इसलिए, यह एकल है या युगल मैं इससे खुश हूं। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद मैं यहां तक पहुंची हूं। केवल कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से भी मैं यहां पहुंच पायी हूं। मैं इसे नहीं भूल सकती।' अंकिता ने कहा कि पहले उन्होंने ड्रॉ में अपना नाम नहीं देखा तो उन्हें काफी निराशा हुई। उन्होंने कहा, 'मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे ड्रॉ में अपना नाम नहीं दिखा। अभ्यास के बाद मैंने ड्रॉ देखा और उत्सुकता में अपना नाम ढूंढा लेकिन मुझे अपना नाम नहीं दिखा। इसके बाद मेरे कोच ने मुझे बताया कि मुझे ड्रॉ में जगह मिली है।' 28 साल की अंकिता और बाएं हाथ से खेलने वाली मिहेला पहले दौर में वाइल्ड कार्ड से प्रवेश पाने वाली ऑस्ट्रेलियन जोड़ी ओलिविया गाडेस्की और बेलिंडा वूलकॉक से भिड़ेंगी। अंकिता ने कहा, 'एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मिहेला जोड़ीदार ढूंढ रही हैं। मैंने उनसे बात की और वह तैयार हो गईं। मैं इससे पहले उनके साथ नहीं खेली हूं, लेकिन मैं बाएं हाथ के खिलाड़ी के साथ खेली हूं। इससे यह अच्छा संयोजन बन गया है। मैं इसे लेकर उत्साहित हूं।'

सिंगल्स के क्वॉलिफायर्स के फाइनल राउंड में मिली थी हार

अंकिता को पिछले महीने दुबई में खेले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 क्वालिफायर्स के फाइनल राउंड में हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें ओल्गा डैनिलोविच ने हराया था। वह छठी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स का क्वॉलिफायर्स खेली थीं। हालांकि, डबल्स के मेन ड्रॉ में उन्हें डायरेक्ट एंट्री मिल गई है।

चार भारतीय ग्रैंड स्लैम में लेंगे हिस्सा

इस तरह से साल के पहले ग्रैंडस्लैम में चार भारतीय खेलेंगे। सुमित नागल पुरुष एकल में जबकि रोहन बोपन्ना और दिविज शरण युगल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। नागल पहले दौर में लिथुआनिया के रिकार्ड बेरांकिस से भिड़ेंगे। बोपन्ना ने जापान के बेन मैक-लाचलान के साथ जोड़ी बनाई है और वे पहले दौर में जी सुंग नाम और मिन कियु सोंग कोरियाई जोड़ी का सामना करेंगे। शरण और स्लोवाकिया के उनके जोड़ीदार इगोर जेलेनी पहले दौर में जर्मनी के यानिक हाफमैन और केविन क्रावित्ज से भिड़ेंगे।

ऐसे की सफर की शुरूआत

11 जनवरी 1993 को जन्मी भारत की नई टेनिस स्टार अंकिता रैना ने 2009 में मुंबई के एक छोटे से आईटीएफ टूर्नामेंट में अपना पहला पेशेवर खेल खेला। जिसके बाद 2011 के सीज़न में अंकिता डबल्स में तीन आईटीएफ सर्किट फाइनल में पहुँची, जिसमें से एक में उन्होंने देश की ही ऐश्वर्या अग्रवाल के साथ जीत दर्ज की। वहीं 2012 में, अंकिता ने नई दिल्ली में अपना पहला पेशेवर एकल खिताब जीता और युगल में तीन और खिताब जीते। इसके बाद अंकिता ने अपना शानदार प्रदर्शन ज़ारी रखा। जिसका नतीजा ये रहा कि अंकिता साल 2018 में निरुपमा संजीव, सानिया मिर्ज़ा, शिखा ओबेरॉय और सुनीता राव के बाद महिला एकल रैंकिंग के शीर्ष 200 में जगह बनाने वाली पाँचवीं भारतीय बनीं। इसी साल अगस्त 2018 में, अंकिता ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई खेलों में एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अंकिता सानिया मिर्ज़ा के बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एशियाई खेलों में एकल पदक जीता है।

दूसरा टेस्ट हारते ही कोहली को इस्तीफा दे देना चाहिए: पनेसर

लगातार 4 टेस्ट मैच हार चुका है भारत

नई दिल्लीः इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने कहा है कि भारत अगर इंग्लैंड के खिलाफ हो रहा दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाता है, तो विराट कोहली को कप्तानी से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम लगातार चार टेस्ट मैच हार चुकी है। बता दें कि भारत को चेन्नई में बीते 9 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ 227 रन की हार मिली और इससे पहले, भारत को एडिलेड, क्राइस्टचर्च और वेलिंगटन में भी कोहली की कप्तानी में हार का सामना करना पड़ा था। इन हार के बाद अब कोहली की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं।

पनेसर ने वियोन से कहा कि विराट कोहली अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं, लेकिन टीम अब उनकी कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और हमारे पास कोहली की कप्तानी में खेले गए भारत के अंतिम चार टेस्ट मैचों के परिणाम हैं। मुझे लगता है कि कोहली अभी और दबाव में होंगे, क्योंकि रहाणे ने कप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले रखी है। इंग्लैंड से मिली हार से पहले भारत अपने घर में पिछले 14 टेस्ट मैचों से अजेय था। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही उनकी कप्तानी में चार टेस्ट मैच हार चुका है और अगर अगले मैच में यह संख्या पांच हो जाती है, तो मुझे लगता है कि कोहली को अपने पद से हट जाना चाहिए। 2012-13 में भारत दौरे पर 17 विकेट लेकर इंग्लैंड की ऐतिहासिक सीरीज जीत में योगदान देने वाले पनेसर ने साथ ही कुलदीप यादव की जगह शाहबाज नदीम को खेलाने के टीम प्रबंधन के फैसले की कड़ी आलोचना की।

कोहली की कप्तानी में भारत पिछले वर्ष न्यूजीलैंड दौरे पर गया था, जहां उसे दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप झेलना पड़ा था। इसके बाद हाल में ऑस्ट्रेलिया दौरे में एडिलेड में खेले गए पहले दिन-रात्रि टेस्ट में उसे 8 विकेट से पराजय मिली थी। हालांकि इसके बाद कोहली अपने पहले बच्चे के जन्म को लेकर स्वदेश लौट गए थे और उनकी गैर-मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे ने टीम की कमान संभाली थी। रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान तीन टेस्ट मुकाबलों में कप्तानी की थी, जिसमें भारत ने मेलबर्न टेस्ट जीता, जबकि सिडनी टेस्ट ड्रॉ रहा। इसके बाद ब्रिस्बेन में खेले गए अंतिम मुकाबले में भारत को जीत मिली और उसने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। इंग्लैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए कोहली की टीम में वापसी हुई और उनकी कप्तानी में एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा।

चिली दौरे पर हमारी मेहनत रंग लाई: संगीता

बेंगलुरूः भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर संगीता कुमारी का हाल ही में संपन्न चिली दौरे पर शानदार प्रदर्शन रहा था। भारतीय टीम इस दौरे पर अजेय रही थी और संगीता ने 5 मैचों में 4 गोल किए थे। संगीता ने कहा है कि लंबे अंतराल के बाद खेल में वापसी करने के बाद टीम की सफलता में योगदान करना उनके लिए एक शानदार अहसास है।

संगीता ने कहा कि मैं काफी लंबे समय के बाद खेल रही थी क्योंकि 2019 में मैं चोटिल हो गई थी। इसके बाद कोविड-19 की वजह से मैदान से दूर रही। टीम की जीत में योगदान देना बहुत अच्छा लगा। चिली दौरे पर भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने 6 में से 5 मैच जीते थे जबकि एक मैच ड्रॉ रहा था। उन्होंने टीम के प्रदर्शन को लेकर कहा कि महामारी के कारण 2020 में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होने के बावजूद हमने चिली में अच्छा प्रदर्शन किया। हमने दौरे के लिए शिविर में वास्तव में कड़ी मेहनत की थी, जोकि रंग लाई।

दौरे पर अजेय रही थी भारतीय टीम

झारखंड की संगीता ने 2016 गर्ल्स अंडर-18 एशिया कप के दौरान आठ गोल किए थे और टीम को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह हॉकी झारखंड टीम का भी हिस्सा थीं, जिसने 9वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2019 (ए डिवीजन) जीती थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 2019 में झारखंड के लिए जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं अपने खेल में सुधार के लिए कड़ी मेहनत कर रही हूं। संगीता का अब जूनियर महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाना उनका लक्ष्य है। महिला एशिया कप इस साल अप्रैल में जापान में होना है। 19 साल की संगीता ने कहा कि हम जल्द ही इस सप्ताह अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि चिली दौरे ने हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि हम शिविर में और फिर जूनियर महिला एशिया कप में उसी तरह के फॉर्म को जारी रख सकते हैं।

पंत बने पहले 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ'

नई दिल्लीः भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड दिया है। पंत को ये अवार्ड जनवरी माह के लिए मिला है। सोमवार 8 फरवरी को ICC ने इसकी घोषणा की। महिला क्रिकेटरों में साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल को यह अवॉर्ड मिला है। ICC ने पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की घोषणा की है। पंत ने इंग्लैंड के जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग को पीछे छोड़कर यह अवॉर्ड अपने नाम किया है। ICC के मुताबिक पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जनवरी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के आधार पर तीन-तीन खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद एक स्वतंत्र ICC वोटिंग एकेडमी और फैंस ने इन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को वोट किया। ICC वोटिंग एकेडमी में पूर्व क्रिकेटर्स, ब्रॉडकास्टर और खेल पत्रकार शामिल हैं। हर महीने इसी प्रक्रिया से दोनों वर्गों में प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाएंगे।

स्प्रिंटर हिमा दास बनेंगी डीएसपी, जारी रखेंगी दौड़ना

नई दिल्लीः केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अनुभवी स्प्रिंटर हिमा दास असम पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के रूप में नियुक्त होने के बाद भविष्य में भी भारत के लिए दौड़ना जारी रखेंगी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार 10 फरवरी को कैबिनेट बैठक में हिमा को डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया। रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा, कई लोग पूछ रहे हैं कि अब हिमा के स्पोर्ट्स करियर का क्या होगा। वह पटियाला के एनआईएस में ओलंपिक क्वालीफिकेशन की तैयारी कर रही हैं और वह भारत के लिए दौड़ना जारी रखेंगी।

खेल मंत्री ने दी हिमा को बधाई

खेल मंत्री ने कहा, हमारे एथलीट विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं और उन्होंने खेलना जारी रखा है। यहां तक कि संन्यास के बाद भी वे खेलों को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। इससे पहले, रिजिजू ने हिमा को डीएमसपी के पद पर नियुक्त करने के असम कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया और हिमा को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, शाबाश मुख्यमंत्री सबार्नंद सोनोवाल की अध्यक्षता में असम कैबिनेट ने असम पुलिस में धावक हिमा दास को डीएसपी पद की पेशकश करने का फैसला किया है। 'ढिंग एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर हिमा ने भी असम सरकार के इस फैसले के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा सरकार के इस फैसले से उन्हें अधिक प्रेरणा मिलेगी। हिमा ने ट्विटर पर लिखा, असम पुलिस में उपाधीक्षक नियुक्त करने पर मैं मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हिमांता बिस्वा सरमा सर को धन्यवाद देती हूं। इस फैसले से मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी।

तीन दिन में खेले गए 90 मैच

आईपीके, लखनऊः 25वीं अखिल भारतीय पोस्टल कैरम टूर्नामेंट के तीसरे दिन 12 फरवरी को महिला व पुरुष एकल एवं युगल प्रतिस्पर्धा में कुल 90 मैच खेले गए। कैरम के खेल में काफी अहम समझे जाने वाले दो व्हाइट स्लैम लगाए गए, जो मेजबान टीम के मोहम्मद ओवैस और तमिलनाडु के भारती दासन ने लगाए।

पुरुष एकल प्रतिस्पर्धाओं में किशोर तमिलनाडु, मोहम्मद ओवैस, यूपी ए इमरान खान यूपी, अखलाख असम, जलज बिहार, सुबोध बिहार, शिवानंद तेलंगाना, श्यामसुंदर कर्नाटक, सिल्वन तमिलनाडु, सुमन तमिलनाडु, इलाही ओडिशा, सिलम ब्रासन तमिलनाडु, भारती दासन तमिलनाडु, राजेश कर्नाटक, धारनि तमिलनाडु व जेपी दास छतीसगढ़ से प्री. क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पुरुष युगल में जलज और विवेक बिहार, सुमन व सिलम ब्रासन तमिलनाडु, शिवानंद व जीवा तेलंगाना, राजेश व श्याम सुंदर कर्नाटक, इलाही व जेके ओडिशा, मोहम्मद ओवैस व इमरान खान यूपी, के तमिल व धरनी तमिलनाडु तथा भारती दासन व किशोर तमिलनाडु से क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल हुए। महिला एकल में सोनल महाराष्ट्र, निवेदिता असम, रामा तेलंगाना, विनीता आंध्र प्रदेश, लिखिता महाराष्ट्र, लक्ष्मी तेलंगाना, भाग्य श्री महाराष्ट्र तथा सविता देवी तेलंगाना क्वार्टर फाइनल में पहुंची। महिला युगल में आशा व मुमताज तमिलनाडु, सोनल व भाग्यश्री महाराष्ट्र, एम सरकार व एम पाल पश्चिम बंगाल तथा सविता व रामा तेलंगाना से सेमीफा-इनल में प्रवेश करने में सफल रहीं। 13 फरवरी को महिला व पुरुष युगल के फाइनल मैच खेले गए। इस दौरान चीफ रेफरी रणवीर सिंह, सहायक रेफरी कुमार अजय, खेल विकास अधिकारी नूपुर सिंह और सहायक निदेशक विनीत कुमार शुक्ल स्टेडियम में मौजूद रहे।

धार्मिक आरोपों को जाफर ने बताया बेबुनियाद

नई दिल्लीः अपने ऊपर लगे धार्मिक आधार पर टीम के चयन के आरोपों का सामना कर रहे उत्तराखंड क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी भी खिलाड़ियों को 'जय श्रीराम' और 'जय हनुमान' का नारा लगाने से नहीं रोका। उत्तराखंड क्रिकेट संघ (सीएयू) के अधिकारियों ने जाफर पर आरोप लगाया है कि जाफर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए धार्मिक आधार पर राज्य टीम में खिलाड़ियों को शामिल कराने की कोशिश की थी। जाफर उस समय उत्तराखंड टीम के कोच थे, लेकिन अपने ऊपर आरोप लगने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

मेरे ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद

जाफर ने कहा कि पहली बात तो यह कि खिलाड़ी कभी भी टीम में 'जय श्रीराम' और 'जय हनुमान' का नारा नहीं लगाते हैं और न ही उन्होंने खिलाड़ियों को कभी ऐसा करने से रोका है। उन्होंने कहा, पहली बात तो यह कि इस तरह के नारे ('जय श्रीराम' और 'जय हनुमान') नहीं लगाते हैं। खिलाड़ी जब भी मैच में या अभ्यास मैच खेलते हैं तो वे 'रानी माता सच्चे दरबार की जय' कहते हैं। मैंने उन्हें कभी 'जय श्रीराम' और 'जय हनुमान' कहते नहीं सुना है। यह नारा ('रानी माता सच्चे दरबार की जय') सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है और हमारी टीम में दो खिलाड़ी इस समुदाय से थे, इसलिए वे ऐसे नारे ('रानी माता सच्चे दरबार की जय') लगाते थे। पूर्व टेस्ट बल्लेबाज ने आगे कहा कि उत्तराखंड की टीम जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने के लिए बड़ौदा पहुंची थी तब उन्होंने खिलाड़ियों को 'गो उत्तराखंड', 'लेट्स डू इट उत्तराखंड' या फिर 'कमऑन उत्तराखंड' जैसे नारे लगाने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें ऐसे नारे इसलिए लगाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि जब मैं विदर्भ की टीम में था, तब चंदू सर (कोच चंद्रकांत पंडित) इस तरह के नारे लगवाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि टीम में करीब 11-12 खिलाड़ी थे, जोकि विभिन्न समुदायों से थे। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। अगर मैं धार्मिक होता तो उन्हें 'अल्लाह हू अकबर' कहने के लिए प्रेरित करता।

कहा नहीं लगे कभी 'जय श्रीराम के नारे'

जाफर पर लगे थे धार्मिक भेदभाव करने के आरोप

भारत के लिए 31 टेस्ट मैचों में 1944 रन बनाने वाले जाफर के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ग्रुप चरण में पांच मैचों में से केवल एक ही मैच जीत पाई थी। सीएयू के अधिकारियों ने जाफर पर आरोप लगाया था कि जाफर ने ऑलराउंडर इकबाल अब्दुल्लाह को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उत्तराखंड की टीम का कप्तान बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन जाफर का कहना है कि उन्होंने जय बिस्ता को उत्तराखंड टीम का कप्तान बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन सीएयू के सचिव माहिम वर्मा और चयन समिति के चेयरमैन रिजवान शमशाद ने अब्दुल्लाह को कप्तान बनाए जाने की सिफारिश की थी। जाफर ने कहा, मैंने उनसे कहा था कि जय बिस्ता को कप्तान बनाया जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि वह युवा हैं और मैं चाहता हूं कि वह टीम का नेतृत्व करे। वे सहमत हो गए थे। लेकिन बाद में शमशाद और वर्मा ने कहा कि इकबाल अब्दुल्लाह को कप्तान बनाते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने आगे कहा, यह बेहद निराशा-जनक है। मैंने मेल में सबकुछ लिखा था। वे इसे धार्मिक एंगल देना चाहते हैं और मेरे खिलाफ धार्मिक आरोप लगा रहे हैं।

एथलीटों को 5 लाख रुपये देगी हरियाणा सरकार

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके एथलीटों को उनकी तैयारियों के लिए 5 लाख रुपये की राशि देने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार 10 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस तैयारी के साथ खिलाड़ियों को गुणवत्ता प्रशिक्षण और आहार प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इससे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिलेगा और राज्य तथा देश का नाम रोशन होगा।

भारत में ही कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं एंडरसन

चेन्नईः भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में 5 विकेट लेने के साथ ही इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के टेस्ट करियर में 611 विकेट हो गए हैं और अब वह भारत में ही टीम इंडिया के महानतम टेस्ट गेंदबाज अनिल कुंबले के 619 विकटों के रिकॉर्ड को तोड़ने के काफी करीब हैं। एंडरसन ने पहले मैच की दूसरी पारी में भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत के विकेट लिए और इंग्लैंड की सबसे बड़ी टेस्ट जीत में से एक की पटकथा लिखी।

इंग्लैंड ने भारत को पहले मैच में 227 रन से हराकर चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। अभी इस सीरीज में तीन टेस्ट और खेले जाने हैं। ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि कुम्बले का रिकॉर्ड तोड़कर एंडरसन टेस्ट इतिहास के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज बन जाएं। एंडरसन के 158 मैचों में 611 विकेट हैं और वह टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में चौथे स्थान पर हैं जबकि कुंबले ने 132 मैचों में 619 विकेट लिए हैं। इस सूची में पहले स्थान पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं जिनके नाम 133 मैचों में 800 विकेट हैं और दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न हैं जिन्होंने 145 मैचों में 708 विकेट लिए हैं।

एबी डी विलियर्स: नाम एक पर काम अनेक

मिस्टर 360 डिग्री के नाम से हैं मशहूर, 14 साल के करियर में बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

जन्म विशेष

आईपीके, लखनऊः भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है। यहां क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी एक अलग ही लेवल पर है। यहां सिर्फ देश के क्रिकेटर्स को ही नहीं, बल्कि विदेशी खिलाड़ियों की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। जिन विदेशी खिलाड़ियों को भारत में प्यार दिया जाता है, उनमें सबसे पहला नाम आता है क्रिकेट के 'मिस्टर 360 डिग्री' यानी एबी डी विलियर्स का।

एबी डी विलियर्स का जन्म 17 फरवरी 1984 को हुआ था। डी विलियर्स का पूरा नाम अब्राहम बेंजामिन डी विलियर्स है। डीविलियर्स को क्रिकेट की दुनिया का एक शानदार खिलाड़ी माना जाता है। वो अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, हालांकि डीविलियर्स ने सभी को चैंकाते हुए काफी जल्दी ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने 14 साल के करियर में डीविलियर्स ने न जाने कितने रिकॉर्ड बनाए हैं।

14 साल का शानदार करियर

एबी डी विलियर्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 20 साल की उम्र में साल 2004 में टेस्ट से की थी। डीविलियर्स ने अपना पहला मैच 16 दिसंबर 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इस मैच में डीविलियर्स ने बतौर ओपनर शुरुआत की थी, लेकिन अगले ही मैच में उन्हें बैटिंग में नीचे उतार दिया गया। इस मैच में डीविलियर्स ने 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी और साथ में विकेटकीपिंग की भी ज़िम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद डीविलियर्स ने अफ्रीका के लिए कई सालों तक मुख्य विकेट कीपर की भूमिका निभाई। डीविलियर्स के पास टेस्ट में सबसे ज्यादा इनिंग तक शून्य पर न आउट होने का रिकॉर्ड है। अफ्रीका के इस धाकड़ बल्लेबाज ने 114 टेस्ट मैचों में 8,000 से अधिक रन बनाए हैं। जिसमें 22 शतक और 46 अर्धशतक शामिल हैं। डीविलियर्स के नाम अफ्रीका की तरफ से टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने का भी रिकॉर्ड है। डीविलियर्स उन कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं, जिनका टेस्ट में 50 से अधिक का ऐवरेज है। डीविलियर्स एक शानदार बल्लेबाज होने के साथ-साथ एक शानदार कप्तान के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा डीविलियर्स को दुनिया का बेहतरीन क्षेत्ररक्षक माना जाता है।

टेस्ट में अपना डंका बजवाने वाले डीविलियर्स को टेस्ट से ज्यादा एक वनडे खिलाड़ी के रूप में सफलता मिली। डीविलियर्स को दुनिया के एक बेहतरीन वनडे खिलाड़ी के रूप में गिना जाता है। एबी ने एकदिवसीय खेलों में अपना पदार्पण साल 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। एबी को एक अति आक्रामक खिलाड़ी के रूप में गिना जाता है। डीविलियर्स ने अपने करियर में 228 एकदिवसीय मैचों में 53.50 के औसत से 9,577 रन बनाए हैं। जिसमें 25 शतक और 53 अर्धशतक शामिल हैं। डीविलियर्स उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं, जिसका वनडे और टेस्ट दोनों प्रारूपों में 50 से ऊपर का औसत है। डीविलियर्स अपने अनोखे अंदाज से बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। वो विकटों के पीछे एक अनोखे शॉट के लिए जाने जाते हैं। जिसके चलते उन्हें 'मिस्टर 360 डिग्री' भी कहा जाता है। एक समय एबी को विराट कोहली का घोर कंपटीटर माना जाता था, लेकिन डीविलियर्स ने अचानक ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब डीविलियर्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तो नहीं खेलते हैं, लेकिन अलग-अलग देशों में होने वाली क्रिकेट लीग में हिस्सा लेते हैं। एबी आईपीएल में कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूर की तरफ से खेलते हैं।

सबसे तेज अर्धशतक और शतक का रिकॉर्ड

अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले डीविलियर्स के नाम कई रिकॉर्ड हैं। अपने 14 साल के करियर में डीविलियर्स ने क्रिकेट जगत में अपने नाम का झंडा गाड़ा है। डीविलियर्स के नाम वनडे में सबसे तेज अर्धशतक, शतक और 150 रन बनाने का रिकॉर्ड है। एबी ने वनडे इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक महज 16 गेंदों में पूरा किया था। वहीं सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी एबी डीविलियर्स के नाम ही है, जो उन्होंने 31 गेंदों में पूरा किया था, जबकि एकदिवसीय मैचों में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड भी डीविलियर्स के ही पास है, जो एबी ने सिर्फ 64 गेंदों पर बनाए हैं। अपने इस शानदार खेल के प्रदर्शन के दम पर ही डीविलियर्स को करियर में तीन बार आईसीसी का वनडे 'प्लेयर ऑफ द इयर' का अवॉर्ड मिला है। ये अवॉर्ड डीविलियर्स को 2010, 2014 और 2015 में मिला है।

अचानक कहा क्रिकेट को अलविदा

लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे डीविलियर्स ने साल 2018 की शुरुआत में कई टेस्ट मैचों से खुद को अलग कर लिया और संन्यास ले लिया। इसके बाद डीविलियर्स ने एक बार फिर वापसी की। 2018 में डीविलियर्स ने भारत दौरे पर वापसी की, लेकिन उन्होंने कहा कि पीठ में परेशानी की वजह से उन्होंने विकेटकीपिंग करना छोड़ दिया है और कप्तानी से भी खुद को दूर कर लिया। इसके बाद डीविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में अपने करियर का 22वां शतक जमाया और 146 गेंदों पर नाबाद 126 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बाद 23 मई 2018 को सभी को चौंकाते हुए डीविलियर्स ने अचानक ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। डीविलियर्स के इस फैसले से सभी काफी हैरान हुए क्योंकि उनके फैंस को लग रहा था कि डीविलियर्स 2019 में होने वाले विश्व कप में दक्षिण अफ्रीकी टीम के साथ रहेंगे, लेकिन डीविलियर्स ने अचानक ही अपने संन्यास की घोषणा कर दी।

टेक-टॉक

चोरी होने के बाद भी डिलीट कर सकते हैं फोन का डाटा

आजकल देश में अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में चोरी की घटनाएं काफी तेजी से सामने आ रही हैं। जिसमें मोबाइल चोरी के मामले ज्यादा ही बढ़ गए हैं। आमतौर पर जब लोगों का मोबाइल चोरी हो जाता है तो लोग अपने डाटा को लेकर काफी परेशान और चिंतित होते हैं। क्योंकि आजकल लोग अपना अधिकतर डाटा अपने फोन्स में ही सेव रखते हैं। जिसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी शामिल होते हैं। कुछ लोग अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी अपने फोन में ही सेव कर लेते हैं। ऐसे में जब उनका फोन चोरी हो जाता है, तो उन्हें अपने इस डाटा के चोर के हाथ लग जाने की सबसे अधिक फिक्र होती है। इसके अलावा फोन में फोटोज का होना तो स्वाभाविक है। अब फोन में लोगों के फैमिली की भी कई फोटोज होती हैं। इस वजह से भी लोग फोन के चोरी हो जाने पर उन फोटोज के वायरल हो जाने से या चोर के द्वारा उनका गलत इस्तेमाल करने से काफी परेशान और चिंतित रहते हैं। ऐसे में यहां हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन के चोरी होने के बाद अपने डाटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं। जिससे आपको अपने डाटा के किसी के हाथ लगने का कोई डर नहीं रहेगा। हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, जिसको यूज करके आप अपने डाटा को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। आइये जानते हैं आप अपने फोन के डाटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं।

हम आपको बताएंगे कि आपको अपने फोन के डाटा को डिलीट करने के लिए क्या करना है-

- सबसे पहले आप किसी कंप्यूटर या दूसरे फोन पर इंटरनेट ब्राउजर ओपन करें।
- यहां आपको www.google.com/adroid/find टाइप करना होगा।
- अब आपको अपनी उस जीमेल आईडी से लॉगइन करना होगा, जो स्मार्टफोन में भी है।
- आपके सामने प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस और इरेज डिवाइस के तीन ऑप्शन नजर आएंगे।
- इनमें से फोन का डाटा डिलीट करने के लिए आपको इरेज डिवाइस पर क्लिक करना होगा।
- एक बार और क्लिक करने पर आपको जीमेल का पासवर्ड डालना होगा।
- अब अगर आपके फोन में इंटरनेट ऑन होगा तो आप अपना पूरा डाटा डिलीट कर सकते हैं।

भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अमेरिका

रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रहे दोनों देश | हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर जोर

नई दिल्लीः अमेरिका में बाइडेन सरकार आने के बाद भारत-अमेरिका के संबंधों में और भी अधिक प्रगाढ़ता आएगी और इसकी झलक भी अभी से दिखने लगी है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों को लेकर दोनों देशों की चली आ रही नीतियों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठने लगे हैं। भारत को उभरती हुई वैश्विक शक्ति मानते हुए अमेरिका ने बड़ी साझेदारी को लेकर पहल की है। दरअसल, पिछले सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत के खिलाफ चीन की आक्रामक कार्रवाई के मद्देनजर, अमेरिका नई दिल्ली के साथ खड़ा रहेगा। कहा कि हम अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने के चीन के लगातार जारी रवैये से चिंतित हैं। हमेशा की तरह, हम दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे, हम सहयोगियों के साथ खड़े रहेंगे। हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र के मामले में साझा समृद्धि, सुरक्षा और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ खड़े रहेंगे। भारत के प्रति चीन की बढ़ती आक्रामकता पर नए अमेरिकी प्रशासन की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, प्राइस ने कहा कि अमेरिका वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जहां चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है, जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है।

भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का अहम साझेदार

अमेरिकी प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम भारत एवं चीन की सरकारों के बीच जारी वार्ता से अवगत हैं और सीधी वार्ता और उन सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार समर्थन कर रहे हैं। प्राइस ने भारत-अमेरिका के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर जोर दिया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां चीन की ओर से इससे लगते देशों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई देखी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक अहम साझेदार है। हम भारत के विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय और क्षेत्र के एक प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका का स्वागत करते हैं। प्राइस से पूछा गया कि क्या विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने मानवाधिकार के मुद्दों को उठाया है, जिस पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और भारतीय-अमेरिकी प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमिला जयपाल सहित कई डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने चिंता जताई है। इस पर एक सीधी प्रतिक्रिया दिए बिना, प्रवक्ता ने कहा कि मैं यह कह सकता हूं कि यह न केवल भारत के लिए बल्कि हमारे हर साथी पर लागू होता है। हम एक स्वतंत्र और खुले सभ्य समाज एवं कानून के मजबूत शासन सहित लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मिलकर कर रहे काम

भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बात करते हुए अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी के कई आयाम हैं और इसका दायरा काफी विस्तृत है। प्राइस ने आगे कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका भारत का सबसे अहम व्यापारिक साझेदार भी है और साल 2019 में दोनों देशों के बीच 146 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसके अलावा, अमेरिकी कंपनियां भारत में विदेशी निवेश का बड़ा स्रोत भी हैं। प्राइस ने अमेरिका और भारत के लोगों के बीच कायम रिश्ते का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिका में करीब 40 लाख भारतीय अमेरिकी रहते हैं और अपने-अपने में अहम योगदान दे रहे हैं।

पिछले 15 दिनों में दो बार हुई बात

आपको बता दें कि इससे पहले, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत की थी। ये पिछले 15 दिनों में दूसरी बार है जब अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस. जयशंकर से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका की साझेदारी और अपनी साझा चिंताओं पर चर्चा की। म्यांमार में हालात को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। ब्लिंकेन ने म्यांमार में हुए तख्तापलट पर चिंता जाहिर की और कहा कि म्यांमार में कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कायम रहना जरूरी है।

बाइडेन ने की चीन पर पेंटागन टास्क फोर्स बनाने की घोषणा

बीजिंग रणनीति का चार्ट बनाने की तैयारी

न्यूयॉर्कः अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाशिंगटन की बीजिंग रणनीति का चार्ट बनाने के लिए एक पेंटागन टास्क फोर्स की घोषणा की है और अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान कड़ा रुख दिखाते हुए साफ कह दिया कि वह एक खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी। व्हाइट हाउस की ओर से उनकी बातचीत के बारे में जारी बयान के अनुसार, 10 फरवरी को शी के साथ फोन पर वार्ता के दौरान, बाइडेन ने हांगकांग और शिनजियांग में मानवाधिकार और बीजिंग के व्यापारिक रुख संबंधी मुद्दे को भी उठाया।

बीजिंग की बढ़ती शक्ति और आक्रामक रुख के मद्देनजर बाइडेन ने पेंटागन के दौरे के दौरान चीन की चुनौतियों से निपटने और भविष्य की प्रतिस्पर्धा में अमेरिकी लोगों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें शांति बनाए रखने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में और विश्व स्तर पर हमारे हितों की रक्षा के लिए चीन की ओर से बढ़ती चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। पेंटागन में, राष्ट्रपति ने नए टास्क फोर्स के गठन की भी घोषणा की जो रणनीति पर तत्काल प्रभाव से काम करेगा ताकि हम चीन से संबंधित मामलों पर मजबूती से आगे बढ़ सकें। पेंटागन में अपने भाषण में बाइडेन ने कहा कि चीन पर टास्क फोर्स हमारी रणनीति और ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट, प्रौद्योगिकी, फोर्स पॉस्चर और बहुत कुछ देखने को देखेगा। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पेंटागन के भाषण के बाद जारी बयान में कहा कि शी के साथ वार्ता के दौरान, बाइडेन ने अमेरिकी लोगों की सुरक्षा, समृद्धि, स्वास्थ्य की रक्षा करने और स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत को संरक्षित करने की अपनी प्राथमिकताओं पर जोर दिया।

कोरोना और जलवायु परिवर्तन पर भी हुई चर्चा

राष्ट्रपति बाइडेन ने बीजिंग के अनुचित आर्थिक नियम, हांगकांग में कड़ी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई, शिनजियांग में मानवाधिकारों के हनन और ताइवान की ओर क्षेत्र में तेजी से मुखर कार्रवाई के बारे में अपनी बुनियादी चिंताओं को रेखांकित किया। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और हथियारों के प्रसार को रोकने की साझा चुनौतियों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। शी के साथ बाइडेन की फोन पर वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्षेत्र के प्रमुख सहयोगियों-जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ चर्चा के बाद हुई है, जिसके दौरान उन्होंने हिंद-प्रशांत मुद्दों पर चर्चा की थी।

दक्षिण कोरिया में 22 साल बाद चरम पर पहुंची बेरोजगारी दर

सियोलः दक्षिण कोरिया में पिछले साल की तुलना में जनवरी में 9,82,000 रोजगार में गिरावट दर्ज की गई है, जो दिसंबर 1998 के बाद से 22 वर्षों में सबसे अधिक गिरावट है। इसकी जानकारी बुधवार 10 फरवरी को सांख्यिकीय आंकड़ों से मिली। कोरिया के सांख्यिकी के अनुसार जनवरी में रोजगार लोगों की संख्या 2,58,18,000 थी।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी के बीच मार्च 2020 से लगातार 11वीं बार यहां रोजगार दर में गिरावट देखने को मिल रही है। लॉजिंग, इटरिंग और थोक, खुदरा क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या एक साल पहले जनवरी से प्रत्येक में 3,67,000 और 2,18,000 थी। संघ, समाज और अन्य निजी सेवा क्षेत्र में रोजगार पिछले महीने 1,03,000 घट गए, लेकिन परिवहन और भंडारण और सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और सामाजिक कल्याण प्रशासन में क्रमशः 30,000 और 20,000 की बढ़ोत्तरी हुई। जनवरी में बेरोजगारों की संख्या 1,570,000 दर्ज की गई है।

86 देशों में फैल चुका कोरोना का नया वैरिएंट

जनेवाः विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने घोषणा की है कि कोरोना वैरिएंट बी.1.1.7, जिसे पहली बार 20 सितंबर को ब्रिटेन में पाया गया था, वह अब 86 देशों में फैल चुका है। अपने साप्ताहिक महामारी विज्ञान अद्यतन में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वैरिएंट बी.1.1.7 में प्रसार में वृद्धि हुई है और प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर रोग की गंभीरता में वृद्धि के कुछ प्रमाण मिले हैं। 7 फरवरी तक अतिरिक्त 6 देशों ने इस संस्करण के मामलों की सूचना दी है।

डब्ल्यूएचओ ने मंगलवार 9 फरवरी को कहा कि उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन की बात करें तो नया वैरिएंट का सैंपल जांच 14 दिसंबर के सप्ताह में 63 प्रतिशत से बढ़कर 18 जनवरी के सप्ताह में 90 प्रतिशत हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा डब्ल्यूएचओ दो अतिरिक्त कोरोना के प्रकार पर भी निगरानी कर रहा है जो सक्रिय रूप से फैल रहे हैं। इ.1.351 शुरू में दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था और पी.1 स्ट्रेन को पहली बार ब्राजील में पाया गया। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 7 फरवरी तक 44 देशों में इ.1.351 स्ट्रेन के मिलने की पुष्टि हुई है, जबकि 15 देशों में पी.1 स्ट्रेन पाए गए हैं।

चमोली त्रासदी पर चाइना ने जताई अपनी संवेदना

बीजिंगः उत्तराखंड में हुई भयानक त्रासदी पर अब भारत के प्रतिद्वंदी चाइना ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने की घटना से मची तबाही पर चीन ने संवेदना जताई है। चीनी स्टेट काउंसिलर और विदेश मंत्री वांग यी ने 10 फरवरी को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को संवेदना संदेश भेजा।

इसमें उन्होंने हाल में उत्तराखंड में ग्लेशियर गिरने से हुए जान-माल के भारी नुकसान पर दुःख जताया है। उन्होंने ग्लेशियर फटने से आई बाढ़ से प्रभावित लोगों व मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। गौरतलब है कि बीती 6 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से तबाही मच गई थी। जिसमें अभी भी रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है और मलबे में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है।

अजब-गजब

इस गांव में सभी लोग होते हैं बौने

आपने दुनिया के कई तरह के गांव और शहरों के बारे में सुना और देखा होगा। इस दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। बेशक ही आपने बौनों के बारे में भी सुना ही होगा। आम तौर पर बौने लोग काफी कम संख्या में पाए जाते हैं। किसी भी गांव या शहर में आपको एक आध लोग ही ऐसे मिलेंगे, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक पूरा गांव ही बौनों का है, तो क्या आप यकीन करेंगे। एक पूरा गांव जहां जो भी पैदा होता है वो बौना ही होता है। इसीलिए इस गांव को बौनों का गांव कहा जाता है। ये गांव चीन के शिचुआन प्रांत के दूर-दराज पहाड़ी वाले इलाके में स्थित है। बौनों के इस गांव का नाम यांग्सी है। इस गांव को 'ड्वार्फ विलेज ऑफ चाइना' भी कहा जाता है। इस अद्भुत गांव में करीब आधे से ज्यादा लोगों की लंबाई मात्र 2 फीट 1 इंच से लेकर 3 फीट 10 इंच तक ही है। वहीं बौनों के इस गांव में ज्यादातर बच्चों की लंबाई 5 से 7 साल के बाद रुक जाती है। उनकी उम्र तो बढ़ती है, लेकिन उनकी लंबाई बढ़ना रुक जाती है।

दरअसल, यहां ऐसा क्यों है इसके पीछे भी एक कहानी है। यहां के बुजुर्गों का कहना है कई दशक पहले इस गांव को एक खतरनाक बीमारी ने घेर लिया था। सभी लोग इस बात को लेकर आज भी आश्चर्य में ही हैं कि सामान्य कद काठी वाला ये गांव अचानक बौनों के गांव में कैसे तब्दील हो गया। बौनों के इस गांव के बारे में वैज्ञानिकों ने भी कई प्रकार के शोध किए, जिससे वो जान पाएं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। वैज्ञानिकों ने इस गांव की मिट्टी, पानी हवा, वातावरण और अनाज तक हर चीज का अध्ययन भी किया, लेकिन वो इस गांव का रहस्य आज तक नहीं जान पाए। 1911 से इस गांव में सिर्फ बौनों के होने की खबरें सामने आ रही हैं। सन् 1997 में एक रिसर्च में यहां कि

मिट्टी में पारा होने की बात कही गई थी, जिसकी वजह से ऐसा है।

वहीं कुछ लोग यहां बौनों के होने का कारण उन जहरीली गैसों को मानते हैं, जिन्हें जापान ने कई दशकों पहले चीन पर छोड़ा था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि खराब फेंगशुई के चलते ऐसा हो रहा है। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सब अपने पूर्वजों को सही तरीके से दफन नहीं करने की वजह से यह सजा भुगत रहे हैं। फिलहाल वजह जो भी हो लेकिन ये बौनों का अनोखा गांव वाकई अद्भुत है।

सट्टेबाजी के जाल में फंसता देश का भविष्य

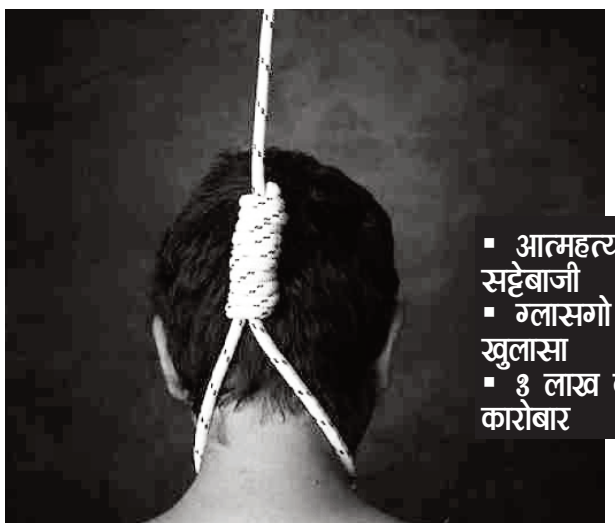

- आत्महत्या के लिए उकसा रही सट्टेबाजी
- ग्लासगो यूनिवर्सिटी के सर्वे से हुआ खुलासा
- 3 लाख करोड़ से ऊपर है सट्टे का कारोबार

आईपीके, लखनऊः देश में आए दिन आत्महत्याओं के मामले सामने आते रहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में साल 2019 में 1.39 लाख लोगों ने आत्महत्या की थी, जो 2018 के आंकड़ों से 4 प्रतिशत अधिक था। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इन आंकड़ो में 67 प्रतिशत लोग 18-45 वर्ष की उम्र के थे। इससे ये साफ है कि देश का भविष्य कहा जाने वाला युवा आत्महत्या ज्यादा कर रहा है। वहीं अभी कुछ दिन पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि भारत आत्महत्या की घटनाओं वाले देशों की सूची में शीर्ष 20 में शामिल है। इस मामले में भारत की स्थिति अपने ही पड़ोसी देशों से काफी बदतर है।

एनसीआरबी ने हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत में लगभग हर 4 मिनट में किसी न किसी ने आत्महत्या की है। ऐसे में देश में आत्महत्या एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जिसकी चपेट में सबसे अधिक देश के युवा आ रहे हैं। वैसे तो आत्महत्या करने के कई कारण हैं। जिसमें 35 प्रतिशत लोग ऐसे थे, जो किसी न किसी कारोबार में लगे थे, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार सट्टेबाजी की वजह से भी कई युवा खुद को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं यानि कि अब सट्टेबाजी आत्महत्या करने का एक प्रमुख कारण बन कर सामने आया है।

आत्महत्या के लिए उकसा रही सट्टेबाजी की लत

आत्महत्या के विभिन्न कारणों के बीच सट्टेबाजी एक डरावने रूप में उभरकर सामने आई है, जिसकी वजह से युवा आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में सट्टेबाजी का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस ओर सबसे अधिक युवा ही आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में सट्टेबाजी के चलते भी लोग खुद को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं और ये जानलेवा कदम उठा रहे हैं। सट्टेबाजी के चलते लोगों को हार-जीत में कई लाखों-करोड़ों का नुकसान होता है, जिसके कारण लोग अपने नुकसानों को लेकर तनाव में रहते हैं जो उनके आत्महत्या का एक कारण बनता है। क्रिकेट, आईपीएल, फुटबाल जैसे कई ऐसे खेल हैं, जिनमें लोग सट्टेबाजी करते हैं। देश में सट्टेबाजी का खेल काफी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में लोग इसके जाल में भी काफी तेजी से फंस रहे हैं।

ग्लासगो यूनिवर्सिटी के सर्वे से हुआ खुलासा

सट्टेबाजी काफी तेजी से पूरे देश में फैल रही है। ऐसे में सट्टेबाजी की वजह से होने वाले आत्महत्या के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन की ग्लासगो यूनिवर्सिटी की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बार-बार नुकसान होने के बावजूद सट्टा लगाने से बाज नहीं आने वाले पुरुषों के आत्महत्या का प्रयास करने की आशंका नौ गुना बढ़ी है। चौंकाने वाली बात ये है कि इस सट्टेबाजी के जाल में सिर्फ पुरूष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी फंसी हैं। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में ये खतरा 4.9 गुना अधिक पाया गया है। शोध करने वाली टीम में शामिल एक शोधकर्ता के मुताबिक, युवाओं में खुदकुशी के खतरे का सट्टेबाजी की लत से सीधा संबंध मिला है। ये सोशल मीडिया या गेमिंग के नशे से कहीं ज्यादा घातक है। ऐसे में सट्टेबाजी को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला करार देते हुए इसकी लत से छुड़वाने के प्रयास और उपाय तेज करने चाहिए। ग्लासगो ही नहीं बल्कि इससे पहले ऑक्सफोर्ड अध्ययन में भी सट्टेबाजी के आदी लोगों के इसकी शुरुआत के 5 साल के भीतर दम तोड़ने की आशंका तीन गुना ज्यादा पाई गई थी। सट्टेबाजी में होने वाले नुकसान के तनाव को मौत की मुख्य वजह बताया गया था।

भारत में इतने करोड़ है सट्टेबाजी का बाजार

सट्टेबाजी का कारोबार पिछले कुछ समय में ही भारत में काफी ज्यादा फैल गया है। अब देश में कई खेलों के ज़रिये सट्टा लगाया जा रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में भारत में सट्टेबाजी का कारोबार 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पर पहुंच चुका है। यह राशि करीब-करीब भारत के रक्षा बजट के बराबर है। वहीं एक अनुमान के मुताबिक अब ये आंकड़ा लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का होगा। हालत ये है कि अकेले दिल्ली में 10 हजार से भी ज्यादा बुकीज हैं। जो एक-एक मैच पर करोड़ों का सट्टा लगाते हैं। भारत में ऑफलाइन के साथ-साथ अब ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में तेजी से बढ़ता सट्टेबाजी का कारोबार युवाओं में आत्महत्या का भी एक प्रमुख कारण बन रहा है।

इन खेलों पर लगता है सट्टा

भारत में सट्टे का सबसे बड़ा कारोबार क्रिकेट में हैं। क्रिकेट मैचों में सबसे ज्यादा सट्टा लगाया जाता है। जबसे आईपीएल की शुरुआत हुई है, तबसे देश में सट्टेबाजारी का खेल कई गुना बढ़ गया है। इसके अलावा फुटबाल और टेनिस में भी यहां सट्टा खेला जाता है। भारत में करीब 15 करोड़ लोग यूरोपीय फुटबॉल लीग को नियमित

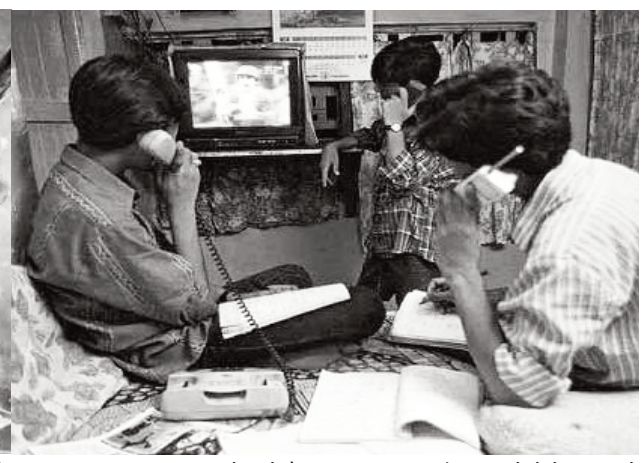

फॉलो करते हैं। ऐसे में इन खेलों में बड़े स्तर पर सट्टे का खेल खेला जाता है।

बीमारियों के मुंह में भी धकेल रही सट्टेबाजी

देश में तेजी से बढ़ रहा सट्टेबाजी का खेल अब युवाओं में एक बीमारी की तरह फैल रहा है। सट्टा भी एक लत है, शराब या अन्य नशों की तरह इसकी भी एक लत होती है, जो आजकल के युवाओं को काफी लग रही है। ऐसे में युवा सट्टे के एडिक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो कई तरह की बीमारियों में भी घिर रहे हैं। इस सट्टे की लत में जब लोगों को लगातार इससे कोई नुकसान होता है, इससे वो काफी परेशान रहने लगते हैं, जिससे वो डिप्रेशन जैसी बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं।

भारत में गैर-कानूनी है सट्टेबाजी

देश में लगातार बढ़ रहा सट्टेबाजी का ये कारोबार भारत में गैर-कानूनी है, फिर भी काफी तेजी से ये काला कारोबार फैल रहा है। आपको बता दें कि भारत में जुआ या सट्टेबाजी 1867 के सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत अपराध भी है। यह अंग्रेजो के शासन में बनाया गया पुराना कानून है। इस 145 साल पुराने कानून के तहत जुआघर चलाना, जुआघर चलाने में मदद करना, जुआ घर जाना चाहे आप खेले या नहीं, जुए में पूंजी लगाना और जुआ उपकरण रखना अपराध है।

क्या कहते हैं मनोचिकित्सक

हमने सट्टेबाजी के अवसाद के रूप में सामने आने और लोगों के आत्महत्या करने को लेकर राजधानी लखनऊ के जाने-माने चिकित्सा संस्थान केजीएमयू के मनोचिकित्सक डॉ. शाश्वत सक्सेना से बात की। डॉ. शाश्वत ने बताया कि हमारे दिमाग में एक सरोटोनिन नाम का एक रसायन होता है। इस रसायन के कम हो जाने से लोगों में अवसाद के लक्षण पाए जाते हैं। ये रसायन हमारे अंदर के तनाव को संतुलित करता है और जब ये तनाव बढ़ जाता है या जो लोग कम खुश रहते हैं उनमें ये रसायन कम हो जाता है, जिससे वो तनाव का शिकार हो जाते हैं। डॉ. सक्सेना ने बताया कि अवसाद के समय में व्यक्ति लगातार उदास रहता है, लेकिन अगर कोई दो हफ्ते से ज्यादा समय तक उदास रहता है, गुमसुम रहता है, तो उसमें अवसाद या डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। वहीं ऐसी स्थिति में इंसान के मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। मनोचिकित्सक डॉ. शाश्वत ने बताया कि सट्टेबाजी की वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार तेजी से हो रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि अक्सर लोग जुआ या सट्टा इसलिए लगाते हैं, जिससे उनको तुरंत ही वो खुशी मिल जाए जिसके लिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसे में ये लोगों की एक लत बन जाता है और जब उन्हें वो खुशी तुरंत नहीं मिलती, मतलब कि अगर वो सट्टे या जुएं में हारने लगते हैं तो ऐसे में लोग तनाव में रहने लगते हैं, नतीजतन वो जल्द ही डिप्रेशन का भी शिकार होने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अक्सर डिप्रेशन में लोगों के दिमाग में नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं, उनको लगने लगता है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लगातार हर समय ऐसे विचार ही दिमाग में आते रहने से लोग सो भी नहीं पाते हैं और वो अपनी ये बातें किसी से शेयर भी नहीं कर पाते, ऐसे में लोगों को लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो आत्महत्या का रास्ता निकालते हैं। उनको लगता है कि जब हम रहेंगे ही नहीं तो हमें किसी भी बात की कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, क्योंकि डिप्रेशन या अवसाद में लोग कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। डॉ. शाश्वत ने बताया कि अवसाद का तीन तरह से इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले डिप्रेशन की दवाई लेकर। जो एंटी डिप्रेशन मेडीसिन आती हैं उनको लेने से दो हफ्ते में डिप्रेशन से राहत मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा काउंसिलिंग भी अवसाद का स्थायी इलाज है। वहीं डिप्रेशन को दूर करने के लिए आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो खुश रहें वो काम करें जो आपके खुशी दे।

डॉ. शाश्वत सक्सेना

पंकज त्रिपाठी : बावर्ची से कालीन भईया तक का सफर

कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कर दिया गया था रिजेक्ट | सशक्त भूमिकाओं से बॉलीवुड में बनाई अलग पहचान

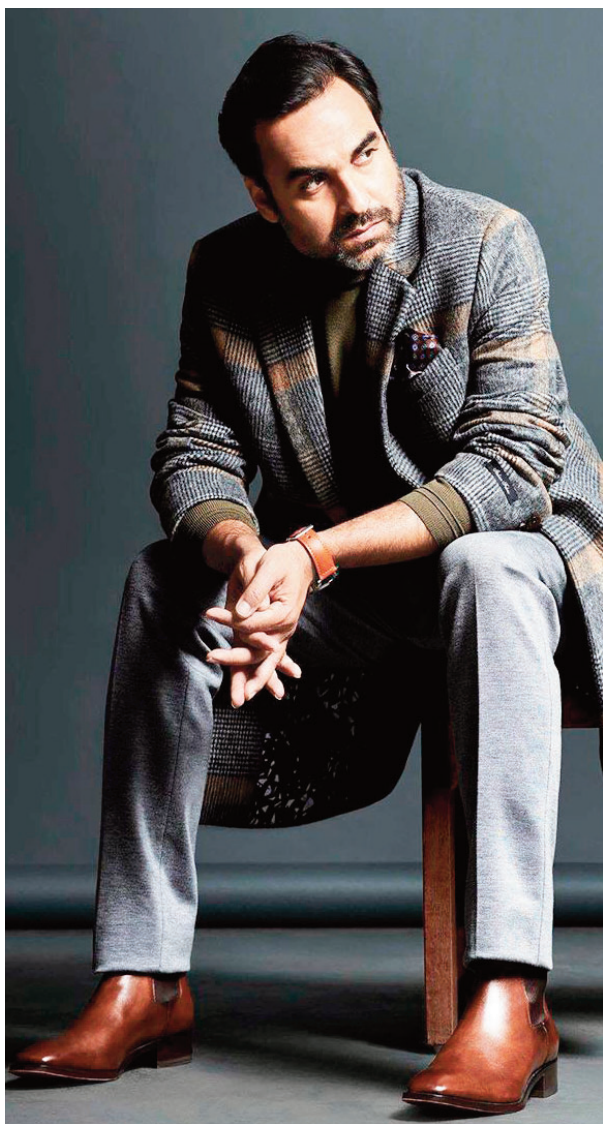

आईपीके, लखनऊः कालीन भईया से तो आज हर कोई भली-भांति परिचित होगा। अमेजन प्राइम की सुपरहिट वेब सीरीज मिर्जापुर में अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भईया का किरदार निभाने वाले पंकज त्रिपाठी को आज भला कौन नहीं जानता है। आने वाली हर दूसरी फिल्म में आप किसी न किसी किरदार में पंकज को देख ही लेंगे।

अब पंकज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पंकज के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। वह फिल्म में किसी मामूली या छोटे रोल में नज़र नहीं आते, बल्कि उनका फिल्म में अहम किरदार होता है। मिर्जापुर और कागज जैसी फिल्मों व वेब सीरीज में तो पंकज त्रिपाठी मुख्य किरदार में नज़र आए हैं, लेकिन आज हर फिल्म में नज़र आने वाले पंकज त्रिपाठी कभी रोल मांगने जब जाते थे तो उन्हें ऑफिस का गॉर्ड ही धक्के मार कर निकाल देता था। पंकज ने काफी संघर्ष के बाद ये मुकाम हासिल किया है। आईये जानते हैं पंकज के जीवन के कुछ अनसुने किस्से और उनके संघर्ष की कहानी।

बावर्ची से एनएसडी तक का सफर

पंकज त्रिपाठी का जन्म बिहार के गोपालगंज में बेलसंद के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ था। पंकज का बचपन काफी संघर्ष भरा रहा है। उनके गांव में बिजली नहीं आती थी और वो स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ाई किया करते थे। पंकज के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन पंकज का मन शुरू से ही अभिनय में लगता था। आज बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम हीरो में गिने जाने वाले पंकज कहते हैं कि 10वीं कक्षा तक उन्होंने कभी सिनेमाघर तक नहीं देखा था। पंकज बचपन में अपने गांव में होने वाले नाटकों में अक्सर लड़की का किरदार करते थे। 12वीं के बाद पंकज ने अपने मित्रों के कहने पर होटल मैनजमेंट के एक छोटे से कोर्स में एडमिशन ले लिया। जिसके बाद उन्होंने मौर्य होटल पटना में एक बावर्ची के रूप में काम किया। पंकज बताते हैं कि लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा रचित प्रोसेनियम थिएटर "अंधा कुआं" को देखने के बाद वह बेहद प्रभावित हुए, यह शो देखने के बाद वह बहुत रोए थे। इसको देखने के बाद ही पंकज की दिलचस्पी अभिनय में और अधिक हो गई। जिसके बाद पंकज पटना में कालीदास रंगालय से जुड़ गए और उसके बाद बिहार आर्ट थिएटर से 2 साल तक जुड़े रहे। इस दौरान वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) के लिए भी कोशिश करते रहे। वर्ष 1995 में उन्हें पहली बार भीष्म साहनी की कहानी पर आधारित नाटक "लीला नंदलाल" में देखा गया, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया, लेकिन पंकज को दो बार एनएसडी से रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद साल 2001 वो साल था जब पंकज को एक बहुत बड़ी खुशी मिली। उनके लिए एनएसडी से चिट्ठी आई और उनका चयन एनएसडी के लिए हो गया।

मुंबई में किया संघर्ष

2001 में एनएसडी में चयन होना पंकज के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था, क्योंकि यहां पंकज को वो लोग मिले जिनसे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। यहां उनके सीनियर थे दिग्गज अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 2001 से 2004 तक पंकज ने एनएसडी में अध्ययन किया। इसके बाद साल 2004 में एनएसडी पूरा करने के बाद पंकज सपनों की नगरी मुंबई में आ गए। अपनी पत्नी के साथ पंकज मुंबई आ तो गए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि बिना पैसों के वो कहां रहेंगे और क्या करेंगे ? यहां से पंकज के जीवन का असली संघर्ष शुरू हुआ। पंकज बताते हैं कि यहां आने के बाद उन्होंने स्टूडियो के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। पंकज जहां भी जाते वहां उनसे कोई न कोई रिफरेंस मांगा जाता, लेकिन पंकज के पास न कोई रिफरेंस था और न ही किसी से कोई पहचान। ऐसे में पंकज जिसके भी पास जाते वो उन्हें रिजेक्ट ही कर देता। पंकज बताते हैं कि जहां भी जाता था वो 'नॉट फिट' बोल देता था। उसके बाद उन्हें छोटे-मोटे विज्ञापन में काम मिलने लगा और उनकी रोजी-रोटी चलने लगी। वहीं उनकी पत्नी मृदुला जो कि बीएड पास थीं वो भी एक स्कूल में पढ़ाने लगीं और इस तरह से उनका घर तो चलने लगा, लेकिन अभी भी पंकज को वैसे काम की तलाश थी, जिसका सपना लेकर वो मुंबई आए थे।

गैंग्स ऑफ वासेपुर से मिली पहचान

कई ऐड और सीरियल्स में छोटे-मोटे काम करने के बाद पंकज त्रिपाठी की किसी फिल्म में पहली उपस्थिति 2004 में आई अभिषेक बच्चन की फिल्म 'रन' में थी। इस फिल्म में उन्होंने एक चोर की भूमिका निभाई थी। ये रोल काफी छोटा था। इसके अलावा

और भी कई फिल्मों में पंकज ने छोटे-मोटे रोल किए। पंकज के रोल को कोई गौर करे या न करे लेकिन पंकज अपने इन कुछ मिनटों के किरदारों में भी अपनी पूरी जान लगा देते थे और अपना सौ प्रतिशत देते थे।

पंकज ने अपहरण, ओमकारा, शौर्य, रावण और आक्रोश जैसी कई फिल्मों में छोटे मगर असरदार किरदार निभाए, लेकिन पंकज को असली पहचान और नाम मिला 2012 में आई अनुराग कश्यप की बॉलीवुड की आईकॉनिक फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से। गुलाल नाटक की शूटिंग के दौरान कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने उन्हें "गैंग्स ऑफ़ वासेपुर" के ऑडिशन के लिए बुलाया था। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पीयुष मिश्रा, रिचा चड्ढा जैसे तमाम बड़े सितारे थे। पंकज बताते हैं कि इस फिल्म के लिए उन्होंने 8 घंटे तक ऑडिशन दिया। दरअसल, शुरू में अनुराग कश्यप को पंकज का ऑडिशन पसंद ही नहीं आया, लेकिन बाद में पंकज के हाथ सुल्तान का किरदार लग ही गया और पंकज इस यादगार फिल्म का एक अहम हिस्सा बन गए। इस फिल्म से पंकज को नाम, काम और शोहरत तीनों मिलीं। हालांकि 2012 तक पंकज को मुंबई आए 8 साल हो चुके थे। इस 8 साल की घोर तपस्या और संयम के बाद पंकज को वो एक पहचान मिल पाई। इस फिल्म के बाद पंकज को कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आए, जिनमें मसान, फुकरे, दबंग 2, मांझी-द माउंटेन और ऐसी कई फिल्में शामिल हैं। आज पंकज के खाते में बरेली की बर्फी, स्त्री, अंग्रेजी मीडियम, ताशकंद फाइल, सुपर-30 जैसी कई बड़ी फिल्में हैं। वहीं अब वो गुंजन सक्सेना, मीर्जापुर सीजन 1 और 2, गुड़गांव और कागज जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका में नज़र आ चुके हैं। आज पंकज बॉलीवुड के सबसे बिजी ऐक्टर्स में से एक हैं।

मनोज वाजपेयी को मानते हैं आइडियल

पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बिहार से ही आने वाले मनोज वाजपेयी को अपना आईडियल मानते हैं। पंकज ने एक इंटरव्यू में बताया कि मनोज सर को देखकर ही मुझ में इतनी ताकत और विश्वास आया कि मैं भी फिल्म लाइन में आ सकता है। पंकज बताते हैं कि मनोज भईया ने हम जैसों के लिए नया रास्ता खोला। मैं सोचता था कि मनोज अगर वहां से आकर स्टार बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ? एक नया रास्ता खोला था उन्होंने, जो मेरे और मेरे जैसे अनगिनत के लिए नई दुनिया थी। मनोज वाजपेयी से जुड़ा एक किस्सा पंकज ने शेयर किया। उन्होंने बताया एक बार मनोज वाजपेयी जी मौर्या होटल में ठहरने आये थे। उस समय मैं वहां काम करता था। जब वे होटल छोड़ कर जा रहे थे तो गलती से उनकी चप्पल वहां छूट गयी। हाउस कीपिंग का एक लड़का था उसने फोन कर के पंकज को बताया कि मनोज वाजपेयी जी आए थे उनकी चप्पल छूट गई है। तो मैंने कहा कि यार मुझे दे दो मैं कम से कम उसमें पैर तो डाल सकूंगा। पहले जैसे गुरुओं का खड़ाऊ चेले रखते थे, वैसे ही मैंने उसे रख लिया। जब वासेपुर में उनसे मिला तो मैंने उनसे ये बात बताई थी।

रिक्शा चालक की बेटी बनी फेमिना मिस इंडिया 2020

आईपीके, लखनऊः तेलंगाना की 23 वर्षीय फाइनेंशियल एक्सचेंज इनफॉर्मेशन एनालिस्ट मानसा वाराणसी वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत कर मिस इंडिया बन गई हैं। इस बात की घोषणा फेमिना मिस इंडिया ने अपने ऑफीशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से की।

10 फरवरी को आयोजित हुए फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रांड फिनाले में तेलंगाना की ब्यूटी मानसा वाराणसी ने जहां खिताब पर कब्जा जमाया, तो वहीं मान्या सिंह और मनिका शियोकांड फर्स्ट व सेकेंड रनर अप रहीं। मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने वाली मानसा का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा है। आज तो वो बेशक भारत की सबसे खूबसूरत महिला बनी हैं, लेकिन उनके यहां तक पहुंचने की कहानी काफी संघर्ष भरी है।

पिता चलाते हैं रिक्शा

आज मिस इंडिया के खिताब पर कब्जा करने वाली मानसा एक अत्यंत गरीब परिवार से आती हैं। मानसा के पिता एक रिक्शा चालक हैं। मानसा ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है और काफी कुछ झेला है, लेकिन वो कहते हैं न कि सब्र का फल मीठा होता है। वो ही मानसा के साथ भी हुआ। मानसा ने काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना किया है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने बिना कुछ खाए ही कई रातें गुजारी हैं। अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताते हुए मानसा कहती हैं कि मेरा खून, पसीना और आंसू मेरी आत्मा के लिए खाना बने और मैंने सपने देखने की हिम्मत जुटाई। मैंने कम उम्र में ही नौकरी करना शुरू कर दिया था। मानसा ने बताया कि मेरे पास जो भी कपड़े थे वो दूसरों के दिए हुए ही थे। मानसा ने कहा कि मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पास किताबें नहीं थीं। बाद में मेरे मां-बाप ने मुझे पढ़ाने के लिए जो भी जेवर उनके पास थे उन्हें भी बेच दिया और मुझे पढ़ाया।

14 साल में छोड़ा घर

मानसा ने अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताते हुए कहा कि 14 साल की उम्र में मैं सबकुछ छोड़ कर घर से भाग गई थी। ऐसे में मैं दिन में किसी तरह से पढ़ाई करती थी तो वहीं शाम को लोगों के घर बर्तन धोने का काम करती थी, वहीं रात में फिर कॉल सेंटर में काम करती थी। मानसा ने बताया कि रिक्शे के पैसे बचाने के लिए मैं काफी दूर और कई घंटों पैदल चली हूं। मानसा ने कहा कि मैने अपने घर की स्थिति को ठीक करने के लिए काफी कुछ किया और उसी का नतीजा है कि मैं आज यहां हूं। मानसा ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि दुनिया को दिखाने के लिए आप एक बार ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। मानसा ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी मुश्किल आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है।

ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई भारतीय फिल्म 'बिट्टू'

LIVE ACTION SHORT FILM

Ten films will advance in the Live Action Short Film category for the 93rd Academy Awards. One hundred seventy-four films qualified in the category. Members of the Short Films and Feature Animation Branch vote to determine the shortlist and the nominees.

The films, listed in alphabetical order by title, are:

"Bittu"
"Da Yie"
"Feeling Through"
"The Human Voice"
"The Kicksled Choir"
"The Letter Room"
"The Present"
"Two Distant Strangers"
"The Van"
"White Eye"

लॉस एंजेलिसः बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारतीय फिल्म 'जल्लीकट्टू' के जगह बनाने में नाकामयाब होने के बाद भी आशा की किरण बाकी है। भारत के पास अब भी 93वें अकादमी पुरस्कार में चमकने का एक मौका है क्योंकि लाइव एक्शन फिल्म कैटेगरी में भारत की फिल्म 'बिट्टू' शॉर्टलिस्ट हो गई है। करिश्मा देव दुबे की फिल्म 'बिट्टू' 10-फिल्मों की सूची का हिस्सा है। इस फिल्म को एकता कपूर, गुनीत मोंगा और ताहिरा कश्यप ने इंडियन वूमन राइजिंग इनीशिएटिव के तहत प्रजेंट किया है।

यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है और स्कूल के 2 दोस्तों की कहानी बताती है। इस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुईं अन्य फिल्मों में - दा यि, फीलिंग थ्रू, द ह्यूमन वॉयस, द किक्सल्ड क्वायर, द लेटर रूम, द प्रेजेंट, टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स और द वैन एंड व्हाइट आई। इसे लेकर गुनीत ने लिखा कि 93वें अकादमी पुरस्कारों के लिए बिट्टू शॉर्टलिस्ट हो गई है। फिल्म और अद्भुत टीम की बहुत आभारी हूं। वहीं एकता ने लिखा कि यह बहुत ही रोमांचक खबर है, हम महिलाओं के लिए जो इस पर काम कर रही हैं। पूरी टीम को बधाई। ऑस्कर के लिए अंतिम नामांकन 15 मार्च को घोषित किए जाएंगे। वहीं प्राइज सेरेमनी 25 अप्रैल को होगी।

ऑनलाइन दुनिया बच्चों को सीखने का देती है मौकाः आयुष्मान

मुंबईः यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना ने 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के मौके पर बच्चों की इंटरनेट शिक्षा को लेकर बात की। वे 'एंडिंग वॉयलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन' नाम से चलाए जा रहे वैश्विक अभियान का हिस्सा हैं।

आयुष्मान ने कहा कि ऑनलाइन दुनिया बच्चों को सीखने और उनके विचारों को साझा करने का बड़ा मौका देती है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस के मौके पर बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वे इंटरनेट एक्सप्लोर कर सकें और अपने अच्छे भविष्य के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं और सपनों को पूरा कर सकें। इंटरनेट, बच्चों के दिमाग की तरह विचारों और कल्पना से भरा हुआ है। आयुष्मान ने आगे कहा कि इसके खतरे भी हैं, लेकिन शिक्षा के जरिए हम बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहने के लिए सशक्त बना सकते हैं। इस सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर ऑनलाइन हिंसा को खत्म करने और हर बच्चे के लिए ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए काम करते हैं।

हां, मैं नाइटी क्वीन हूंः अर्शी खान

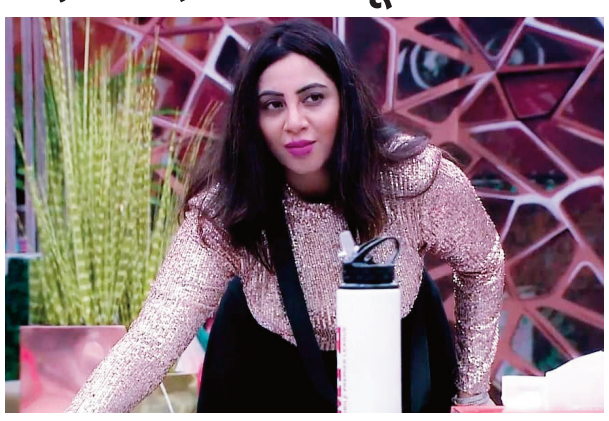

नई दिल्लीः बिग बॉस 14 से निकाली गई प्रतियोगी अर्शी खान अपने अजीब ड्रेसिंग सेंस को लेकर इस सीजन में आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। वह ज्यादातर समय घर में नाइटवियर पहने हुए दिखाई देती थीं। इतना ही नहीं उनके इस ड्रेसिंग सेंस के कारण यदि उन्हें नाइटी क्वीन नाम दिया जाए तो वह परवाह नहीं करेंगी। उनके ऐसे ड्रेस और स्मोकी आई मेकअप के कारण कई तरह की बातें भी हुईं लेकिन अर्शी इन चीजों को लेकर परेशान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल, मैं अपनी नाइटीज में बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूं।

इतना ही नहीं वह सलमान खान के साथ 'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान भी ऐसी ही ड्रेस पहनना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि मैं वीकेंड का वार एपिसोड में एक बार नाइट वियर ही पहनना चाहती थी, लेकिन राहुल वैद्य और एली गोनी ने मुझे रोक दिया। मैं बस उनमें सहज महसूस करती हूं। हां, मैं नाइटी क्वीन हूं और मैं इसे प्यार करती हूं। अर्शी अब बिग बॉस के घर से बाहर हो चुकी हैं और फिलहाल गोवा में छुट्टियां मना रही हैं लेकिन वे खुद को घर से बाहर निकाले जाने के कारण परेशान हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूं। मैं सदमे में हूं और मुझे अजीब लग रहा है। निश्चित रूप से मैं परेशान हूं। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने बहुत कोशिश की थी।

लाइफस्टाइल फंडा

कई मायनों में गुणकारी है सरसों का तेल

शरीर के दर्द को कर देता है छूमंतर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कम करने में है कारगर

आईपीके, लखनऊः सरसों का तेल हर भारतीय घर में बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। सरसों के तेल का प्रयोग लगभग रोज ही किसी न किसी घर में किया ही जाता है। आम तौर पर इसका प्रयोग घरों में खाना पकाने में या किसी पकवान को तलने के लिए किया जाता है, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि सरसों का तेल खाना पकाने के अलावा भी और कई मायनों में काभी लाभदायक है। सरसों का तेल हमारी स्किन और बालों की सुरक्षा के लिए बहुत लाभकारी है। सरसों के तेल का प्रयोग हम मॉश्चराइजर के रूप में भी कर सकते हैं। आइये जानते हैं सरसों के तेल के और क्या-क्या फायदे हैं।

दर्द रोकने में सहायक

सरसों का तेल मोटा होता है और इसकी गंध काफी तीखी होती है। सरसों के तेल का स्वाद भी काफी मजबूत होता है और खाने में अच्छा लगता है। जिसकी वजह से कई भारतीय घरों में इसका प्रयोग खाना पकाने में किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी काई मायनों में फायदेमंद ये तेल पिग्मेंट यानी एलिल आइसोथियोसाइनेट में भरपूर होता है, जो शरीर के दर्द में काफी कारगर साबित होता है। इसके अलावा सरसों का तेल अल्फा-लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा-3 फैटी एसिड में भी भरपूर होता है, जिससे किसी भी प्रकार के गंभीर तेज दर्द में काफी राहत मिलती है। इसके साथ सरसों का तेल गठिया जैसी बीमारियों के भयंकर दर्द में भी काफी कारगर साबित होता है। कई मायनों में गुणकारी सरसों का तेल बैक्टीरिया को रोकने में भी काफी सहायक है। ये बैक्टीरिया के एक खास प्रकार का विकास रोक सकता है और आगे किसी भी संक्रमण को रोकने में सहायक होता है। इसलिए शरीर में लगाने के लिए भी सरसों के तेल का प्रयोग किया जा सकता है, जो काफी लाभदायक होता है। सरसो का तेल बैक्टीरिया के प्रभावों को निष्क्रिय करने के तौर पर जाना जाता है और शरीर में उसकी वृद्धि को रोकने में भी मदद करता है।

कैंसर और दिल की सेहत में है काफी सहायक

कई मायनों में गुणकारी सरसों का तेल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी काफी सहायक है। चूंकि कैंसर की कोशिकाएं

सामान्य कोशिकाओं के मुकाबले तेजी से बढ़ने के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में ये तेल शरीर में कैंसर की कोशिकाओं के विकास को धीमा करने में काफी सहायक है। कई वैज्ञानिक अनुसंधान और रिसर्च में पाया गया है कि सरसों का तेल शरीर में कैंसर की कोशिकाओं के विकास को धीमा भी कर सकता है और इस तरह किसी गंभीर स्थिति को रोक सकता है। आजकल लोगों का ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल सामान्य से बढ़ जाता है और बदली जीवनशैली के कारण दिल की बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में सरसों का तेल दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। वनस्पति का तेल मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरा होता है। उसके चलते ये तेल ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कम करने और दिल की सेहत में मददगार होता है।

किशमिश के हैं कई फायदे, दिनचर्या में जरूर करें शामिल

खून की कमी को पूरा करने में है काफी सहायक, बच्चों के शारीरिक-मानसिक विकास के लिए है वरदान

आईपीके, लखनऊः किशमिश मेवों में काफी महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो हर किसी के घर में किशमिश आसानी से मिल जाती है और यह अधिकतर लोगों को पसंद भी होती है। किशमिश का इस्तेमाल हम किसी भी पकवान की खूबसूरती और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। हम अक्सर, खीर, सेवइयां और अन्य मिष्ठानों में किशमिश का प्रयोग सजावट के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किशमिश के इसके अलावा भी बहुत ही फायदे हैं। किशमिश को रात भर भिगाकर सुबह के समय खाने से इसकी गुणवत्ता में और बढ़ोत्तरी हो जाती है, क्योंकि रात भर किशमिश को भिगोने से इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। आइये जानते हैं किशमिश के कुछ फायदे।

खून की कमी को पूरा करती है किशमिश

किशमिश के सेवन के अनेकों फायदे होते हैं। इसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम और पोटैशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह शारीरिक और

मानसिक विकास में मदद करता है। इसके अलावा किशमिश में काफी उच्च मात्रा में फाइबर भी होता है। इसके साथ ही किशमिश खून की कमी को पूरा करने में काफी सहायक है। किशमिश में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो खून की कमी को पूरा करता है। अगर किसी के शरीर में खून की कमी है तो उसे रोजाना एक मुट्ठी किशमिश जरूर खाना चाहिए। किशमिश में पाए जाने वाले तत्व एंटी-माइक्रोबियल और एंटीबैक्टीरियल से बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किशमिश के गुण दांतों के अंदर पैदा होने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म करने में मददगार साबित होते हैं। वहीं अगर आप अपने दुबलेपन से परेशान हैं तो फिर आपको किशमिश का सेवन अवश्य करना चाहिए। किशमिश फ्रुक्टोज से भरपूर होती है, जो शरीर का वजन बढ़ाने में मदद कर सकती है।

बच्चों के शारीरिक-मानसिक विकास में काफी सहायक

अक्सर लोग अपने बालों के झड़ने से काफी परेशान रहते हैं। बाल झड़ने की समस्या महिलाओं व पुरुषों दोनों में पाई जाती है। ऐसे में किशमिश के प्रतिदिन सेवन से बालों की सेहत में भी सुधार होता है और बालों के झड़ने की समस्या से निजात मिलता है। वहीं किशमिश में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पायी जाती है, इसलिए इसके सेवन से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। बच्चों को खास तौर से किशमिश जरूर खाने के लिए देना चाहिए। किशमिश के सेवन से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छी तरह से होता है और बच्चों की याद्दाश्त भी मजबूत होती है। किशमिश कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी शरीर की रक्षा करती है। कई शोध में इस बात की पुष्टि भी हुई है। कब्ज, एसिडिटी और थकान से परेशान लोगों को भी किशमिश को सेवन जरूर करना चाहिए। किशमिश के रोजाना सेवन से इन समस्याओं से जल्द ही आराम मिल जाता है। उच्च रक्तचाप की समस्या में भी किशमिश एक औषधि की तरह काम करता है। किशमिश के पानी को पीने से उच्च रक्तचाप की समस्या में भी आराम मिलता है।